

भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 312]
No. 312]नई दिल्ली, बुधवार, जून 20, 2001/ज्येष्ठ 30, 1923
NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 20, 2001/JYALSTHA 30, 1923

महानिदेशक (रक्षोपाय) का कार्यालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 मई, 2001

विषय: सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के नियम 18 के अधीन भारत में फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का पुनरीक्षण—अंतिम निष्कर्ष।

सा. का. नि. 441(अ).—सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली, 1997 के अधीन।

क प्रस्तावना

रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 6 के अधीन भारत में फिनाल के आयात के संबंध में जाँच शुरू करने का नोटिस दिनांक 2.2.99 को जारी किया गया था। फिनाल के वर्धित आयात से गंभीर क्षति की आशंका से घरेलू उद्योग को बचाने के लिए फिनाल के आयात पर न्यूनतम आवश्यक समझी गई प्रथम वर्ष के दौरान यथामूल्य 22% और दूसरे वर्ष के दौरान यथामूल्य 15% की दर से रक्षोपाय शुल्क लगाने की संस्तुति करने संबंधी अंतिम निष्कर्ष कथित नियमावली के नियम 11(1) के अधीन (भारत के राजपत्र (असाधारण) भाग-II, खण्ड -III उपखण्ड (1) में प्रकाशित) दिनांक 11.6.99 को जारी किये गये थे। रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 12 और 14 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 (1975 का 51) की धारा 8 बी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महा-निदेशक (रक्षोपाय) के अंतिम निष्कर्षों के आधार पर भारत सरकार ने दिनांक 30.6.1999 की अधिसूचना सं० 82/99- सीमा शुल्क के द्वारा कथित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की प्रथम अनुसूची के उप शीर्ष सं० 290711 के अधीन आने वाले फिनाल पर, जब कभी भी यह भारत में आयातित हो, निम्न दरों पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया है:-

- (क) 29 फरवरी, 2000 तक के आयात पर 22% और
 (ख) 1 मार्च, 2000 से 29 जून, 2001 तक (दोनों दिन शामिल) के बीच आयात होने पर 15%।

ख प्रक्रिया

यह विचार करने के लिए कि गंभीर क्षति को रोकने के लिए भारत में फिनाल के आयातों पर क्या रक्षोपाय शुल्क जारी रहना चाहिए के विषय में पुनरीक्षण का नोटिस 1.1.2001 को जारी किया गया था और वह दिनांक 08.01.2001 को भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था। नोटिस की एक प्रति सभी ज्ञात पक्षों को प्रेषित की गई थी, यथा -

घरेलू उत्पादकगण

- (i) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि० मुम्बई (एच०ओ०सी० एल) मुम्बई
- (ii) हर्डीलिया केमिकल्स लिमिटेड (एच सी एल), मुम्बई
- (iii) नैवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन, तमिलनाडु

आयातकगण/प्रयोगकर्ता उद्योग

- (1) सी०जे०शाह एण्ड कम्पनी, मुम्बई
- (2) हरेश कुमार एण्ड कम्पनी, मुम्बई
- (3) पी०सी०एल इण्डस्ट्रीज, नई दिल्ली
- (4) कांती लाल मणिलाल एण्ड कम्पनी, मुम्बई
- (5) विनमार इंटरनेशनल इंडिया प्राइवेट लि०, मुम्बई
- (6) सोनकमल एण्टरप्राइजिज, मुम्बई
- (7) खेतान ब्रदर्स, मुम्बई
- (8) शुभम डाइज एण्ड केमिकल्स लि०, दिल्ली
- (9) एक्सप्रो इण्डिया, मुम्बई
- (10) केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि०, मुम्बई
- (11) बेकेलाइट हाथलम लि०, हैदराबाद
- (12) ग्रीनप्लाइ एण्डस्ट्रीज लि०, जिला रत्नागिरि, महाराष्ट्र
- (13) गार्गी हट्टन्स अलबर्ट्स प्राइवेट लि०, मुम्बई
- (14) अल्टा लेबोरेट्रीज लि० दादर, मुम्बई
- (15) युनाइटेड फास्फोरस लि०, मुम्बई
- (16) कलर केम लि० बाल्कम, थाणे
- (17) किटप्लाइ इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता
- (18) रोमित रेजिन्स प्राइवेट लि०, पनवेल
- (19) बिलाग इण्डस्ट्रीज, वापी
- (20) युनाइटेड मैटाकेम, पुणे
- (21) मार्वल थर्मोसेट्स प्राइवेट लि०, मुम्बई
- (22) हेल्म इण्डिया प्राइवेट लि०, मुम्बई

निर्यातकगण

- (1) फेनालकेमी जी एम बी एच, जर्मनी
- (2) एनीकेम, इटली
- (3) जार्जिया गल्फ कार्पोरेशन, यू०एस०ए०
- (4) मित्सुई केमिकल्स, टोकियो
- (5) कुम्हो केमिकल्स कम्पनी, सियोल, कोरिया
- (6) ताइवान प्रास्पैरिटी केमिकल कम्पनी, ताइवान
- (7) मेरिसोल, साऊथ अफ्रीका (मेरीकेम ससोल)
- (8) कोलमार पेट्रोकेमिकल्स ए जी स्विटजरलैण्ड
- (9) आई सी सी केमिकल्स कार्पोरेशन, न्यूयार्क
- (10) तोसोह कार्पोरेशन, टोकियो
- (11) फार्मोसा प्लास्टिकस कार्पोरेशन, ताइवान
- (12) द्राइकान एनर्जी लि०, यू०एस०ए०

विदेशी संगठन

- (1) केमिकल सेफ्टी मैनेजमेंट सेण्टर, जापान केमिकल इण्डस्ट्री एसोसिएशन-
जे सी आई ए टोकियो-100, जापान
- (2) केमिकल एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीज एसोसिएशन -(सी ए आई ए)
आकलैण्ड पार्क 2006, दक्षिण अफ्रीका ।
- (3) कोरियन पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्री एसोसिएशन -
(के०पी०आई०ए०) चोंगों - कू० सियोल, कोरिया ।
- (4) पेट्रोकेमिकल इण्डस्ट्री एसोसिएशन आफ ताइवान
(पी०आई०ए०टी०) सैक्शन - 4 चुटुंग हसिंचु, ताइवान
- (5) केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन (सी०एम०ए०)
वर्जीनिया - 22209 यू०एस०ए०
- (6) वरबैंड - डेर केमिस्केन इण्डस्ट्री - वी सी एल जर्मनी ।

भारतीय संगठन

- (1) सोसाइटी आफ थर्मोसेटिंग इण्डस्ट्रीज, मुम्बई ।
- (2) इंडियन लैमिनेट्स मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई ।
- (3) इंडियन केमिकल मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई ।

2. प्रार्थना पत्र और प्रश्नावली के साथ नोटिस की एक प्रति निर्यातक देशों को दिल्ली स्थित उनके उच्चायोग/राजदूतावासों जैसे बेल्जियम, चीनी ताइपेई, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया डी पी आर, कोरिया आर पी, नीदरलैण्ड, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, यू०के०, यू०एस०ए० और यूरोपियन यूनियन, भारत में यूरोपियन आयोग के प्रतिनिधिमण्डल, नई दिल्ली के माध्यम से प्रेषित की गई थी।

3. उसी दिन प्रश्नावलियाँ सभी ज्ञात घरेलू उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को भी प्रेषित की गई थी जिनको 09.02.2001 तक अपना प्रत्युत्तर प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।

4. निम्नलिखित पक्षों द्वारा अपना उत्तर प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाने हेतु अनुरोध किया गया था:-

- (1) केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि०, मुम्बई।
- (2) अल्टा लेबोरेट्रीज लि० दादर, मुम्बई।
- (3) किटप्लाई इंडस्ट्रीज, कलकत्ता।
- (4) रोमित रेजिन्स प्राइवेट लि०, पनवेल।
- (5) मार्बल थर्मोसेट्स प्रा० लि०, मुम्बई।
- (6) दुजोदवाला रेजिन्स एण्ड टरपिन्स लि०, मुम्बई।
- (7) इंस्टीट्यूट आफ इंडियन फाउंडरीमैन, कलकत्ता।
- (8) आल इण्डिया असोसिएशन आफ इंडट्रिस, मुम्बई।

समय बढ़ाने का अनुरोध क्योंकि बिना किसी औचित्य के किया गया था इसीलिए समय बढ़ाने की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया और तदनुसार सभी संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया गया था।

5. 01.01.2001 के नोटिस और प्रश्नावली के प्रत्युत्तर निम्नलिखित पक्षों से प्राप्त हुए थे:-

घरेलू उत्पादकगण

- (1) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लि० मुम्बई।
- (2) हर्डीलिया केमिकल्स लि०, मुम्बई।
- (3) नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लि० नेवेली

आयातकगण/प्रयोगकर्ता उद्योग

- (1) केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि०, मुम्बई
- (2) अल्टा लेबोरेट्रीज लि० दादर, मुम्बई
- (3) किटप्लाई इण्डस्ट्रीज, कलकत्ता
- (4) मार्बल थर्मोसेट्स प्रा० लि०, मुम्बई
- (5) एक्सप्रो इण्डिया लि०, मुम्बई
- (6) युनाइटेड मैटाकेम प्रा० लि०, पुणे

- (7) दौराला आर्गेनिक्स लि० , नई दिल्ली ।
- (8) कलर केम लिमिटेड, थाणे ।
- (9) शिनेक्टेडी स्पेशलिटीज एशिया लि०, मुम्बई ।
- (10) गार्गी हटन्स- आलबर्टस, मुम्बई
- (11) फोसेको इण्डिया लिमिटेड, पुणे
- (12) सैन्चुरी लेमिनेटिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता ।

निर्यातकगण

- (1) फिनालकेमि , जर्मनी
- (2) आई सी सी केमिकल कार्पोरेशन, यू०एस०ए०
- (3) मित्सुई केमिकल्स टोकियो, जापान

भारतीय संगठन

- (1) सोसाइटी आफ थर्मोसेटिंग इण्डस्ट्रीज, मुम्बई ।
- (2) अखिल भारतीय उद्योग संघ, मुम्बई
- (3) इंडियन केमिकल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन, मुम्बई ।

6. जांच के लिए आवश्यक समझी गई सूचना का सत्यापन किया गया और इसके लिए लागत लेखा विशेषज्ञों सहित अधिकारियों के दल ने मै० हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि०, कोचीन, मै० हर्डीलिया केमिकल्स लि०, मुम्बई, मै० केसर पेट्रोकेमिकल्स लि० मुम्बई के परिसरों का दौरा किया । जाँच के परिणामों को संबंधित पक्षों को सूचित कर दिया गया था और जाँच रिपोर्ट की एक प्रति को सार्वजनिक फाइल में भी रखा गया था ।

7. सभी इच्छुक पक्षों की सार्वजनिक सुनवाई 12.4.2001 को आयोजित की गई थी जिसके लिए 9.3.2001 को नोटिस प्रेषित किया गया था । सार्वजनिक सुनवाई के दौरान इच्छुक पक्षों से अनुरोध किया गया था कि वे अपने द्वारा दी गई मौखिक दलीलों की लिखित प्रस्तुति 19.4.2001 तक दर्ज कराएं तथा दूसरों द्वारा दर्ज कराए गए उत्तरों को 23.4.2001 को प्राप्त करें और अपना खंडन यदि कोई हो तो 30.4.2001 तक प्रस्तुत कर दें । निम्निलिखित पक्षों ने सार्वजनिक सुनवाई में भाग लिया :-

- (1) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स, मुम्बई
- (2) हर्डीलिया केमिकल्स लि०, मुम्बई
- (3) फिनालकेमि, जर्मनी (वकील के माध्यम से)
- (4) शिनेक्टेडी स्पेशलिटीज एशिया लि०, मुम्बई
- (5) सुमिटोमा कार्पोरेशन, जापान
- (6) मित्सुई एण्ड कम्पनी लि० जापान

- (7) बर्डसैल लिमिटेड
- (8) फोसेको इण्डिया लिमिटेड, पुणे }
- (9) केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स लि०, मुम्बई } (वकील के माध्यम से)
- (10) दौराला आर्गेनिक्स लि०, नई दिल्ली }
- (11) हर्मन बावा (प्रा०) लिमिटेड }
- (12) शुभम डार्ज एण्ड केमिकल्स लि०, नई दिल्ली
- (13) सैन्चुरी लेमिनेटिंग कम्पनी लि०, कलकत्ता ।
- (14) एवरैस्ट प्लास्टिक्स, नई दिल्ली ।
- (15) पारस डाइज एण्ड केमिकल्स, दिल्ली

ख निर्यातकों के दृष्टिकोण

निर्यातकों द्वारा निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं:-

(क) फिनाल केमी, जर्मनी

(i) वे अन्तराष्ट्रीय विनिर्माता है जो कि विश्वभर में फिनाल की बिक्री कर रहे हैं । भारत में उनकी औसतन कीमत 630 अमरीकी डालर प्रति टन थी जो अन्य एशियन बाजारों में विशेषकर दक्षिण पूर्वी एशिया में चल रही कीमतों से 20% ऊंची थी ।

(ii) वर्ष, 2000 में उनकी क्षमता 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष थी और अब उनकी क्षमता 1.4 मिलियन टन प्रति वर्ष है यथा ग्लेडबैक 639 केटी/एन्टबैर्प (बैल्जियम) 420 केटी/एम्पबाइल (यू एस) 400 केटी । उनकी क्षमता उपयोगिता 92% से ऊपर थी ।

(iii) वर्ष, 2000 के दौरान उन्होंने भारत को 4579 मी० टन फिनाल का निर्यात किया

(iv) फिनाल का प्रयोग कीटनाशक के अलावा फिनाल फोर्मलडिहाइड संघनित उपयोग रेजिन्स बनाने के लिए भी प्रयोग की जाती है जिसमें विश्वभर में फिनाल के समस्त उपयोग में से 25% से भी अधिक का प्रयोग किया जा रहा है । फिनाल रेजिन्स, विभिन्न उपयोगों के यथा सजावट और औद्योगिक लेमिनेट्स, औषधियों, ढलाई उद्योग में प्रयोग आने वाले साचों के लिए, चिपकाने वाले पदार्थों तथा व्यापक रूप से अन्य कई उपयोगों में प्रयोग की जाती है । (हाल ही के वर्षों में फिनाल से बिसफिनाल -एके उत्पादन में उपरोक्त औसत दर से वृद्धि हुई है जिसकी जारी रहने की संभावना है) इस वृद्धि का अत्यंत महत्वपूर्ण कारण बिसफिनाल ए का सुसंबद्ध डिस्क तथा कम्प्यूटर भंडारण के लिए सी डी आर एम ओ, विमान की खिड़कियों तथा ट्रकों के ढाँचागत पुर्जों के उत्पादों इत्यादि में प्रयोग किया जाना है ।

(v) हानिरहित मूल्य गणना में ऋण के प्रभाव का कोई स्थान नहीं है । निर्यातक की हैसियत से वे लिखित रूप से यह कहना चाहेंगे कि कोई भी ऋण जो वे स्वीकृत करते हैं वह केवल

शाख-पत्र के विरुद्ध है। जहाँ तक उनको ज्ञात है, भारत में शाख-पत्र लेने की कीमत है। सभी वाणिज्यिक संव्यवहार के लिए ऋण पर खर्चा होता है जो अन्ततः वस्तुओं की कीमतों में प्रतिबिम्बित होता है।

(vi) रक्षोपाय शुल्क का निरंतर जारी रखने का कोई आधार नहीं हो सकता क्योंकि आयातों में कोई नहीं वृद्धि नहीं हुई है आंकड़े जिनके आधार पर आवेदक यह विश्वास कर रहे हैं कि वे फिनाल के आयातों में वृद्धि को प्रकट करते हैं, उन पर पहले ही विचार किया जा चुका है और फलस्वरूप ये रेस जुडी-काटा के सिद्धांत के अधीन आते हैं अर्थात् समान पक्षों में एक ही मुद्दे पर दो बार निर्णय नहीं हो सकता।

(vii) कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के फलस्वरूप घरेलू आवेदकों को लाभ होना ही चाहिए अथवा खोए हुए बाजार अंश को पुनः प्राप्त करना चाहिए।

(viii) रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जारी रहना और यहां तक कि उसका घटे स्तर पर आगे बढ़ाना अनुचित और सार्वजनिक हित के विपरीत है।

(ख) आई सी सी केमिकल कार्पोरेशन, यू० एस०ए०

(i) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 8 बी में रक्षोपाय शुल्क का अधिरोपण जारी रखने में तीन शर्तों की व्यवस्था है:- यथा वस्तुओं का भारत में वर्धित मात्रा में आयात होना चाहिए, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होनी चाहिए, वर्धित मात्रा में आयातों और गंभीर क्षति में कारणात्मक संबंध अथवा उससे घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति होनी चाहिए।

(ii) रक्षोपाय शुल्क जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार को यह विचार कर लेना चाहिए कि घरेलू उद्योग ने ऐसी क्षति अथवा क्षति की आंशका के समायोजन के उपाय किए हैं।

(iii) आवेदक उपरोक्त संघटकों को सिद्ध करने में विफल हुए हैं जो कि न केवल रक्षोपाय शुल्क उद्ग्रहण के लिए बल्कि उसे जारी रखने के लिए भी आवश्यक है।

(iv) वर्तमान वर्ष 2000-2001 के दौरान फिनाल का कुल आयात 1998-99 और 1999-2000 से कम दर्शाया गया है। यह 25760 मी० टन आकलित किया गया है। घरेलू उद्योग ने अपने बैलेंस शीट में घोषित स्थापित क्षमता के अनुसार 97% क्षमता उपयोगिता प्राप्त कर ली है। घरेलू उत्पादन जिन कारणों से प्रभावित हुआ था वे घरेलू उद्योग की आंतरिक कठिनाइयों से संबंधित थे जिनका फिनाल के आयात से कोई संबंध नहीं है।

(v) एच ओ सी एल और एच सी एल दोनों के लिए फिनाल एक लाभकारी उत्पाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि एच ओ सी एल और एच सी एल फिनाल का प्रयोग करने वाले घरेलू उद्योग तथा अन्य अनुप्रवाहित उत्पादों के विनिर्माताओं की कीमत पर अपने द्वारा विनिर्मित अन्य उत्पादों पर हुई हानि

की क्षतिपूर्ति वसूली करने के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं ।

(vi) फिनाल के दो विनिर्माताओं का शेष भण्डार स्थानीय बाजार में अच्छी बिक्री दर्शाता है । शेष भण्डार चार दिनों के उत्पादन के बराबर है जो कि किसी भी मानदण्ड के अनुसार सामान्य है ।

(vii) फिनाल के विक्रय मूल्य में 1998-99 में 35,541/- रु० प्रति मी०टन से 2000-2001 में 45,810/- रु० प्रति मी०टन तक की वृद्धि हुई ।

(viii) आवेदकों की फिनाल की वर्तमान विक्रय मूल्य पर लागत की विक्रय मूल्य की लगभग 260% है ।

(ix) आवेदकों ने पिछले दो वर्षों में, जब अधिक फलोत्पादक लागत और तथाकथित क्षति अथवा आयातों द्वारा क्षति की आशका से बचाने के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया गया था, कोई भी समायोजनाएं नहीं बनाई है ।

(x) आवेदक जनशक्ति के लिहाज अधिक बड़े हैं और प्रस्तावित विस्तारीकरण की लागत भी अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों और मानकों के अनुसार अत्यधिक और बढ़ा चढ़ा कर बताई गयी है ।

(xi) उन्होंने गत तीन वर्षों में लगभग 5,000 मी० टन फिनाल प्रति वर्ष भारत को निर्यात किया है ।

उन्होंने दिनांक 27.4.2001 को एक पत्र संबंधित किया है जिसमें उन्होंने यह कहा है कि मैसर्स केसर पेट्रोप्रोडक्ट्स, मुम्बई के अनुरोध पर उन्होंने 12.4.2001 को सार्वजनिक सुनवाई के लिए सामान्य कागजी कार्यवाही के प्रेषण के लिए एक व्याख्या पत्र भिजवाया था । तदुपरांत उनको यह कहा जाता रहा कि उनका आवरण पत्र कुछ विशेष दस्तावेजों के साथ प्रेषित कर दिया गया है जिसकी उनको कोई जानकारी नहीं है और जो उनकी स्वीकृति और इजाजत के बिना है । उन्होंने अनुरोध किया है कि सभी दस्तावेज जो उनके आवरण पत्र के साथ प्रेषित किए गए हैं, रद्द समझे जाएं और उनको रिकार्ड पर न लिया जाए ।

(ग) मित्सुई केमिकल्स, टोकियो, जापान

(i) फिनाल के प्रयोगकर्ताओं की माँगों की तुलना में भारतीय विनिर्माताओं के अपर्याप्त मात्रा में उत्पादन के कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी कीमतों पर भारत में फिनाल के आयातों में वृद्धि हुई है ।

(ii) भारत में भारतीय विनिर्माताओं द्वारा निश्चित कीमतों का स्तर अन्य एशियन देशों की तुलना में अत्यधिक उच्च हैं जो फिनाल व्युत्पन्नों के विनिर्माताओं के लाभांशों पर दबाव डालती है ।

और जो भारत की सामान्य अर्थव्यवस्था पर अपूर्णीय बुरा प्रभाव डालेगी ।

(iii) भारतीय विनिर्माताओं हेतु "समायोजन योजना को लागू करने" में विसफलता फिनाल के वर्धित आयात के कारण नहीं बल्कि फिनाल के भारतीय विनिर्माताओं की संरचनात्मक समस्याओं के कारण हुई है ।

(iv) यह सच नहीं है कि भारत में फिनाल का आयात 1998 की दूसरी छःमाही से भी बहुत कम कीमतों पर किया गया (जब कच्चे माल की कीमत में समायोजन वृद्धि की थी) । उन्होंने माना है कि मार्च, 99 से अक्तूबर, 99 की अवधि दौरान भारत में फिनाल की आयात की कीमतें अपेक्षाकृत निम्न स्तर की थी तथा परिणामस्वरूप फिनाल की कीमत और कच्चे माल की लागत से अन्तर 1998 की दूसरी छःमाही में कम थी । भारत में यह एक विशिष्ट मुद्दा नहीं था फिर भी कच्चे माल की कीमतों में अचानक वृद्धि के कारण एशिया के अन्य देशों सहित समस्त विश्व का औसत मूल्य अप्रैल, 2000 से दिसम्बर, 2000 के बीच लिया जाये तो यह 437 अमेरिकी डालर प्रति मीट्रिक टन था, जो कि सितम्बर, 1998 में 450 अमेरिकी डालर प्रति मीट्रिक टन से बहुत दूर नहीं है । तो इस बात का प्रमाण है कि फिनाल के विनिर्माता भारत में निर्यात मूल्यों को कम से कम कच्चे माल में हुई अचानक वृद्धि के कम से कम नौ महीने के बाद समायोजित कर सकते थे । फिनाल के वर्तमान मूल्य लाभ की दृष्टि से उचित स्तर पर रहे हैं ।

(v) जैसा कि आवेदकों द्वारा कहा गया है फोर्स मैज्योर परिस्थितियों और नकदी के अभाव के कारण उनको एक निश्चित अवधि के लिए उत्पादन रोकना पड़ा । परिणामस्वरूप भारतीय फिनाल उत्पादकों द्वारा उत्पादित फिनाल की मात्रा, भारत में फिनाल के प्रयोगकर्ताओं की कुल मांग को पूरा नहीं कर सकी और फिनाल प्रयोगकर्ताओं को रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के बाद भी भारत के बाहर से फिनाल लेना पड़ा है । भारतीय विनिर्माताओं द्वारा निम्न उत्पादन आयातित फिनाल की वृद्धि के कारण नहीं था बल्कि जुलाई, 1999 से रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के बावजूद भारतीय विनिर्माताओं द्वारा कम उत्पादन, फिनाल के आयातों में वृद्धि का कारण था ।

(vi) एच ओ सी एल और एच सी एल ने 201.05 अमरीकी डालर प्रति मी०टन की दर से रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध किया है जिससे कि फिनाल की आयात कीमत को 991 अमरीकी डालर प्रति मी०टन तक बढ़ाया जा सके और दावा किया है कि टिके रहने के लिए यह उचित विक्रय मूल्य है । यदि कोई सी आई एफ कीमत के रूप में 610 अमरीकी डालर प्रति टन ले जो कि एशिया में फिनाल का उत्पादन करने वाले देशों में दिसम्बर, 2000 का वास्तविक विक्रय मूल्य था तो हर एक देश की भूमि पर उतराई की लागत आयात शुल्क (रक्षोपाय शुल्क के बिना) के पश्चात् निम्न प्रकार से होगी -

देश	रक्षोपाय शुल्क के बिना आयात शुल्क दर	आयात शुल्क के पश्चात् आयात कीमत	- 777.75 अमरीकी डालर से अंतर
-----	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------------

चीन	9%	664.90 अमरीकी डालर	-112.85 अमरीकी डालर
जापान	0%	610.00 अमरीकी डालर	-167.75 अमरीकी डालर
कोरिया गणराज्य	8%	658.80 अमरीकी डालर	-118.95 अमरीकी डालर
ताईवान	1.25%	617.63 अमरीकी डालर	-160.12 अमरीकी डालर
भारत	27.5%	777.75 अमरीकी डालर	- 0.00 अमरीकी डालर

(vii) आयात के लिए अन्य संबंधित लागतों को मिलाकर जैसे कि सीमा निकासी शुल्क, आयात शुल्क के पश्चात् भारत में फिनाल की कीमत, रक्षोपाय शुल्क के बिना, उच्च सीमा शुल्क के कारण पहले ही एशिया के अन्य देशों से अधिक है। 201.05 अमरीकी डालर प्रति मी०टन का अतिरिक्त अथवा इसके बराबर रक्षोपाय शुल्क का अनुरोध साक्ष्य है कि एशिया के अन्य देशों की तुलना में भारतीय विनिर्माताओं की उच्च लागत वाली संरचना है। उनको आभास है कि भारत विश्व व्यापार संगठन से संबंधित है जिसका यह कार्य है कि वह सुनिश्चित करें कि राष्ट्रों का आपस में जहाँ तक संभव हो व्यापार सहजता से, कथनानुसार और स्वतंत्रता से हो, और उसके लिए, 201.05 अमरीकी डालर प्रति मी०टन का रक्षोपाय शुल्क विश्व व्यापार संगठन की नीतियों विरुद्ध और अनुचित है जो कि भारत को छोड़कर किसी भी अन्य देश पर लागू नहीं है। एच ओ सी एल और एच सी एल के अलावा फिनाल के अधिकतर विनिर्माताओं ने वास्तव में लगभग ऊपर दी गई कीमतों के स्तर पर निर्यात किया है और वर्ष 2000 के दौरान एच ओ सी एल और एच सी एल द्वारा कोई निर्यात न किया जाना भारतीय फिनाल विनिर्माताओं का अप्रतिस्पर्धात्मकता का साक्ष्य है।

(viii) भारत में फिनाल के प्रयोगकर्ताओं ने उनसे उच्च गुणवत्ता के साथ प्रतिस्पर्धी कीमत पर फिनाल की आपूर्ति के लिए अनुरोध किया है तो घरेलू फिनाल विनिर्माता पूरी करने में असमर्थ रहे थे। तथापि भारत में जब तक फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित है, भारत में फिनाल के प्रयोगकर्ताओं को कथित अतिरिक्त शुल्क सहन करने के लिए बाध्य है और फलस्वरूप फिनाल के व्युत्पन्न, जो विभिन्न उद्योगों में प्लाईवुड से लेकर विद्युत उपकरण उद्योग अथवा औषधीय उद्योग में प्रयोग किए जाते हैं, की कीमत में अन्तराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी आएगी और वह भारत की सामान्य अर्थव्यवस्था पर अपूर्ण्य प्रतिकूल प्रभाव डालेगा।

(ix) भारतीय विनिर्माताओं के कुल लाभांश में कमी कच्चे माल को प्राप्त करने के ढांचे में है। शेष भण्डार चार दिनों के उत्पादन के बराबर है जो कि किसी भी मानदण्ड के अनुसार सामान्य है। विफलता के कारण हैं और उसके लिए समायोजन प्लान योजना के कार्यान्वयन

के लिए प्रतिकारी उपाय नहीं किए गए ।

(x) उन्हें एच ओ सी एल और एच सी एल द्वारा प्रकट फिनाल की अत्यधिक विश्वव्यापी क्षमता की दृष्टि पर गहन आपत्ति है क्योंकि उनका दृष्टिकोण केवल फिनाल की आपूर्ति की ओर है और प्रयोगकर्ताओं की माँग को शामिल नहीं किया गया है, अतः एक पक्षीय है ।

(xi) एच ओ सी एल और एच सी एल ने कहा है कि फिनाल की उत्पादन क्षमता में 1.2 मिलियन टन प्रति वर्ष वृद्धि हो गई है अथवा हो जाएगी । हॉलांकि उसी अवधि के दौरान बिसफिनाल-ए जो कि एक बड़ा फिनाल व्युत्पन्न है ने मुख्यतः अमरीका में बेयर से (160,000 प्रतिवर्ष), थाईलैंड में बेयर से (160,000 टन प्रति वर्ष), सिंगापुर में मितसुई केमिकल्स से 140,000 टन प्रतिवर्ष), यूरोप में बेयर से (135,000 टन प्रतिवर्ष) और ताईवान में नान या प्लास्टिकस से (100,000 टन प्रतिवर्ष) से अपनी उत्पादन क्षमता में 0.9 मिलियन टन जो कि फिनाल के 0.8 मिलियन टन के बराबर है। प्रतिवर्ष वृद्धि कर ली है अथवा कर लेगा । फिनाल के अन्य व्युत्पन्न जैसे कि फिनोलिक रेजिन्स, साइक्लोहैक्सा तथा एनीलाइन की बढ़ती हुई मांग पर यदि विचार किया जाए तो विश्व भर में मांग और आपूर्ति का संबंध अच्छी तरह से संतुलित है । इसके अतिरिक्त 2002-2003 के दौरान कोरिया में कुम्हों पी एण्ड बी द्वारा (100,000 टन प्रतिवर्ष) चीन में बेयर (100,000 टन प्रतिवर्ष) तथा सिंगापुर में मितसुई केमिकल्स (70,000 टन प्रतिवर्ष) द्वारा बिसफिनाल -ए की उत्पादन में की घोषणा के बावजूद फिनाल के उत्पादन क्षमता में वृद्धि की अधिकारिक घोषणा नहीं की है ।

(ग) भारतीय संगठनों के दृष्टिकोण

उनके द्वारा निम्नलिखित मुख्य मुद्दे उठाए गए हैं:-

(क) आल इंडिया एसोसिएशन आफ इंडस्ट्रीज, मुम्बई

उनके द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण घरेलू उपभोक्ता उद्योग द्वारा व्यक्त किए गए दृष्टिकोण की तरह ही है ।

(ख) इंडियन केमिकल मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन

वे कहना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और एच सी एल, आई सी एम ए० के सदस्य हैं और उन्होंने रसायनों के उच्चतम शुल्क स्तर पर फिनाल पर पुनः सीमा शुल्क लगाने के लिए प्रार्थना की है उनकी प्रार्थना पर व्यापार और बिजनेस विकास विशेषज्ञ समिति की बैठक में अनुकूल विचार किया गया था और भारत सरकार को अग्रेषित अपनी उत्पाद विशिष्ट संस्तुति में उन्होंने संस्तुत किया है कि रसायनों पर उच्चतम शुल्क स्तर पर फिनाल पर पुनः सीमा शुल्क लगाया जाना चाहिए ।

(ग) सोसाइटी आफ थर्मोसेटिंग इंडस्ट्रीज, मुम्बई

रक्षोपाय शुल्क की मंशा देशी विनिर्माताओं को इतना पर्याप्त समय देने की है जिससे कि आयातों की तुलना में उन्हें प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके । शुल्क जारी रहने से इन दोनों विनिर्माताओं के कार्य या कार्यवाई में कोई सारभूत परिवर्तन नहीं हो सकेगा । रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित करने या जारी रखने के समय सरकार को उन खतरों पर विचार करना चाहिए जो उपभोक्ता उद्योग को खतरा पैदा कर सकते हैं । इसे जारी रखने से एक बड़ा खतरा उपभोक्ता उद्योग को होगा ।

रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के पश्चात् विनिर्माताओं ने अपने मूल फिनाल के मूल्य लगभग 52% अर्थात् जुलाई, 1999 में 31,000 रु० प्रति मी०टन से अक्टूबर, 2000 में 47,000 रु० प्रति मी०टन तक बढ़ा दिए जो कि बहुत मनमाने हैं । फिनालिक रेसिन उद्योग, जो कि फिनाल का मुख्य उपभोक्ता उद्योग है, फिनाल पर पूर्ण रूप से वर्धित बोझ हस्तांतरित करने में सफलता प्राप्त नहीं कर सका है । और अपने उपभोक्ताओं से केवल अतिरिक्त लागत का कुछ एक हिस्सा ही हस्तांतरित करने में सफल हो सका है । इसने वर्तमान वित्तीय वर्ष में सभी उपभोक्ता उद्योगों के कार्य को बुरी तरह प्रभावित किया है और उनमें से कई बंद होने के कगार पर है ।

रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण हेतु जब मूल आवेदन प्रस्तुत किया गया था, तब फिनाल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य अमेरिकी डालर 395-420 प्रति टन सी आई एफ भारत थे । अब, ये स्थिर हो गए हैं और 630 अमेरिकी डालर प्रति टन से ऊपर है और इसलिए विनिर्माताओं का शिकायत करने का कोई कारण नजर नहीं आता ।

(घ) आयातक/उपभोक्ता उद्योगों के दृष्टिकोण

उन्होंने मुख्य रूप से निम्न लिखित मुद्दे प्रस्तुत किए हैं:-

1. आवेदकों द्वारा वर्ष 1997-98 से आगे के फिनाल क्षमता (टी०टी०ए०) गलत आँकड़े प्रस्तुत किए गए हैं । उनके द्वारा प्रकाशित वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल लि० (एच ओ सी एल) की स्थापित क्षमता 40,000 टन प्रतिवर्ष थी जो कि 1999-2000 तक बढ़ी नहीं है अपने नियंत्रक प्रशासनिक मंत्रालय को एच ओ सी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में भी वर्ष 1999-2000 और 2000-2001 में 40,000 टन प्रतिवर्ष का लक्ष्य दर्शाया गया है । इसलिए वर्ष के लिए स्थापित क्षमता और आवेदन में दर्शाई गई क्षमता उपयोगिता को ठीक करने की आवश्यकता है । क्षमता उपयोग अत्यधिक कम इस्तेमाल होने का मामला बनाने हेतु क्षमता को बढ़ा चढ़ा कर दर्शाया गया है ।
2. जहां तक 2000-2001 का संबंध है, यह मानने का कोई आधार नहीं है कि स्थापित क्षमता वर्ष 1999-2000 से बढ़ी है क्योंकि दोनों घरेलू विनिर्माताओं की 1999-2000 की वार्षिक रिपोर्ट में भी उनकी क्षमता में वृद्धि का कोई इस प्रकार का कार्यक्रम नजर नहीं आता ।

3. यदि एच ओ सी की प्रभावी फिनाल क्षमता में वास्तव में 1997-98 में वृद्धि हुई है तो ऐसा कोई कारण नहीं हो सकता कि इसे कम्पनी की वार्षिक रिपोर्ट में शामिल न किया गया हो जो कि सच्ची है और ठीक इसके निष्पादन का सच्चा और सही रिकार्ड है और जिसे कि विधि प्राधिकारियों द्वारा आडिट किया गया है और एच ओ सी एल के मामले में सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा भी आडिट किया गया है । विधि प्राधिकारियों और इसके शेयर होल्डरों को प्रस्तुत की गई वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी का प्रमाणिक दस्तावेज है और इसमें सही विवरण होना चाहिए ।

4. यदि सही आंकड़ों को अंगीकार किया जाता है तो वर्ष 1997-98 में क्षमता उपयोगिता 104%, 1998-99 में 95%, 1999-2000 में 97% और 2000-2001 के दौरान 96% होगी । यह इस तथ्य के बावजूद है कि उनके संयंत्र उनकी आंतरिक समस्याओं के कारण कई मौकों पर कार्य नहीं कर रहे थे जो कि बाजार की मांग या आयात से संबंधित नहीं हैं ।

5. एच ओ सी एल ने अपने प्रशासनिक मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट में अप्रैल, 2000 से दिसम्बर, 2000 की अवधि के दौरान बिजली की कमी, कच्चे माल की कमी और बंद आदि के कारण 5201 मी० टन फिनाल के उत्पादन की हानि के बारे में रिपोर्ट दी है । एच सी एल ने भी अप्रैल - जून, 2000 के दौरान 5300 मी० टन तक के फिनाल के उत्पादन की हानि के बारे में रिपोर्ट दी है । इस प्रकार फिनाल उत्पादन की कुल संभावित हानि 10,501 मी० टन है जो कि आयात में वृद्धि के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से हुई है ।

6. 30 जून, 2000 के समाप्त तिमाही के लिए आडिट बगैर परिणामों की घोषणा हेतु 27 जुलाई, 2000 को आयोजित बोर्ड की बैठक में एच सी एल ने प्रस्तुत किया है कि वितरक रिफाइनरीज बहुत ज्यादा समय तक बंद होने के कारण मुख्य कच्चे माल की उपलब्धता न होने की वजह से कम्पनी का कार्य प्रभावित हुआ है । इसलिए उत्पादन हानि आयात या नकदी समस्याओं के कारण नहीं बल्कि अन्य कारणों से थी ।

(7) फिनाल की उपयोगिता क्षमता, जो कि 85% से 93% के बीच, की तुलना में एच सी एल द्वारा विनिर्मित अन्य उत्पादों के संबंध में क्षमता उपयोगिता 68% से 78% के बीच थी । इसी प्रकार की स्थिति एच ओ सी एल की थी जहां कि फिनाल की उपयोगिता क्षमता एच ओ सी द्वारा विनिर्मित अन्य उत्पादों की क्षमता उपयोगिता 79% से 86% के बीच की तुलना में से कहीं अधिक है 89% से 105% के बीच । अन्य उत्पादनों के संबंध में क्षमता की कम उपयोगिता के कारण हानि को फिनाल संयंत्र के निष्पादन के खाते में नहीं डाला जाना चाहिए ।

(8) अपनी पूर्व की प्रस्तुतियों में घरेलू विनिर्माताओं ने 1997-98 के दौरान 15352 मी० टन की तुलना में 1998-99 (दिसम्बर, 98 तक) के दौरान बहुत अधिक आयात (25048 मी० टन) के बारे में शिकायत की है । वास्तव में 1998-99 में दिसम्बर, 98 तक घरेलू फिनाल उत्पादन 69281 मी० टन (5773 मी० टन प्रतिमाह) के सामान्य उत्पादन की तुलना में बहुत कम अर्थात् 48703 मी० टन (अर्थात् 5411 मी० टन/ माह) था । इससे दिसम्बर, 1998 तक अधिक आयात की परिणति हुई । अंतिम तिमाही

में उत्पादन 17506 (अर्थात् 5835 मी०टन प्रतिमाह) था और इस प्रकार जब उत्पादन बढ़ा तो आयात बहुत तेजी नीचे आ गया और 1998-99 की अंतिम तिमाही में आयात केवल 1622 मी० टन हुआ । इस प्रकार यह देखा गया है कि 1998-99 की प्रथम तीन तिमाहियों में आयात केवल इसलिए बढ़ा क्योंकि घरेलू विनिर्माता पर्याप्त मात्रा का उत्पादन करने में असफल रहे । इस प्रकार महानिदेशक (रक्षोपाय) द्वारा इस आशंका पर रक्षोपाय शुल्क की संस्तुति की गई थी कि 1998-99 में आयात 33400 मी०टन तक बढ़ेगा । तथापि वास्तविक आयात 26,670 मी०टन था और वह भी मार्केट की मांग और घरेलू उत्पादन की बीच की दूरी को पूरा करने हेतु था । दिसम्बर, 98 तक के आँकड़ों के आधार पर 1998-99 में आयातित माल का मार्केट शेयर 36% तक होने का अनुमान लगाया था जबकि वास्तव में यह 29% था । यह भी नोट किया जा सकता है कि 1997-98 में आयातित माल का मार्केट शेयर 23% था । इस प्रकार रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण से पूर्व भी आयात के मार्केट शेयर में वृद्धि बहुत सामान्य थी और वह भी 1997 -98 में 79708 मी०टन से 1998-99 में 92073 (16% वृद्धि) तक की वर्धित मार्केट मांग के कारण थी ।

(9) आयात में वृद्धि हो रही है क्योंकि घरेलू खपत बढ़ रही है जबकि घरेलू उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जिसके कारण घरेलू मांग और आपूर्ति के बीच की दूरी को पूरा करने हेतु आयात परिणित हुआ । भारत सरकार के पूर्व केमिकल और फर्टिलाइजर विभाग द्वारा बनाए गए कार्यकारी दल के अनुसार 2001-2002 तक की नौवीं पंचवर्षीय योजना के लिए फिनाल की अनुमानित मांग, 1,45,000 मी०टन प्रतिवर्ष और 2006-2007 तक 2,49,000 मी०टन तक है । यह दर्शाता है कि भारत में इसकी मांग अधिक है । इसलिए सुरक्षा की मांग के लिए मार्केट शेयर गिरने के कारण दावा विनिर्माता नहीं कर सकते ।

(10) एच सी एल अपनी कैप्टिव मांग हेतु फिनाल का उपभोग करता है और उसने फिनाल आयात भी किया है । एच सी एल को अपनी मांग की पूर्ति एवं अपनी क्षमता को बढ़ाने हेतु अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करना चाहिए था जो कि केवल यह दर्शाता है कि एच सी एल ज्यादा उत्पादन नहीं कर सकता और इसकी क्षमता उपयोगिता इससे बेहतर नहीं हो सकती ।

(11) आयातित कच्चे माल का अंतशेष पर्याप्त नहीं है जो यह दर्शाता है कि केवल वास्तविक मांग की पूर्ति हेतु आयात का सहारा लिया जा रहा है ओर जैसा कि आवेदन में दर्शाया है आयातित माल का अंतशेष घरेलू उत्पादन के अंतशेष से कहीं कम है जो दर्शाता है कि घरेलू उत्पाद को बिना किसी परेशानी के ब्रिकी की जा रही थी । घरेलू विनिर्माता आयात वृद्धि के कारण परेशान नहीं हैं बल्कि चूंकि घरेलू विनिर्माता फिनाल की आपूर्ति करने में असफल रहे हैं इसलिए वे आयात कर रहे हैं । इसलिए फिनाल के उपभोक्ताओं को अपनी मांग पूरी करने हेतु घरेलू मांग से अधिक और ज्यादा फिनाल आयात करनी है और रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के कारण अनावश्यक रूप से उच्च मूल्य देने हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उसके उत्पादन की लागत अप्रतिस्पर्धी बनाती है और जिससे उनकी क्षमता कम उपभोग योग्य बनाते हैं और उनके संयंत्र अलाभकारी बनते हैं ।

(12) विनिर्माताओं के पास अंतशेष बहुत ज्यादा नहीं हैं और वर्ष 1999-2000 के 7 दिन के उत्पादन के बराबर है और वर्ष, 2000-2001 के लिए 4 दिन के बराबर है । रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण से पहले भी वर्ष 1997-98 के लिए अंतशेष 12 दिन के उत्पादन के बराबर और 1998-99 वर्ष के लिए यह 14 दिन के उत्पादन के बराबर था जो बड़े रसायनों हेतु एक सामान्य स्टॉक स्तर है ।

(13) वर्ष 1997-98 से आगे फिनाल की कुल खपत तेजी से बढ़ रही है । वास्तव में यह मांग और भी अधिक होगी यदि फिनाल के मूल्य ठीक स्तर पर हो जिससे कि अनुप्रवाह उत्पादक अपनी पूर्ण क्षमता का उपयोग कर सके जो कि वर्तमान में संभव नहीं हैं क्योंकि उनके अंतिम उपभोक्ता भारत में कम कीमतों पर आयातित फिनाल प्राप्त कर रहे हैं ।

(14) विद्यमान क्षमता के अधीन फिनाल के घरेलू विनिर्माता अपना उत्पादन एक सीमा तक बढ़ा सकते हैं जबकि खपत बढ़ती जाएगी और विनिर्माताओं को मनमुटाव नहीं रखना चाहिए कि उनके मार्केट शेयर नीचे जा रहें हैं । घरेलू विनिर्माताओं द्वारा नई क्षमताओं को बढ़ाने हेतु कोई गंभीर प्रयास नहीं किए गए हैं ।

(15) भारतीय बाजार में फिनाल की बढ़ती मांग और घरेलू उत्पादन में वृद्धि न होने के कारण रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के कारण उच्च आयात शुल्क भुगतान करके उपभोक्ताओं को अधिक मात्रा में फिनाल आयात करनी पड़ी । तथापि इससे घरेलू उत्पादकों को विनिर्माण की लागत कमी या अतिरिक्त उत्पादन के लिए अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए कोई कार्रवाई किए बगैर अपनी कीमतें बढ़ाने हेतु अतिरिक्त सुरक्षा कवच प्राप्त हो गया है । अपना पूरा माल बेचने के पश्चात भी यदि घरेलू उत्पादक घरेलू मांग पूरा नहीं कर सकते तो उन्हें वर्धित आयात के बारे में शिकायत नहीं करनी चाहिए और रक्षोपाय शुल्क के रूप में जारी सुरक्षा के बारे में नहीं कहना चाहिए जो कि केवल उनके बिक्री मूल्य को बढ़ाने और अदेय लाभो को बढ़ाने हेतु सुरक्षा के रूप में प्रयोग किया जा रहा है ।

(16) रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के कारण, फिनाल के घरेलू विनिर्माताओं ने फिनाल की कीमतों में वृद्धि और विनिमय दर में वृद्धि के कारण 5738/- रु० प्रति मी०टन का अनैच्छिक लाभ प्राप्त किया । पिछले दो वर्षों में फिनाल की कीमतों में वृद्धि के साथ रु० में गिरावट ने भी आवेदकों को समूचित सुरक्षा प्रदान की है ।

(17) यह देखा गया है कि आवेदकों ने उनके द्वारा दिए गए बेन्जिन के 0.606 और प्रोपलीन के 0.348 के लिए औसत खपत के आंकड़ों के विपरीत प्रोपलीन के लिए 0.255 प्रति मी०टन से 0.394 प्रति मी०टन और बेन्जिन हेतु 0.554 प्रति मी०टन से 0.723 प्रति मी०टन के बीच भिन्न- भिन्न खपत मानकों पर आबंटित कच्चे माल की लागत की गणना की है । यह किसी मान्यता प्राप्त उद्योग के स्तर का नहीं है । यू०ओ०पी० औसत खपत मानक (अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी वितरक) द्वारा दिए गए 0.538 प्रति मी०टन और 0.300 प्रति मी०टन से अधिक है । इस प्रकार आवेदकों द्वारा ली गई औसत खपत बेन्जिन के मामले में 12.4% और प्रोपिलीन के मामले में 16% अधिक है । यह उच्च खपत अनुपात आवेदकों के असक्षम कार्य

स्तर को दर्शाता है जिसने कि आवेदकों को आयात की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होने से रोका है। यदि आवेदक अपने खपत अनुपात में सुधार करें तो उनकी औसतन आबंटित कच्चा माल की लागत 306.95 अमेरिकी डालर से 268.35 अमेरिकी डालर अर्थात् 38.60 अमेरिकी डालर तक नीचे हो जाएगी। तदनुसार लागत समायोजित फिनाल की कीमतें बढ़ेंगी जो कि उनके लाभ को बढ़ाएगा। यह दर्शाता है कि आवेदकों को रक्षोपाय शुल्क की मांग करके उपभोक्ताओं को दंडित करने के बजाए अपनी क्षमता को सुधारने पर ध्यान लगाना चाहिए।

(18) 1994-95 से 2000-2001 तक के कच्चे माल की कीमतों और फिनाल की बिक्री मूल्य के विवरणों से यह देखा जाएगा कि इस पूरी अवधि में दोनों विनिर्माताओं ने पर्याप्त योगदान वसूल किया है। एच ओ सी एल के मामले में योगदान रु० 20440 से रु० 28187/- के बीच था जबकि एच सी एल के मामले यह रु० 19559/- से रु० 29890/- प्रति मी०टन के बीच था। विनिर्माताओं ने न केवल कच्चे माल की पूर्ण वर्धित लागत वसूल की बल्कि अपने लाभ के अंतर में भी वृद्धि की है।

(19) आयातित फिनाल के सी आई एफ मूल्य, शुल्क सहित कुल आयात मूल्य और वर्ष 1994-95 से 2000-2001 तक के एच ओ सी एल और एच सी एल के मूल्यों के विवरण दर्शाएंगे कि सी आई एफ मूल्य 19614 रु० से 26825/- रु० (37%) तक बढ़ गए और सदृशतः 2000-2001 में एच ओ सी एल के बिक्री मूल्य भी 32184 रु० से 45810 रु० (42%) और एच सी एल के बिक्री मूल्य 1994-95 में 33008 रु० से 47513 /- रु० (44%) तक बढ़ गए। इस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के कारण विनिर्माताओं को कोई हानि नहीं हुई। उनके मूल्य हमेशा कुल आयात मूल्यों के साथ समायोजित थे।

(20) मै० फिनाल केमी, जर्मनी ने पूर्व में कहा था कि लगातार तकनीकी सुधार के कारण फिनाल बाजार में 50% मूल्य में कमी आई थी जो कि वर्तमान फिनाल मूल्यों को पर्याप्त अधिक लागत प्रभावी बना रहे थे इसलिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने का सही रास्ता तकनीकी उन्नयन द्वारा उत्पादन की लागत में बचत प्राप्त करना है।

(21) दोनों विनिर्माताओं ने अपने पूर्व में दी गई प्रस्तुति के यह स्वीकार किया है कि वे 6000/- प्रति मी०टन की लागत बचत प्राप्त करेंगे। तथापि उन्होंने अब कहा है कि सभी योजनाएं क्रियान्वित नहीं हुई इसलिए समायोजन योजना लागू करने में असफल रहने के कारण रक्षोपाय शुल्क सुरक्षा को आगे विस्तारित करने के लिए उनका कहना ठीक नहीं है।

(22) हालांकि लागत समायोजित फिनाल के मूल्य बढ़े नहीं हैं, मूल्य वास्तविक रूप में 450 अमेरिकी डालर प्रति मी०टन से 670 अमेरिकी डालर प्रति मी०टन तक बढ़े हैं। शुल्क की अतिरिक्त मात्रा के रूप में वर्धित आयात के मूल्यों के साथ-साथ भारतीय रु० के मुकाबले अमेरिकी डालर की कीमतों में वृद्धि ने विनिर्माताओं को अपरोक्ष लाभ दिया है। जब जून 99 में 22% रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया गया था तो फिनाल के विनिर्माताओं को रक्षोपाय शुल्क के रूप में प्राप्त लाभ 3798 रु० एवम् आयात शुल्क संरक्षण के रूप में 9744 रु० प्राप्त हुआ जिसमें सी वी डी शामिल नहीं हैं। जब मार्च, 2000 में, रक्षोपाय

शुल्क की दर 22% से 15% तक घटाई गई तो वास्तव में रक्षोपाय शुल्क के रूप में लाभ 3811 रु० तक बढ़ गया और रक्षोपाय शुल्क की दर में कमी ने फिनाल के विनिर्माताओं को प्रभावित नहीं किया। सी वी डी को छोड़कर आयात शुल्क संरक्षण 9744 रु० से 12476 तक बढ़ा। दिसम्बर, 2000 में शुल्क की दर 22% से 15% तक करने के बावजूद भी जब जून, 99 में रक्षोपाय शुल्क शुरू किया गया था तब के 3798 रु० की तुलना में 4729 रु० के लगभग था आयात शुल्क संरक्षण बिना सी वी डी के 15482 रु० तक बढ़ गया।

(23) इस प्रकार फिनाल की वर्धित कीमतों और डालर की कीमतों में वृद्धि के कारण फिनाल विनिर्माता पहले ही 5738 रु०/मी०टन (रु० 15482-रु० 9744) की अनैच्छिक अतिरिक्त सुरक्षा प्राप्त कर चुके। यदि इसे लागत बचत के साथ, जिसका फिनाल विनिर्माताओं द्वारा 6000/मी०टन का दावा किया गया था, के साथ जोड़ा जाता है तो, वे इच्छित सुरक्षा से कहीं अधिक सुरक्षा पहले की प्राप्त कर चुके हैं। यदि रक्षोपाय शुल्क हटा भी लिया जाता है तो भी रु० 10534 की आयात शुल्क सुरक्षा तो रहेगी (अर्थात् सी वी डी + 27.5% की दर से अधिभार (8669) + एस ए डी @ 4% की दर से (1865)

(24) एच ओ सी एल अपने कोच्चि संयंत्र में इसके शुरू होने से ही लाभ कमा रहा है, और पहले जब 1998-99 में रक्षोपाय शुल्क लागू किया गया तो कोई हानि नहीं थी बल्कि 18.3 करोड़ का लाभ था जो 2000-2001 के प्रथम नौ महीनों में 36.5 करोड़ तक पहुंच गया है। एच सी एल और एच ओ सी एल के फिनाल संयंत्रों के निष्पादन को अलग इकाई हस्ती के रूप में लिया जाना चाहिए जिनका लाभ दूसरे अधीनस्थ असक्षम संयंत्रों द्वारा खाया जा रहा है जहां उन्होंने पर्याप्त अनुत्पादक निवेश किए हैं। रक्षोपाय शुल्क की मांग करने के पीछे एकमात्र इच्छा फिनाल उपभोक्ताओं से अतिरिक्त लाभ प्राप्त करने की है।

(25) घरेलू फिनाल विनिर्माताओं ने अतिरिक्त विश्वस्तरीय क्षमता के सृजन को उद्धृत किया जिस तथ्य की जानकारी उनको 1998 के प्रथम आवेदन के समय थी। महानिदेशक रक्षोपाय ने रक्षोपाय शुल्क की अनुशंशा नई क्षमताओं का सामना कर सकने के लिए, जैसा कि उन्होंने पहले दावा किया था, की थी। वास्तव में फिनाल क्षमताओं में वृद्धि बिसफिनाल -ए एवं अन्य फिनाल अंतिम उत्पादों की बढ़ती विश्वस्तरीय मांग के साथ सामना करने के लिए की गई थी।

(26) कच्चे तेल की कीमतें अमेरिकी डालर 25/ प्रति बैरल के स्तर पर नीचे आनी शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त कच्चे तेल में वृद्धि ने पूरे विश्व में बहुत से उद्योगों को प्रभावित किया है और इस प्रकार की बाजार शक्तियों का सामना किया जाना है जिसके लिए रक्षोपाय शुल्क जैसी किसी कृत्रिम सुरक्षा का दावा नहीं किया जा सकता है।

(27) घरेलू वितरकों द्वारा दिया जा रहा उधार कीमत पर है क्योंकि इस पर ब्याज 19% है। देरी से हुए भुगतान के लिए वसूल किया जाता है। वास्तव में एच ओ सी एल द्वारा सामान्य उधार अवधि 90 दिनों से घटाकर 60 दिन कर दी गयी है। बिक्री मूल्यों के प्रतिशत के रूप में कर्जदारों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। यह देखा गया है कि 1999-2000 की तुलना में वर्ष 2000-2001 में एच सी एल की

औसत बिक्री मूल्य 35.01% तक और एच ओ सी एल के मूल्य 36.97% तक बढ़ गए हैं । फिनाल विनिर्माता ऋण की अनुमति हेतु कड़ी ऋण शर्त अधिरोपित कर रहे हैं और बैंक गारंटी का आग्रह कर रहे हैं । बिक्री के लिए अपनी शर्त मनवाने के लिए वे अच्छी वित्तीय स्थिति में हैं ।

(28) एच ओ सी ने पहले आवेदन में प्रस्तुत किया था कि उनकी उधार अवधि 69 दिनों तक बढ़ गई है । वर्तमान में एच ओ सी एल अपने किसी उपभोक्ताओं को 60 दिनों से अधिक की उधार अवधि पर फिनाल आपूर्ति नहीं करता और यदि ब्याज लागत के साथ 60 दिनों से ज्यादा उधार दिया जाता है तो यह उनकी आर्थिक प्रवाह को बढ़ाएगा और उनकी आर्थिक समस्याओं को हल करेगा ।

(29) विनिर्माताओं ने 6000/- रु० प्रति मी०टन की लागत कमी को प्राप्त करने हेतु समायोजन योजना प्रस्तुत की है और उन्होंने पुष्टि की है कि उन्होंने इसे क्रियान्वित कर दिया है । अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के अनैच्छिक लाभ को भी उन्होंने प्राप्त किया है । इसलिए उनके पास रक्षोपाय शुल्क के विस्तार की मांग करने हेतु कोई वैध कारण नहीं है ।

(30) दोनों विनिर्माताओं के पास पर्याप्त अनुभव है और उन्होंने तकनीकी परिवर्तन द्वारा सामान्य शुल्क सुरक्षा के अधीन अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने हेतु पिछली कार्रवाईयों से पर्याप्त सुरक्षित निधि बना ली है । उन्होंने 24 महीनों तक रक्षोपाय शुल्क का लाभ भी प्राप्त कर लिया है । इसलिए रक्षोपाय शुल्क का लाभ और जारी रखने का कोई कारण नहीं है ।

(31) समायोजन योजना में दर्शाई गई योजनाएं, जिनके आधार पर महानिदेशक(रक्षोपाय) द्वारा रक्षोपाय शुल्क की संस्तुति की गई थी, भी लागू की गई प्रतीत नहीं होती और जैसा कि उनके द्वारा कहा गया था, इन्हें लागू किया भी गया होता जिससे उत्पादन लागत में कमी होने पर भी रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण उचित नहीं होगा ।

(32) सक्षम और निपुण कर्मचारियों का पलायन फिनाल संयंत्रों के निष्पादन के कारण नहीं बल्कि अन्य कई कारणों से हो सकता है क्योंकि दोनों इकाईयां फिनाल संयंत्रों में पर्याप्त लाभ कमा रही हैं । उनके आवेदन से यह भी देखा गया है कि 8 महीनों में कर्मचारियों में केवल 5% है जो कि प्रत्येक उद्योग में अपने कर्मचारियों की अधिकतम दक्षता बढ़ाने के लिए कर्मचारियों को कम करने की जो प्रवृत्ति है, के कारण हो सकता है । यह भी कहा जा सकता है कि मित्सुई अपने केवल 80 कर्मचारियों के साथ अपने 200000 टन प्रति वर्ष का उत्पादन करती है और फिनाल के भी 125 व्यक्तियों के साथ 400000 मी०टन प्रतिवर्ष का उत्पादन करती है । इसी तर्ज पर एच सी एल ने अपनी मानव शक्ति लागत को कम किया और एच ओ सी एल ने कम स्तर के लागत के 9% से 10% तक की अपनी मानव शक्ति लागत को कम करने हेतु स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की योजना बनाई है क्योंकि उद्योग की औसत 5% से 6% है और विश्वस्तर पर यह औसत 2% से 4% है ।

(33) फिनाल का बिक्री मूल्य अमेरिकी डालर 991 पूर्णतया न्यायोचित नहीं है जबकि अप्रैल, 2000 से नवम्बर, 2000 तक फिनाल के अंतर्राष्ट्रीय औसतन मूल्य अमेरिकी डालर 624 थे। यह अनुरोध किया गया है कि अमेरिकी डालर 991 का मूल्य के विवरण सभी प्रभावित पक्षों को उपलब्ध कराया जाए जिससे कि इनका एक पारदर्शी तरीके से परीक्षण किया जा सके। दोनों विनिर्माताओं के संयंत्रों का पूर्णतया अवमूल्यन हुआ है और उन्होंने भूतकाल में इन संयंत्रों से पर्याप्त लाभ प्राप्त किया है। इस प्रकार वे सामयिक शुल्क संरक्षण के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए पूर्ण सक्षमता के साथ पूर्ण क्षमता उपयोगिता प्राप्त करने की स्थिति में हैं। विनिर्माताओं ने 5738 रु० प्रति मी०टन का अनैच्छिक अतिरिक्त लाभ भी फिनाल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि और डालर की दरों में वृद्धि के कारण प्राप्त किया है। इसलिए रक्षोपाय शुल्क को आगे बढ़ाना न्यायोचित नहीं है। अगर इस प्रकार के विस्तार की अनुमति दी जाती है तो यह केवल फिनाल विनिर्माताओं द्वारा मूल्य वृद्धि में परिणित होगा और फिनाल उपभोक्ता संयंत्रों की क्षमता उपयोगिता कम होगी।

(34) उधार लेने की क्षमता और शेयर मूल्य कम्पनी के सम्पूर्ण निष्पादन पर निर्भर होती है और चूंकि फिनाल लाभकारी मूल्यों पर बेचा जा रहा था, कम्पनी द्वारा उठाया गया घाटा अन्य उत्पादों के कारण हुआ है न कि फिनाल के कारण।

(35) प्रभावी फिनाल क्षमता में वृद्धि के दावे को स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि एच ओ सी एल की नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में दर्शाई गई क्षमता 40000 टन प्रतिवर्ष का उत्पादन जारी है। रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण जारी रखने के लिए प्रस्तुत समायोजन योजना एकदम अस्पष्ट, बिना किसी वास्तविक समय सीमा और प्रतिबद्धता की है। संबद्ध पूंजीगत व्यय हेतु एच ओ सी एल के वार्षिक बजट आकलन में कोई प्रावधान नहीं है। इसी प्रकार तकनीकी उन्नयन हेतु भी कोई निश्चयी विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। यह पता नहीं है कि क्या उनके लाइसेन्स धारियों या सुप्रसिद्ध सलाहकारों द्वारा समर्थित कोई व्यावहारिक रिपोर्ट तैयार की गई है जिसकी अनुपस्थिति में लक्षित बचत को प्राप्त करने को निर्धारित किया जा सके।

(36) वर्ष 1997-98 के लिए एच सी एल की वार्षिक रिपोर्ट में इसके निदेशकों द्वारा दिए गए कथन शामिल है कि 1998 के दौरान उत्पादन परियोजना लगभग पूर्ण है और गैस टर्बाइन उत्पादन ने भी अपना कार्य सुचारु रूप में शुरू कर दिया है। महानिदेशक (रक्षोपाय) के निष्कर्षों में भी यह प्रस्तुत किया गया था कि उत्पादन की सुविधा स्थापित की गई है और यह वर्ष 1999 में स्थापित हो जाएगी। यह समझा नहीं जाता कि एच सी एल कैसे रक्षोपाय शुल्क सुरक्षा की अवधि के दौरान समायोजन योजना के अधीन योजना बनाई जाने को दर्शा रहा है। जबकि इसको प्रथम आवेदन की सुनवाई से पहले ही क्रियान्वित कर दिया गया था। 1999-2000 की एच सी एल की वार्षिक रिपोर्ट से यह देखा गया है कि अपने जेनरेटर के अनुसार प्रति के डब्ल्यू एच विद्युत की लागत डी जी सैट के लिए 4.23 रुपये और खरीदी गई विद्युत की लागत 6.37 रु० के मुकाबले नाफ्था के आधार पर गैस टर्बाइन से निर्मित विद्युत की लागत रु० 3.34/- थी, यह दर्शाता है कि कैप्टिव विद्युत उत्पादन द्वारा मुख्य बचत प्राप्त की गई थी वास्तव में बचत और भी अधिक होती यदि कोई सस्ता ईंधन, अधिक लागत वाले ईंधन नाफ्था का स्थान लेता जैसा कि अन्य कई विद्युत संयंत्रों द्वारा किया गया है।

(37) आवेदकों द्वारा महानिदेशक (रक्षोपाय) के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया है कि जे एन पीटी पत्तन पर प्रोपिलीन प्राप्ति और क्यूमिन हेतु नई तैंकेनीकी के सहयोग से कच्चे माल की कीमते कम हो जाएगी । ऐसी किसी विश्वस्त योजना और प्राप्त बचत के बारे में कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । इन विवरणों को मंगाया जाये क्योंकि अब यह कहा गया है कि कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि के कारण लाभ समाप्त हो गया है । तथापि यह गलत है कच्चे तेल के मूल्य अब कम हो गए हैं और इस संबंध में प्राप्त लाभ की मात्रा के बारे में एच सी एल से पूछा जा सकता है ।

(38) एच ओ सी एल और एच सी एल दोनों द्वारा प्रस्तुत समायोजन योजना एक बहानेबाजी है जो कि केवल पेपर वास्तविक क्रियान्वयन नहीं होने पर भी है इसमें कोई विश्वास और गंभीरता नहीं है । यह अस्पष्ट और सामान्य कथन है और विवरणहीन और विशेषकर साक्ष्य से समर्थित नहीं है और प्रस्तावित समायोजन के बारे में गलत धारणा सृजित करने हेतु की गई है जिससे कि किसी भी तरह रक्षोपाय शुल्क का उदग्रहण जारी रखना सुनिश्चित किया जा सके ।

उपरोक्त के अलावा कुछ इच्छुक पक्षों से निम्नानुसार कथन दिए हैं:-

क. मै० केसर पेट्रोप्राडक्ट्स लि० मुम्बई

उनके द्वारा किए वास्तविक आयात के अनुसार फिनाल के आयातित मूल्य दिसम्बर, 2000 में अमेरिकी डालर 610 न होकर अमेरिकी डालर 670 थे और लागत समायोजित फिनाल मूल्य लगभग 489 अमेरिकी डालर बैठता है ।

रक्षोपाय पर अनुबन्ध के अनुच्छेद 7 का विश्लेषण यह दर्शाता है कि शब्द “पुनरीक्षण” एक रक्षोपाय उपाय के संदर्भ में प्रयोग किया है जो तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लागू होता है । उस मामले में जहाँ रक्षोपाय उपाय तीन वर्ष से कम अवधि के लिए लागू किया जाए, जैसा कि वर्तमान मामले में है, प्राधिकारी ने पहले ही तय कर दिया है कि कथित कम अवधि गंभीर क्षति को रोकने और बचाने के लिए और समायोजन सुविधा के लिए पर्याप्त है । इस प्रकार के मामले में रक्षोपाय उपाय लागू रहने की अवधि को बढ़ाना “फिर से” आयात की वस्तुओं पर रक्षोपाय शुल्क लागू करना है । यह तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रारंभिक रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के पश्चात दो वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती।

रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 16 और 18 उपरोक्त विषय से संबंधित है । नियम 16 (2) के अनुसार नियम 12 में लगाया गया रक्षोपाय शुल्क यदि पहले रद्द न कर दिया जाए तो अधिरोपण की तिथि से चार वर्ष समाप्त होने पर उसका प्रभाव समाप्त हो जाता है । क्योंकि महानिदेशक ने रक्षोपाय शुल्क की केवल दो वर्षों के लिए संस्तुति की थी और केन्द्र सरकार ने भी दो वर्षों के लिए अर्थात् 29-6-2001 तक रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया था, यदि पहले वापस न लिया जाए तो शुल्क का प्रभाव उस दिन समाप्त हो जाना चाहिए । दूसरे शब्दों में नियम 16(2) केवल महानिदेशक को 29-6-2001 से पूर्व रक्षोपाय शुल्क वापस लेने का अधिकार देता है ।

नियम 18 उस परिस्थिति से संबंधित है जहाँ रक्षोपाय शुल्क के प्रवर्तन की अवधि के दौरान, पुनरीक्षण का उत्तरदायित्व लेता है । यह पुनरीक्षण यह आंकने के लिए है कि क्या कथित रक्षोपाय शुल्क

शुरू में नियत की गई अवधि के लिए जारी रहना चाहिए अथवा इसे वापस ले लिया जाए अथवा सरलीकरण की प्रक्रिया बढ़ा दी जाए । यह ऐसी परिस्थिति से व्यवहार नहीं करता जहाँ रक्षोपाय शुल्क की आरम्भ में संस्तुत की गई अवधि को महानिदेशक आगे बढ़ा सकता है । महानिदेशक को केवल इतना जाँचने का अधिकार है कि कथित दो वर्ष की अवधि कम की जा सकती है अथवा नहीं तथा महानिदेशक को रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण की अवधि को बढ़ाने का कोई अधिकार नहीं है । अधिरोपण की अवधि को बढ़ाना नया शुल्क लगाने के बराबर है जो कि नई जाँच शुरू करने के समान है ।

ख. आल्टा लेबोरट्रीज लि० मुम्बई

वे एस्प्रिन (एसीटील सालिसाइलिक एसिड आई पी) के विनिर्माता हैं और इस उत्पाद के विनिर्माण हेतु फिनाल हमारा कच्चा माल है । हमारी फिनाल की वार्षिक खपत लगभग 1200 मी०टन है । एस्प्रिन के मूल्य सरकार द्वारा डी पी सी ओ 1987 के अधीन वैधानिक रूप से नियन्त्रित होते हैं । इस उत्पाद के विनिर्माण हेतु फिनाल मुख्य कच्चा माल होने के कारण, फिनाल की लागत एस्प्रिन के मूल्यों पर सीधा प्रभाव रखती है । पिछले 12 महीनों के दौरान आवेदकों ने चरणों में अपने बिक्री मूल्य लगभग 55% तक बढ़ा दिए हैं । पिछले तीन वर्षों के दौरान घरेलू विनिर्माताओं द्वारा लिए जा रहे फिनाल के असामान्य उच्च मूल्यों के कारण उन्हें हानि उठानी पड़ी है क्योंकि तीन वर्षों में एक बार उनके मूल्य सरकार द्वारा संशोधित किए जाते हैं और अंतरिम राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया लम्बी एवं कठिन है । लागत में वृद्धि और मूल्यों के संशोधन में हमेशा असामान्य देरी होती है ।

(ग) स्नेक्टेडी स्पेशलिटीज एशिया लि. मुम्बई

(i) वे अमेरिकी स्नेक्टेडी इंटरनेशनल इंक ('एस आई आई') (अल्कलेटिड फिनाल के विश्व के सबसे बड़े विनिर्माता) और सनशील्ड केमिकल्स लि. (एस सी सी) जो कि विशेष रसायनों का विनिर्माण के लिए एक सूचीबद्ध कम्पनी के बीच एक संयुक्त उपक्रम कम्पनी है । वे स्टेट- आफ-आर्ट तकनीक के साथ अल्कलेटिड फिनाल का सबसे ज्यादा रेंज का विनिर्माण करते हैं जो कि विभिन्न महत्वपूर्ण और मुख्य क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है ।

(ii) फिनाल उनका मूल कच्चा माल है जो कि अल्कलेटिड फिनाल के विनिर्माण हेतु उनके कच्चे माल का लगभग 50% बैठता है, और इसकी शुद्धता, विश्वसनीय गुणवत्ता और प्रतिप्रस्पर्धी मूल्य उनके उत्पाद के सफल गुणवत्ता वाले उत्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है । वे लगभग 3000 मी.टन फिनाल प्रतिवर्ष उपभोग करते हैं ।

(iii) फिनाल के अलावा हर्डीलिया केमिकल्स अल्काइल फिनाल का भी विनिर्माण करते हैं और यदि उन्हें फिनाल की कीमतों को बढ़ाने का मौका मिलता है तो अन्यो द्वारा भारत में अल्काइल फिनाल का विनिर्माण व्यवहार्य नहीं होगा और इस स्थिति में अल्काइल फिनाल उद्योग हर्डीलिया के पूर्ण एकाधिकार में होगा और सरफैक्टेन्ट एण्टी आक्सीडेंट जैसे अंतिम उत्पाद उद्योग जो कृषि क्षेत्र में आते हैं, कपड़ा पेस्टिसाइड, प्लास्टिक, फूड्स और बहुत से उद्योग जो कि भारतीय समाज हेतु दिन प्रतिदिन की वस्तुओं का विनिर्माण करती हैं, की लागत निरर्थक हो जाएगी ।

- (iv) फिनाल के विनिर्माताओं ने अपने निवेशों का लाभ प्राप्त किया है और पिछले कई सालों में इस लाभ को अपने संयंत्रों की आर्थिक स्थिति को सुधार में लगाने के बजाए असंबद्ध विविध कामों में लगाया है ।
- (v) उन्होंने अल्काइल फिनाल के विनिर्माताओं हेतु "क्षेत्र विशिष्ट छूट" की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की है जिससे कि उनके लिए एक सम स्तरीय क्षेत्र सुनिश्चित हो सके ।

घ एक्सप्रो इंडिया लि. मुम्बई :

रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण केवल घरेलू विनिर्माताओं को समय प्राप्त करने और आयात की तुलना में अधिक प्रतिस्पर्धी होने हेतु ही किया जाना चाहिए । आवेदकों द्वारा दी गई प्रस्तुति द्वारा यह स्पष्ट है कि फिनाल विनिर्माण वास्तव में सस्ता हो सकता है यदि विश्व स्तरीय श्रेणी के सक्षम संयंत्र कार्यरत हो । ऐसा कोई इशारा नहीं है कि दोनों घरेलू विनिर्माता ऐसी कोई योजना बना रहे होंगे । उन्होंने एक नया संयंत्र स्थापित करने की अपनी पहली योजनाओं को ही लम्बित कर रखा है और इसलिए घरेलू उत्पादकों को विश्वस्तरीय प्रतिस्पर्धी बनाने हेतु कुछ भी पर्याप्त योजना नहीं होगी ।

(ड) कलर केम लि., ठाणे

तैयार उत्पाद यथा लेदर केमिकल्स/चमड़े की वस्तुओं पर आयात शुल्क फिनाल के कच्चे माल से कम है । उन्होंने अपना व्यापार गवां दिया क्योंकि उनके द्वारा विनिर्मित स्वदेशी उत्पादों से सस्ता होने के कारण, चमड़ा उद्योग आयात शुल्क कम होने के कारण लेदर केमिकल्स के आयात को प्राथमिकता देता है ।

ऊ घरेलू उत्पादकों के दृष्टिकोण

घरेलू उत्पादकों निम्न मुख्य मुद्दे उठाए हैं :-

(क) मैसर्स हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लि. कोचीन

(i) उनकी विनिर्माण इकाई 1) रसायनी - 410027, जिला रायगढ़, महाराष्ट्र 2) अम्बालामुगल -682302, जिला इर्नाकुलम, केरल में हैं और फिनाल संयंत्र केवल अम्बालामुगल में हैं ।

(ii) वे मूल आर्गेनिक केमिकल्स यथा फिनाल का विनिर्माण करते हैं जो कार्बोलिक एसिड अथवा हाइड्रोक्सी बैनजीन, एसीटोन, एनीलाइन, नाइट्रोटोल्यून्स, नाइट्रोक्लोरो बैनजींस, मोनोक्लोरोबैनजीन, फोरमलडिहाइड, नाइट्रोबैनजीन, सल्फ्यूरिक एसिड, साइक्लोहेक्सीलेमिन, एसिटोनिलाइड, कास्टिक सोडा, हाइड्रोजन पैराक्साइड, ब्यूटिन - 1, 4- डिओल के नाम से भी जाने जाते हैं ।

(iii) उनके द्वारा दोनों क्रिस्टल और हाइड्रेटि रूप में विनिर्मित फिनाल, फिनाल फोरमलडिहाइड रेजिन्स, लेमिनेट्स प्लाइवुड, पार्टीकल बोर्ड, फार्मास्यूटिकल्स इत्यादि के विनिर्माण में प्रयोग होता है । लेदर

केमिकल्स के विनिर्माण में बिसफिनाल -ए तथा अल्किल फिनाल, फिनाल के पारदर्शी रूप में ही प्रयोग किया जाता है ।

(iv) बैनजीन और प्रोपिलिन मुख्य कच्चा माल है जबकि क्यूमिन फिनाल के विनिर्माण में एक मध्यवर्ती है । फिनाल के विनिर्माण में एसिटोन को एक सह-उत्पाद के रूप में बनाया जाता है । फिनाल और एसिटोन 1 : 0 : 6 के अनुपात में बनाया जाता है ।

(ख) हर्डिलिया केमिकल्स लि. मुम्बई

वे मूल आर्गेनिक केमिकल्स और विशिष्टियाँ जैसे कि फिनाल, एसिटोन, थैलिक एनहाइड्राइड, डाइसिटोन अल्कोहल, डोडिसिल फिनाल, नोनिल फिनाल, डाईफिनाइल आक्साइड, आइसाब्यूटिल बैजिन, आइसोफोरोन, हीट ट्रांसफर मीडिया, एसिटोफिनोन विनिर्माण करते हैं ।

(ii) उनके द्वारा दो श्रेणी के फिनाल विनिर्मित किए जाते हैं यथा क्रिस्टालाइन और हायड्रेटिड । जबकि क्रिस्टालिन फिनाल पारदर्शी रूप में सख्त फिनाल है, हायड्रेटिड फिनाल 10% से भी कम पानी और फिनाल का सम्मिश्रण है । इसी कारण फिनाल परिवशी अथवा ठंडी परिस्थितियों में भी पिघले रूप में रहता है और अन्तिम प्रयोगकर्ताओं को उतराई के समय माल को रखने उठाने में आसानी होती है । क्रिस्टालिन फिनाल का वजन के द्वारा कम से कम 99.5% की शुद्धता है । तथापि हाइड्रेटिड फिनाल की बिलिंग माल में फिनाल की वास्तविक मात्रा के आधार पर की जाती है ।

(iii) फिनाल का प्रयोग फोरमलडिहाइड रेजिन्स, लेमिनेट्स, प्लाइवुड, पार्टिकल बोर्डों, बिसफिनाल ए अल्किल फिनाल, फार्मास्यूटिकल्स, डाईफिनाइल आक्साइड इत्यादि के विनिर्माण में प्रयोग किया जाता है । लैडर केमिकल्स और बिसफिनाल-ए में सामान्यतः केवल क्रिस्टालिन फिनाल की आवश्यकता होती है ।

(iv) आयातित फिनाल और उनके द्वारा विनिर्मित फिनाल हर प्रकार से एक समान है । भारत में उत्पादित फिनाल अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है तथा विश्व बाजार में अच्छी तरह स्वीकार किया जाता है ।

(v) 10,000 टन प्रतिवर्ष की फिनाल की सुविधा 1960 के दशक में स्थापित की गई थी तथा 1968 में संचालित हो गई थी । शुरू में फिनाल विनिर्माण सुविधा में 3.31 करोड़ रुपये का निवेश था । समय के साथ वित्त वर्ष 1996-97 के अंत तक डीबाटलनेकिंग में निवेशों से पूर्णरूपेण आंतरिक संभूतियों के जरिये क्षमता को 20,000 टन प्रति वर्ष तक बढ़ा दिया था । संयंत्र की क्षमता 1999-2000 के दौरान 32,000 टन प्रतिवर्ष थी और अब वार्षिक आधार पर फिनाल संयंत्र की क्षमता 34,000 टन प्रतिवर्ष है ।

(vi) वर्ष 1995-96 में फिनाल के लिए पैकिंग लागत 3.5 रुपये प्रति किलोग्राम, 1996-97 के लिए 3.75 रुपये प्रति किलोग्राम (औसतन) और 1997-98 के लिए 4/-रु. प्रति किलोग्राम थी । यह थोक और पैकड फिनाल की शुद्ध बिक्री वसूली में निकटतम अन्तर था । फिनाल का विक्रय मूल्य भूमि पर उतराई की लागत की समतुल्यता पर आधारित है न कि लागत जमा लाभ की धारणा पर । फलस्वरूप कच्चे माल की लागत और विक्रय मूल्य में कोई परस्पर संबंध नहीं है ।

(vii) हालांकि बहुत ही निचले स्तर की गत रक्षोपाय शुल्क जाँच अवधि के पश्चात कीमत वसूलियों ने वास्तविक रूप से वृद्धि दर्शाई है फिर भी शुद्ध कीमत वसूली से लागत वृद्धि घटाने के पश्चात गिरावट दर्शाई है ।

(viii) रक्षोपाय शुल्क लागू होने के बावजूद फिनाल उत्पादन के काम में 1998-99 और अप्रैल-नवम्बर, 2000 के बीच प्रतिटन नियोजन की हानि 19.86% तक है ।

(ix) उन्होंने वर्ष 1998-99, 1999-2000, आर 2000-01 (नवम्बर, 2000 तक) में फिनाल का निर्यात नहीं किया ।

उपरोक्त के अलावा, घरेलू उत्पादकों ने मोटे तौर पर निम्नलिखित कहा है :

क. भारत में फिनाल का आयात मुख्यतः बैल्जियम, चीनी ताइपे, जर्मनी, इटली, जापान, कोरिया डी पी आर, कोरिया आर पी, नीदरलैण्ड, रूस, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, यू०के० और यू०एस०ए० से किया जाता है । घरेलू उत्पादन की तुलना में तथा वास्तविक रूप से आयातों ने वृद्धि का रुख दर्शाया है ।

1994-95 से 1999-2000 के दौरान आयात और घरेलू उत्पादन निम्न प्रकार हैं:-

वर्ष	घरेलू उत्पादन मी०ट०	आयात मी०ट०	आयातों का % घरेलू उत्पादन की तुलना में
1994-95	57780	6664	11.53
1995-96	63719	21752	34.14
1996-97	57466	19545	34.01
1997-98	69281	15352	22.16
1998-99	66210	26670	40.28
1999-01	69961	28992	41.44

ख एच ओ सी एल और एच सी एल के अलावा भारत में केवल एक फिनाल विनिर्माता है (नेवेली लिग्नाइट कार्पोरेशन लिमिटेड) जिनकी क्षमता 1500 टन प्रतिवर्ष और उत्पादन 1000 प्रतिवर्ष से भी कम है । इस प्रकार देश में फिनाल का कुल घरेलू उत्पादन एच ओ सी एल और एच सी एल द्वारा ही माना जाता है ।

ग. अप्रैल से दिसम्बर (प्रथम छःमाही) 2000 के पहले साढ़े आठ महीनों में बताया गया है कि 18247 मी०टन का आयात हुआ । उन्होंने कहा है कि नवम्बर और दिसम्बर, 2000 में आयातों में तेजी से वृद्धि हुई । 1998-99 और 1999-2000 की अवधि के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत आँकड़े बजार की आसूचना के स्रोतों पर आधारित है ।

घ. घरेलू मांग को पूरा करने के लिए घरेलू उत्पादकों की क्षमता उपयोगिता में जो 1996-97 में 85% से 1999-2000 में 89% तक की वृद्धि हुई वह 2000-2001 के प्रथम आठ महीनों में 83% तक गिर गई । उन्होंने अपनी प्रभावित उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि के लिए सफल प्रयत्न किए फिर भी वे इस प्रकार के विस्तारों के लिए निवेशों हेतु अतिरिक्त राशि रक्षोपाय शुल्क के फायदों से प्राप्त नहीं कर सके । आर्थिक तंगी के कारण एच ओ सी को मजबूरन अप्रैल, जून और अक्तूबर, 2000 माह में काम बंद करना पड़ा जिसके कारण वर्धित क्षमता स्तरों की तुलना में इन महीनों में उत्पादन की मात्रा कम थी ।

ङ फिनाल के कुल घरेलू खपत में उनका फिनाल का बाजार शेयर जो 1996-97 में 74.3% से 1997-98 में 80.25% तक बढ़ गया था वह 1998-99 और 1999-2000 में 71.13% और 70.75% तक गिर गया । उन्होंने यह भी कहा है कि वे फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के बावजूद काम में घाटे की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं ।

च. 1999 की प्रथम छःमाही के दौरान किया गया अन्वेषण उस वक्त चल रही परिस्थितियों के तथ्यों पर आधारित था । तदन्तर आयातों की अविच्छिन्न उच्च स्तर की परिस्थिति अनवरत जारी रही और अब तक आयात सितम्बर, 1998 के स्तर से भी कम कीमतों पर हो रहे हैं । जो कच्चे माल की लागत वृद्धि के लिए समायोजित किये गये थे ।

छ. फिर भी वास्तविक मूल्य स्तर जिस पर फिनाल आयात किया जा रहा है ने अक्तूबर, 1999 के बाद की अवधि में कुल वृद्धि दर्शाई है लेकिन वह बहुत ही अधिक भ्रामक है क्योंकि वह वृद्धि कच्चे माल और ईंधन की लागतों में असाधारण वृद्धि के कारण बाध्य हो कर की गई थी । फिनाल की कीमतें कच्चे माल की लागत में वृद्धि के साथ समायोजित मूल्य से कम है (सितम्बर, 1998 की कीमत और कच्चे माल की लागतों की तुलना करके परिकलित की गई) । लागतों की तुलना में यदि कीमतों पर विचार किया तो 1999-2000 और 2000-2001 में कीमतें सामान्यतया 1998 की दूसरी छःमाही में चल रही निम्नतम कीमतों से भी कम हैं । देश में फिनाल का आयात जिन कीमतों पर हुआ वह वर्ष 1998 की दूसरी छःमाही की कीमतों से भी कम है ।

ज. बैन्जीन, प्रोपिलीन और क्यूमिन आदि के अन्तर्वस्तुओं की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में वृद्धि ने घरेलू अन्तर्वस्तुओं और फिनाल की विनिर्माण की कीमतों में वृद्धि की है । 1999-2000 में एच सी एल को फिनाल विनिर्माण में हानि होती रही (रक्षोपाय शुल्क लागू होने के बावजूद) और जहां तक एच ओ सी एल का प्रश्न है उनके लाभांश बहुत ही कम थे । यहां तक की संवृद्धि लाभ भी रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के पश्चात् प्राप्त हुए । रक्षोपाय शुल्क की वापसी की स्थिति में अप्रैल-नवम्बर, 2000 में हुए न्यूनतम लाभ भी हानि में परिवर्तित हो जाएंगे ।

झ. फिनाल की क्षमता पर एक साथ सार्वभौमिक रूप से कच्चे तेल की 1999 की शुरुआत में 10 अमेरिकी डालर प्रति बैरल से वर्तमान स्तर की लगभग 30 अमेरिकी डालर प्रति बैरल की वृद्धि वास्तव में अप्रत्याशित थी । फिनाल की क्षमता पर उस वक्त सार्वभौमिक रूप से कच्चे माल और तेलों की कीमतों में परिणामिक आकस्मिक और अर्थवान वृद्धि के कारण महत्वपूर्ण नीचे स्तर की 'समायोजित लागत फिनाल

कीमतों पर एच ओ सी एल और एच सी एल की सितम्बर, 1998 से नवम्बर, 2000 तक के दौरान समायोजित लागत फिनाल कीमत क्रमशः 19% और 13% तक गिर गई ।

भारतीय बाजार का आकार और घरेलू फिनाल उत्पादन उद्योग का अनुवर्ती आकार दोनो विश्व के फिनाल उत्पादन करने वाले उद्योग के आकार से 2% से भी कम है । क्योंकि फिनाल का आयात स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है, कुछ भी हो उनका भारतीय फिनाल कीमतों पर कोई नियंत्रण नहीं है जो कि इस व्यापार में विश्व के मुख्य उद्यमियों द्वारा निश्चित किया जाता है ।

आयात बड़ी हुई ऋण अवधि पर किए जाते हैं, यह भी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति का कारण है ।

आयातों पर लंबी ऋण अवधि के परिणामस्वरूप घरेलू उत्पादकों को घरेलू बिक्री पर जल्दी अदायगी के लिए नकद छूट देनी पड़ती है या लंबी अवधि के ऋण का प्रस्ताव रखना पड़ता है ।

ट. समायोजन योजना का कार्यान्वयन समयानुसार में होने के बावजूद लागत कम करने की योजनाओं का प्रभाव, कच्चे माल और ईंधन की लागत बढ़ने से निष्प्रभावी हो गया जिससे समग्र रूप से लागत में वृद्धि हुई । जिन कीमतों पर आयात हो रहे हैं वह फिनाल के घरेलू विनिर्माताओं को अव्यवहार्य बना देगा ।

ठ. संचालन दक्षता में सुधारों के कारण अस्थिर लागतों में बचत की वसूली नहीं की जा सकी क्योंकि संचालन की दक्षताओं से प्राप्त प्रभावों को अन्तर्वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि ने निष्प्रभावित कर दिया । स्थिर लागत के क्षेत्र में भी हालांकि बाध्यताओं को दूर करने से उच्च क्षमताएं हुईं लेकिन लंबे समय तक वर्धित आयात के स्तर के कारण और फोर्स मैज्योर परिस्थितियों के कारण शुरू में वास्तव में उत्पादन स्तर में वृद्धि नहीं हुई । ऐसे भी उदाहरण हैं जिसके कारण एच सी एल को क्षति हुई जैसे जिन सार्वजनिक क्षेत्र की रिफाइनरियों जिन से वे आवश्यक कच्चा माल लेते थे, ने बिना पर्याप्त नोटिस के काम बंद कर दिया और तेल कम्पनियों ने सभी ऋणों और छूटों को वापिस ले लिया जिससे कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता को बढ़ाना पड़ा ।

मात्र लागत समायोजित आयात मूल्यों की तुलना में आयात मूल्य कम होने के द्वारा बाधित कमजोर वित्तीय प्रदर्शन के कारण बैंक ने अतिरिक्त कार्यकारी पूंजी सीमा की स्वीकृति में अनिच्छा दिखाई । वास्तव में अप्रैल, जून और अक्टूबर, 2000 के महीने में एच ओ सी एल को नकदी की समस्या के कारण बंद होना पड़ा जिसके कारण उनके उत्पादन वाल्यूम उनकी बड़ी हुई क्षमता स्तर की तुलना में इन महीनों में कम रहें ।

ड. अप्रैल, 1999 से नवम्बर, 2000 के बीच फिनाल ओर एसिटोन की बिक्री पर घरेलू उद्योग की कुल बकाया राशि, आयातकों द्वारा प्राप्त लंबी अवधियों के ऋण के कारण 36% तक बढ़ गई ।

ढ. लगातार वर्धित आयातों से उत्पन्न निराशाजनक परिस्थिति के कारण सक्षम, कुशल कर्मियों का फिनाल और एसिटोन उद्योग से पलायन जारी रहा ।

ण. भारतीय बाजार का आकार अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के आकार की तुलना में छोटा होने के कारण भारतीय आयात पार्सल "तत्काल आधार" पर संचालित किए जाते हैं। तत्कालीन कीमतों का रुख ज्यादातर अनुबंधित कीमतों से काफी कम होता है। इस कारण फिनाल की भारत में पहुंचने की सी आई एफ कीमतें विश्व के विकसित फिनाल उत्पादन करने वाले मुख्य क्षेत्रों में चल रही कीमतों से कम हैं। गिरती हुई कीमतों के दौर में घरेलू कीमतें संभावित माल की और बुकिंग रोकने के लिए भूमि पर उतराई के समय की कीमत की समतुल्यता के आधार पर निर्धारित की जाती है। अतः घरेलू कीमतों का रुख आयात की वास्तविक भूमि पर उतराई के समय की लागत से सदा कम होता है। यद्यपि ऐसी स्थिति में जहाँ आयात कीमतों में वृद्धि हो रही हो, घरेलू कीमतें संभावित या वास्तविक भूमि पर उतराई के समय की कीमतों के बराबर निर्धारित नहीं की जा सकती। यह इसलिए क्योंकि जिस माल का भंडार कम कीमतों पर आयात किया गया हो जब तक वह रहता है वह घरेलू कीमतें निर्धारित करता है। ये कीमतें भी आयात पहुंचने तक की वास्तविक कीमतों से कम होती है। इस प्रकार घरेलू उद्योग को तब तक क्षति होती है जब तक मूल्य यथोचित स्तर तक समायोजित न हो और स्थिर रहे।

त. कुछ पक्षों द्वारा यह भी कहा गया है कि विश्व स्तर पर फिनाल का अतिरिक्त उत्पादन, बिसफिनाल-ए (बी पी ए) की अतिरिक्त क्षमता द्वारा उपभोग कर लिया जायेगा जो अब विश्व के विभिन्न भागों में स्थापित किए जा चुके हैं। फिनाल का उपभोग वास्तव में बी पी ए (और अंतिम प्रयोगकर्ताओं) के उपभाग पर निर्भर होगा न कि बी पी ए की उत्पादन क्षमता पर। अतः बी पी ए की नई क्षमता वर्तमान उत्पादकों से बी पी ए का बाजार शेयर जल्द ही हथिया लेगी और बी पी ए के विनिर्माण के लिए फिनाल की आवश्यकता केवल बी पी ए की वास्तविक उत्पादन दर पर बढ़ेगी। बिसफिनाल ए क्षेत्र में फिनाल के उत्पादन के प्रभाव पर विचार करने के पश्चात् भी फिनाल की मांग में वृद्धि की दर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध कुछ एजेंसियों ने जैसे सी एम ए आई, केम रिसिटमस, फिनाल केमी तथा शैल ने 4% प्रति वर्ष से अधिक नहीं आंकी है।

थ. घरेलू फिनाल विनिर्माण उद्योग को गंभीर क्षति से बचाने के लिए और फिनाल की विश्वभर में अत्यधिक क्षमता के साथ-साथ कच्चे माल की लागतों में अर्थपूर्ण वृद्धि से उत्पन्न नितांत कठिन परिस्थिति में समायोजन हेतु सहायता करने के लिए उन्होंने फिनाल के आयात पर जुलाई, 2001 से और तीन वर्षों के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण जारी रखने का अनुरोध किया है।

च. जाँच परिणाम:-

मैंने मामले के रिकार्ड सभी इच्छुक पक्षों, जिनमें घरेलू उत्पादक, उपभोक्ता/आयातक और निर्यातक शामिल हैं, के द्वारा प्रस्तुत जवाबों को ध्यान से पढ़ा है। विभिन्न पक्षों द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों एवं उनसे उठने वाले मुद्दों को नीचे दिए गए जांच परिणामों में यथोचित स्थान पर डील किया गया है। तथापि मामले के गुणदोष पर चर्चा शुरू करने से पूर्व सीमा शुल्क टैरिफ (रक्षोपाय शुल्क की पहचान और निर्धारण) नियमावली 1997, के नियम 18 जिसे कि यहां एस जी डी नियमावली के रूप में संदर्भित किया गया है, से संबंधित आरंभिक मुद्दों पर चर्चा करना आवश्यक समझा गया है।

कुछ इच्छुक पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि एस जी डी नियमावली का नियम 18 उस स्थिति के साथ डील करता है जो रक्षोपाय शुल्क प्रवृत्त रहने के दौरान महानिदेशक रक्षोपाय कोई पुनरीक्षण करते हैं। पुनरीक्षण यह निर्धारित करने हेतु है कि क्या कथित शुल्क मूल रूप से मांगी गई अवधि के लिए जारी रहना चाहिए या इसे वापिस ले लिया जाए या उदारीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया जाना चाहिए? यह उस स्थिति का डील नहीं करता जहां महानिदेशक रक्षोपाय उस अवधि से आगे शुल्क बढ़ा सकते हैं। जिसके लिए मूल रूप से इसकी संस्तुति की गई थी। महानिदेशक रक्षोपाय शुल्क का अधिकार केवल यह परीक्षण करने का है कि क्या दो वर्ष की अवधि, जिसके लिए फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया गया था, को कम किया जा सकता है या नहीं और अधिरोपण की इस अवधि का विस्तार करने का अधिकार महानिदेशक के पास नहीं है। अधिरोपण की अवधि का विस्तार दोबारा शुल्क लगाने के बराबर है जो एक नई जांच शुरू करने के बाद होती है।

यह तर्क दिया गया है कि रक्षोपाय पर समझौते के अनुबन्ध -7 की शर्त है कि रक्षोपाय उपाय के पुनरीक्षण को एक उपाय के संदर्भ में अपेक्षित है जो कि तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए लगाया गया है। उस मामले में जहां, उपाय कम अवधि के लिए लागू किया गया है, जैसा कि वर्तमान मामले में हैं, रक्षोपाय उपायों को लागू करने की अवधि का विस्तार, उत्पाद के आयात पर उपायों के विरुद्ध लागू करने के बराबर है जो कि तब तक नहीं किया जा सकता जब तक कि प्रथम अधिरोपण के पश्चात् दो वर्ष की अवधि समाप्त नहीं हो जाती। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि रक्षोपाय शुल्क नियमावली का नियम 18 उस स्थिति के साथ डील करता है जहां महानिदेशक उस अवधि के दौरान पुनरीक्षण करते हैं जिस अवधि में रक्षोपाय शुल्क लागू हों। यह पुनरीक्षण यह निर्धारित करने हेतु है कि जिस अवधि हेतु इसकी मांग की गई थी उस अवधि में यह जारी रहे या इसे वापिस लिया जाए या उदारीकरण की गति को बढ़ाया जाए। यह उस स्थिति के साथ डील नहीं करता जहां महानिदेशक उस अवधि से आगे शुल्क का विस्तार कर सकते हैं जिसके लिए मूल रूप से इसकी संस्तुति की गई थी। इसके अलावा महानिदेशक ने घरेलू उद्योगों की स्थिति का निरीक्षण किया है और इस सकारात्मक नतीजे पर पहुंचे हैं कि गंभीर क्षति से बचाने एवं समायोजन सुगम बनाने हेतु दो वर्ष की आवश्यकता है। फलतः महानिदेशक के पास केवल यह परीक्षण करने का अधिकार है कि क्या दो वर्ष की कथित अवधि को कम किया जा सकता है या नहीं। महानिदेशक के पास अधिरोपण की इस अवधि को बढ़ाने का कोई अधिकारी नहीं है।

यह एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण है और रक्षोपाय विधि की योजना के संदर्भ में इसके परीक्षण की आवश्यकता है जैसा कि सीमाशुल्क टैरिफ 1975 और रक्षोपाय नियमावली के अधीन देखा गया है जो कि रक्षोपाय पर समझौते के प्रावधानों को प्रतिबिम्बित करता है

रक्षोपाय पर समझौता के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 1 में उल्लिखित है कि :-

एक सदस्य रक्षोपाय उपाय केवल इतनी समयावधि के लिए लागू करेंगे जो कि गंभीर क्षति को रोकने या इस हेतु उपाय के लिए और समायोजन सुगम बनाने हेतु आवश्यक हो। यह अवधि चार वर्षों से अधिक नहीं होगी जब तक कि इसे पैराग्राफ 2 के अधीन बढ़ाया नहीं जाता है।

अनुच्छेद 7 का पैराग्राफ 2 इस प्रकार है :-

पैराग्राफ 1 में वर्णित अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है बशर्ते कि अनुच्छेद 2,3,4 और 5 में बनाई गई प्रक्रिया के साथ पुष्टि में आयातक सदस्य के सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्धारित किया है कि रक्षोपाय शुल्क गंभीर क्षति को रोकने या इसके उपाय हेतु जारी रखने आवश्यक है और ऐसे साक्ष्य हैं कि उद्योग समायोजित हो रहे हैं और यह है कि अनुच्छेद 8 एवं 12 के संगत प्रावधानों का पालन होता है ।

अनुच्छेद 7 का पैराग्राफ 1 के अंतिम वाक्य का सहज पूर्णरूपेण यह स्पष्ट करता है कि रक्षोपाय उपायों के शुरुआती अधिरोपण की अवधि चार वर्षों से अधिक नहीं होगी और यह कि इस अवधि को पैराग्राफ 2 के अधीन विस्तारित किया जा सकता है । इसी प्रकार पैराग्राफ 2 स्पष्ट करता है कि पैराग्राफ 1 के अधीन अवधि को कुछ शर्तें पूरी करने के पश्चात् ही बढ़ाया जा सकता है । पैराग्राफ 1 में विशेष रूप में अपेक्षित है कि रक्षोपाय उपायों के शुरुआती लागू करने की अवधि 4 वर्षों से अधिक न हो अर्थात् यह कोई भी वह अवधि हो सकती है जो चार साल या कम हो और चार वर्ष तक की इस अवधि को पैराग्राफ 2 के प्रावधानों के अनुसरण में विस्तारित किया जा सकता है । इस प्रकार अनुच्छेद 7 में ऐसा अपेक्षित नहीं है कि आगे बढ़ाये जाने के लिए ग्राह्य होने हेतु रक्षोपाय शुल्क लागू होने की अवधि एक निश्चित अवधि हो ।

आगे अनुच्छेद 7 का पैराग्राफ 4 निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है

उस स्थिति के समायोजन को सुगम बनाने हेतु, जैसा कि अनुच्छेद 12 के पैराग्राफ 1 के अधीन अधिसूचित है जहां रक्षोपाय उपायों की अनुमानित अवधि एक वर्ष से ऊपर है, इसको लागू करने वाले सदस्य इसके लागू होने के अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर इसे लगातार उदार करेंगे । यदि उपायों की अवधि तीन वर्ष से अधिक है, तो इस प्रकार के उपाय लागू करने वाले सदस्य स्थिति का पुनरीक्षण उपाय की मध्यावधि से पहले करेंगे और यदि आवश्यक हो तो इसे वापिस ले सकते हैं या उदारीकरण की गति को बढ़ाएंगे । पैराग्राफ 2 के अधीन विस्तारित उपाय शुरुआती अवधि की समाप्ति से अधिक प्रतिबंधात्मक नहीं होगा और यह उदार होते रहना चाहिए ।

यह पैराग्राफ रक्षोपाय उपायों को उदार बनाने की आवश्यकता पर रोशनी डालता है, यदि रक्षोपाय उपायों को लागू करने की अवधि एक वर्ष से अधिक है । यह मध्यावधि पुनरीक्षण को भी आवश्यक बनाता है यदि रक्षोपाय उपायों को लागू करने की अवधि तीन वर्ष से अधिक है । इस पुनरीक्षण का उद्देश्य यह विचार करना है कि क्या उदारीकरण की गति बढ़ाई जाए या उपायों को वापिस ले लिया जाए । पैराग्राफ 4 का अंतिम वाक्य उदारीकरण की प्रक्रिया को सुनिश्चित करने पर विचार करता है उन मामलों में जहां पैराग्राफ 2 के अधीन रक्षोपाय उपायों को बढ़ाया जाता है ।

रक्षोपाय पर समझौते के अनुच्छेद 7 के उपरोक्त प्रावधानों को रक्षोपाय शुल्क नियमावली के नियम 18 के साथ समाविष्ट किया गया है जिन्हें नीचे पुनर्प्रस्तुत किया गया है ।

(1) समय-समय पर महानिदेशक, रक्षोपाय शुल्क के जारी अधिरोपण की आवश्यकता का पुनरीक्षण करेंगे और यदि उन्हें प्राप्त सूचना के आधार पर वे संतुष्ट हैं तो, संस्तुति करेंगे कि :-

(i) गंभीर क्षति को रोकने या इसके उपाय हेतु रक्षोपाय शुल्क आवश्यक है और उद्योग सकारात्मक रूप में समायोजित हो रहे हैं, वे केन्द्र सरकार को शुल्क के जारी अधिरोपण हेतु संस्तुति भेज सकते हैं।

(ii) इस प्रकार का जारी अधिरोपण न्यायोचित नहीं है तो इसके वापस लेने हेतु संस्तुति कर सकते हैं।

बशर्ते कि जहां रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण की अवधि तीन वर्ष से अधिक हो तो इस प्रकार के अधिरोपण के मध्यावधि से पूर्व स्थिति का पुनरीक्षण करेंगे और यदि उचित हो, तो इस प्रकार के

रक्षोपाय शुल्क को वापस लेने या शुल्क के उदारीकरण में वृद्धि हेतु संस्तुति देंगे।

2. उपनियम (1) के अधीन आरंभ किया गया कोई भी पुनरीक्षण इस पुनरीक्षण के शुरू होने की तिथि से 8 मास के अंदर या इतनी विस्तारित अवधि में, जितनी केन्द्र सरकार अनुमति दे, के अन्दर पूर्ण किया जाएगा।

3. नियम 5,6,7, और 11 के प्रावधान पुनरीक्षण के मामले में आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

नियम 18 में अपेक्षित है कि महानिदेशक रक्षोपाय पर समझौते के अनुच्छेद 7 के पैराग्राफ 2 और पैराग्राफ 4 दोनों के संगत प्रावधानों को समाविष्ट करके रक्षोपाय शुल्क के जारी अधिरोपण की आवश्यकता का पुनरीक्षण समय-समय पर करेंगे। नियम 18 के प्रावधान केवल अधिरोपण की शुरुआती अवधि में महानिदेशक के अधिकारों को सीमित नहीं करते। इसके विपरीत ये महानिदेशक को अधिकार प्रदान करते हैं और शुल्क के जारी अधिरोपण के लिए संस्तुति करने की अपेक्षा उनसे की जाती है यदि

(i) गंभीर क्षति को रोकने या इसके उपाय हेतु यह आवश्यक है और

(ii) ऐसे साक्ष्य है कि उद्योग सकारात्मक रूप में समायोजित हो रहे हैं। उपरोक्त व्याख्या नियम 16 की भाषा से भी समर्थित होती है जहां कि उपनियम 2 के प्रथम प्रावधान को निम्नानुसार पढ़ा जा सकता है। बशर्ते कि यदि केन्द्र सरकार की यह राय है कि इस प्रकार की क्षति या आशंका के साथ समायोजन के लिए घरेलू उद्योग ने उपाय किए हैं और यह आवश्यक है कि रक्षोपाय शुरू अधिरोपित होने जारी रहने चाहिए वह इस प्रकार के अधिरोपण के अवधि को विस्तारित कर सकती है।

अभिव्यक्ति के इस प्रावधान में “रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित होना जारी रहना चाहिए वह इस प्रकार अवधि को विस्तारित कर सकती हैं” को अधिरोपण की शुरुआती अवधि से आगे रक्षोपाय शुल्क के विस्तार के संबंध में स्पष्टतया प्रयुक्त किया गया है ।

उपरोक्त चर्चा के अनुसार इस तर्क में कोई दम नहीं है कि महानिदेशक के पास केवल शुरुआती अधिरोपण की अवधि को कम किया जाए” के परीक्षण का अधिकार है और महानिदेशक के पास शुरुआती अधिरोपण की इस अवधि को विस्तारित करने की संस्तुति करने का अधिकार नहीं है ।

रक्षोपाय शुल्क नियमावनी के नियम 18 के अनुसार रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण जारी रहने हेतु जो आवश्यक अपेक्षा पूरी की जाती है वह यह है कि गंभीर क्षति को रोकने या इसके उपाय होने चाहिए और साक्ष्य है कि उद्योग सकारात्मक रूप में समायोजित हो रहे हैं और यदि इस प्रकार के शुल्क का जारी अधिरोपण न्यायोचित न हो तो इसको वापिस लिए जाने संबंधी संस्तुति करने की आवश्यकता है । विधि में रक्षोपाय शुल्क के पुनरीक्षण हेतु स्वयं एक व्यवस्था है यह और एक स्तर निर्धारित करता है जिसके द्वारा इस प्रभार के जारी अधिरोपण की आवश्यकता को परीक्षण करने की आवश्यकता है । यदि ये शर्तें आपस में मेल खाती हैं तो रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण को जारी रखना न्यायोचित हो जाता है ।

जहां तक मामले के गुणदोष का संबंध है, वर्तमान मामले में यह पाया गया था कि भारत में फिनाल का आयात 1994-95 में 6664 मी० टन से 1997-98 में 15312 मी० टन और 1998-99 के प्रथम नौ महीनों (अप्रैल से दिसम्बर) में 24550 मी० टन तक बढ़ा । फिनाल का वर्धित आयात फिनाल के घरेलू उत्पादन में कमी का कारण बना जिसने कि 1996-97 की तुलना में 1997-98 में लगभग 16.1% की वृद्धि दर्ज की । 1997-98 की तुलना में 1998-99 में गिरावट 6.69% थी । इसी प्रकार 1997-98 की तुलना में 1998-99 (अप्रैल- दिसम्बर) क्षमता उपयोगिता में 10.31% के बिन्दु तक हानि उठाई । 1997-98 की तुलना में 1998-99 (अप्रैल- दिसम्बर) में संगत अवधि के दौरान स्पष्ट घरेलू खपत में 25.1% की वृद्धि की तुलना में घरेलू बिक्री में 3.38% की थोड़ी वृद्धि दर्ज की । यह थोड़ी सी वृद्धि उनके औसत बिक्री मूल्यों में अंधाधुंध कमी के कारण प्राप्त की गई जो कि जनवरी-मार्च 1998 में 37/-रु० किलों की तुलना में, दिसम्बर, 1998 में 28 रु० प्रति किलों तक कम की गई । उन्हें फिनाल के सूची मूल्य कम करने पड़े और अपने उपभोक्ताओं को पूर्णतया: आयात की ओर मुखातिब होने से बचाने हेतु विभिन्न अतिरिक्त छूट प्रदान करनी पड़ी । कुल बिक्री प्राप्ति में गिरावट में घरेलू उद्योग के लाभ पर गंभीर प्रभाव पड़ा और दोनों एच ओ सी एल और एच सी एल को अपने फिनाल संचालन में हानि होनी शुरू हो गई । दिसम्बर, 1998 में एच ओ सी एल को (गोपनीय) प्रति मी० टन और एच सी एल को रु० (गोपनीय) प्रति मी० टन की हानि उठानी पड़ी जिससे कि उनके शेयर मूल्य भी गिर गए । आगे यह पाया गया कि घरेलू उद्योग उनके अंतशेष में कुछ वृद्धि, रोजगार की हानि एवं उत्पादकता में हानि के कारण भी प्रभावित हुए ।

इस प्रकार घरेलू उद्योगों ने 1998-99 के प्रथम तीन तिमाहियों में फिनाल संचालन की विभिन्न गंभीर अवनत अवस्थाएं देखी हैं ।

जहाँ तक सकारात्मक समायोजन करने के लिए घरेलू उद्योग की भूमिका का संबंध है, यह महसूस किया गया था कि एच सी एल में विद्यमान सुविधाएं उदारीकरण एवं एम आर टी पी के समय में बनाई गई थी जो कि स्तर की अर्थव्यवस्था की कमी के कारण उच्च निर्धारित लागत में परिवर्तित हो गई। तथापि घरेलू उत्पादकों ने अपनी तकनीकों के उन्नयन और अपनी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य के साथ अपनी विनिर्माण सुविधाओं की अड़चनों को दूर किया और कार्यात्मक लागत कम की। उन्होंने कोजेनरेशन रूट द्वारा कैप्टिव विद्युत उत्पादन सुविधा जो कि 1999 में शुरू की गई थी, लगाकर विद्युत लागत को कम करने के लिए कदम उठाए। लागत कम करने के अन्य उपायों में फीडस्टाक की गुणवत्ता में सुधार, प्रोपिलीन की वर्धित उपलब्धता और क्यूमिन के उत्पादन हेतु आर्ट जियालाईट तकनीक की कला आदि में सुधार शामिल है।

गंभीर क्षति की लगातार जारी आशंका

भारत में फिनाल का आयात 1998-99 में 26670 मी०टन था। 30 जून, 1999 को 22% यथामूल्य की दर से फिनाल पर अधिरोपित रक्षोपाय शुल्क के बावजूद यह निरंतर जारी रहा और 1999-2000 में 28992 मी०टन तक बढ़ा (डी जी सी आई एस आंकड़ों के अनुसार आयात 29302 मी०टन था, जो कि 28992 मी०टन से थोड़ा सा ज्यादा है)। आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराई सूचना के अनुसार मध्य दिसम्बर, 2000 तक फिनाल का आयात 18247 मी०टन सूचित किया गया जो कि वार्षिक आधार पर 25760 मी०टन के बराबर आता है। आवेदकों द्वारा उपलब्ध कराए गए आयात आंकड़ों की प्रमाणिकता के बारे में कुछ पक्षों द्वारा संदेह व्यक्त किया गया था विशेषकर 2000-01 की अवधि के दौरान आयात आंकड़ों के बारे में। घरेलू आवेदकों ने इस बारे में प्रस्तुत किया है कि वर्ष 1999-2000 तक के आंकड़ों डी जी सी आई एस कलकत्ता के पास उपलब्ध है। 2000-2001 के लिए डी जी सी आई एस आंकड़ों के प्रकाशन में समय की देरी के कारण उन्होंने बाजार सूचना स्रोत पर आधारित आंकड़ों को लिया। जहां तक 2000-2001 के आंकड़ों का संबंध है आवेदकों ने जहाज के नाम, पहुंचने की तिथि, मात्रा आयातक का नाम और आयात मूल्य के साथ सर्वेक्षक/बीमा रिपोर्ट दर्शाते हुए आयात के आँकड़े उपलब्ध कराए हैं। विवरणों के सत्यापन के पश्चात यह पाया गया है कि वर्ष 2000-2001 के दौरान 26442.992 मी०टन फिनाल का मात्रा का आयात किया गया है जिसमें से 12510.594 मी०टन की मात्रा का आयात नवम्बर, 2000 तक 8652.173 मी०टन दिसम्बर, 2000 में किया गया जो कि अप्रैल, दिसम्बर के दौरान 21162.767 मी०टन बैठता है। नीचे सारिणी आयात के विवरण दर्शाती है :-

सारिणी-।

वर्ष	आयात	घरेलू उत्पादन	आयात मी.टन में	
			घरेलू उत्पादन के % के रूप में	
			आयात	
1997-98		15700	69281	22.66
1998-99		25213	66210	38.08
1999-00		29302	69961	41.88
2000-01		21163	52278	40.48
(अप्रैल, दिसम्बर)				

कुछ इच्छुक पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि नियम 18 के उपनियम (3) की शर्त है कि नियम 5,6,7 और 11 पुनरीक्षण के मामले में आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे और नियम 5 में अपेक्षित है कि वर्धित आयात के कारण गंभीर क्षति हुई हो या इसकी आशंका हो और चूंकि आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है इसलिए रक्षोपाय संरक्षण का कोई मामला नहीं बनता ।

यह कहा गया है कि रक्षोपाय शुल्क की नियमावली के नियम 5 में अपेक्षित है कि कोई भी जांच शुरू करने हेतु महानिदेशक को आयात में वृद्धि खोजनी पड़ेगी । विशेषकर वाक्यांश 5(3) में अपेक्षित है कि उप नियम (1) के अधीन किसी भी आवेदन पर महानिदेशक तब तक जांच शुरू नहीं करेंगे, जब तक आवेदन में उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की प्रमाणिकता और सत्यता का परीक्षण न कर लें और जब तक स्वयं संतुष्ट न हों कि वर्धित आयात, गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका से संबंधित पर्याप्त सबूत हैं और वर्धित आयात और आरोपी गंभीर क्षति की आशंका में आकस्मिक संबंध है । घरेलू उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चलता है कि आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है और घरेलू उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना से पता चलता है कि घरेलू उत्पादन बाजार मांग अवस्था के साथ अधिक है । डब्ल्यू टी ओ न्याय विधि के अधीन यदि आयात में वृद्धि वास्तव में है तो यह एंड प्वाइंट टू एंड प्वाइंट तुलना एवं उस अवधि में मध्यवर्ती प्रवृत्ति के विश्लेषण दोनों से साक्ष्य मिलने चाहिए एवं समय के साथ विश्लेषण में आपस में मध्यवर्ती प्रवृत्ति होनी चाहिए । चूंकि आयात में कोई वृद्धि नहीं हुई है तो रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के लिए कोई आधार नहीं है ।

इस संबंध में यह महसूस किया जाता है कि विधि की अपेक्षा है कि नियम 5,6,7 और 11 आवश्यक परिवर्तन सहित (बल देकर) लागू किए जाने हैं । इस तथ्य के बावजूद कि 1999-2000 में वास्तविक आयात 29302 मी०टन (डी जी सी आई एस आंकड़े) था जो कि हाल की अवधि के दौरान सबसे अधिक था, 1999-2000 एवं 2001 की अवधि के दौरान आयात की मात्रा पर इस तथ्य को ध्यान में रखकर विचार किया जाना है कि इस अवधि के दौरान फिनाल आयात पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य क्षतिकारक गंभीर आयात से घरेलू उत्पादकों को राहत प्रदान करना था । इसलिए पहले से ही लागू रक्षोपाय शुल्क के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए आयात की मात्रा पर विचार करना है कि यदि रक्षोपाय उपाय वापिस ले लिए जाते हैं तो क्या आयात घरेलू उद्योगों को गंभीर क्षति पहुंचाना जारी रखेगा ।

इस अवधि के दौरान घरेलू उत्पादकों ने 1997-98 में 69281 मी०टन 1999-2000 में 69961 मी०टन और अप्रैल-नवम्बर, 2000 में 45848 मी०टन का उत्पादन किया । उनकी कथित अवधि के दौरान वार्षिक आधार पर उत्पादक क्षमता 66500. 75000, 77000 और 83000 (वार्षिक) थी । इस प्रकार उन्होंने 1997-98 में

104.18%, 1998-99 में 88.28% 1999-2000 में 90.86% और 2000-01 में प्रथम आठ महीनों में 82.86% क्षमता उपयोगिता प्राप्त की ।

कुछ इच्छुक पक्षों ने प्रस्तुत किया है कि रक्षोपाय शुल्क के भुगतान के पश्चात् भी यदि भारत में आयात उच्च कीमतों पर हो रहा था, तो यह केवल यही दर्शाता है कि फिनाल की मांग बढ़ रही है और घरेलू उद्योग इसे पूरा नहीं कर सके और वर्धित मांग को पूरा करने में यह घरेलू उद्योग की अपनी अक्षमता के कारण ही भारत में आयात हो रहा है । इस संबंध में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि आयात इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि घरेलू खपत में वृद्धि हो रही है जबकि घरेलू उत्पादन उसी अनुपात में नहीं बढ़ रहा है जिसके कारण घरेलू मांग और आपूर्ति को दूरी को भरने हेतु वर्धित आयात की परिणति हो रही है । उन्होंने यह भी तर्क दिया है कि पूर्व केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर विभाग, भारत सरकार द्वारा स्थापित कार्यकारी समूह के अनुसार नौवीं पंचवर्षीय योजना हेतु फिनाल की अनुमानित मांग 2001-02 तक 1,45,000 मी०टन प्रतिवर्ष तथा 2006-07 तक 2,49,000 टन प्रतिवर्ष है । फिनाल की खपत 1997-98 के पश्चात् निरंतर बढ़ रही है । वास्तव में मांग और अधिक स्तर तक होगी यदि फिनाल की कीमतें तर्क संगत हो जिससे कि अनुप्रवाह उत्पादक अपनी पूर्ण क्षमताओं का उपयोग कर सकें जो कि वर्तमान में संभव नहीं है क्योंकि उनके अंतिम उत्पाद कम मूल्यों पर आयात हो रहे हैं । भारतीय बाजार में फिनाल की वर्धित मांग और घरेलू उत्पादन में वृद्धि न होने के कारण उपभोक्ताओं को रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के कारण उच्च आयात शुल्क का भुगतान करके उच्च गुणवत्ता का फिनाल आयात करना पड़ रहा है । तथापि इससे घरेलू विनिर्माताओं को अतिरिक्त उत्पादन हेतु अपनी अक्षमता में सुधार किए बगैर या विनिर्माण की लागत में कमी करने के बगैर अपने मूल्य बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपलब्ध कराई । अपना सम्पूर्ण माल विक्रय करने के पश्चात् भी जब घरेलू विनिर्माता बाजार की मांग को पूरा न कर सकें तो वे वर्धित आयात के बारे में शिकायत नहीं कर सकते और रक्षोपाय शुल्क के रूप में जारी सुरक्षा की मांग नहीं कर सकते जो कि केवल उनकी बिक्री मूल्य को बढ़ाने के सुरक्षा के रूप में और अदेय लाभ प्राप्त करने हेतु प्रयुक्त किया जा रहा है ।

इच्छुक पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए इन कथनों की जाँच डिपार्टमेंट आफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स (रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय) द्वारा कराई गई थी । मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि फिनाल की अनुमानित मांग हेतु हाल ही में केमिकल्स विभाग द्वारा कोई कार्यकारी ग्रुप गठित नहीं किया गया है । तथापि अध्याय x के अधीन पेट्रोकेमिकल्स पर कार्यकारी ग्रुप ने 'फीडस्टाक एंड बिल्डिंग ब्लॉक' पर अपनी रिपोर्ट में 2000-2001 और 2001-2002 वर्षों के लिए 1,33,000 मी०टन और 229,000 मी०टन के रूप में फिनाल की अनुमानित मांग लिखी है । मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बेजिन की खपत के आंकड़ों पर आधारित आकलन तीन वर्ष पूर्व के है । तब से अब तक बाजार की वास्तविकता में पर्याप्त परिवर्तन हो गया है । मंत्रालय के अनुसार, देश में फिनाल की वास्तविक खपत 1997-98 , 1998-99 और 1999-2000 वर्षों में क्रमशः 78,093 मी०टन, 88,800 मी० टन और 91,000 मी०टन (अनुमानित) थी । मंत्रालय

द्वारा यह भी कहा गया है कि 2001-2002 में देश में फिनाल की वास्तविक मांग आकलनों से पर्याप्त रूप में भिन्न हो सकती है ।

तथापि, यहां आपूर्ति -मांग के बीच एक दूरी है जिसके बारे में भारत में आने वाले फिनाल के आयात की मात्रा के संदर्भ में विचार करना जरूरी है । घरेलू बाजार में फिनाल की स्पष्ट घरेलू खपत (घरेलू बिक्री + आयात) 1998-99 में 90923 मी०टन थी जो 1999-2000 में 99440 मी०टन तक बढ़ गई और अप्रैल- नवम्बर, 2000 की अवधि में 60101 मी०टन तक पहुंच गई । यद्यपि आवेदकों ने आयातित फिनाल के अंत शेष और शुरुआती स्टॉक के आधार पर 1998-99 में 92073 मी०टन, 1999-2000 में 95598 मी०टन और 2000-2001 में 64440 मी०टन की कुल घरेलू खपत का अनुमान लगाया है । प्रशासनिक मंत्रालय ने 1997-98 में 78093 मी०टन, 1998-99 में 88,800 मी०टन और 1999-2000 में 91000 मी०टन खपत के बारे में रिपोर्ट दी है । जबकि मंत्रालय ने 99000 मी०टन खपत के आंकड़े उपलब्ध कराए हैं, स्पष्ट घरेलू खपत 1999-2000 में 99440 मी०टन बैठती है । शुरुआती और अंतिम स्टॉक को ध्यान में रखते हुए आवेदकों द्वारा प्रस्तुत 95598 मी०टन के कुछ घरेलू खपत के आंकड़े अधिक प्रतिनिधिक प्रतीत होते हैं । इस प्रकार 1999-2000 में 69991 मी०टन और 2000-2001 में 45848 मी०टन के घरेलू उत्पादन की तुलना में कुल घरेलू खपत 1999-2000 में 95598 और अप्रैल- नवम्बर, 2000 में 64440 मी०टन थी ।

नीचे सारिणी घरेलू उत्पादन, क्षमता, आयात, बिक्री और घरेलू खपत के विवरण प्रस्तुत करती है:-

वर्ष	घरेलू क्षमता	घरेलू उत्पादन	क्षमता उपयोगिता	घरेलू बिक्री	आयात	घरेलू खपत
1998-99	75000	66210	88.28	65710	25213	92073
1999-2000	77000	69961	90.86	70138	29302	95598
2000-2001	55332	45848	82.86	46363	12510	64440

(अप्रैल-नवम्बर)

इस प्रकार 1999-2000 में आपूर्ति और मांग में (9558-69961) 25637 मी०टन का अंतर था इसमें वह भी शामिल है जो कि निर्यात उत्पादन में प्रयोग हेतु अपेक्षित था जिसका कि लगभग 13500 मी०टन प्रतिवर्ष होना अनुमानित है । इसलिए ऐसे साक्ष्य हैं कि घरेलू मांग को पूरा करने हेतु फिनाल की कुछ मात्रा को आयात किया जाना आवश्यक था । आवेदकों ने घरेलू मांग को पूरा करने हेतु घरेलू उत्पादकों के शुरुआती स्टॉक और अंतिम स्टॉक एवं आयातित फिनाल दोनों को ध्यान में रखकर आयातित फिनाल की खपत को निकाला है । उनके अनुसार 1999-2000 के दौरान आयातित फिनाल की खपत 25453 मी०टन थी ।

यद्यपि यह महसूस किया जाता है कि 1999-2000 में 25453 मी०टन आयातित फिनाल की खपत के विरुद्ध उस वर्ष के दौरान कुल आयात 29302 मी०टन था जिसके कारण वर्ष 1998-99 के

अंत में आयातित माल का भंडार 3800 मी०टन से 1999-2000 के अंत तक 7339 मी०टन तक बढ़ना शुरू हो गया । इस बढ़ते हुए अंतशेष का अर्थ है कि 1999-2000 में मांग से अधिक लगभग 3500 मी०टन फिनाल आयात किया गया जो कि कुल आयात के 12% के लगभग है । 2000-2001 (अप्रैल-नवम्बर) में अप्रैल ,2000 में 7339 मी०टन से नवम्बर, 2000 के अंत तक 2000 तक आयातित फिनाल के भंडारण में समाप्ति के साथ नवम्बर और दिसम्बर, 2000 में काफी बड़ी मात्रा में फिनाल आयात किया गया है । अक्तूबर, 2000 तक 1419 मी०टन की औसत के विपरीत नवम्बर, 2000 में फिनाल का आयात 2550 मी०टन और दिसम्बर, 2000 में 8652 मी०टन था ।

तथापि घरेलू उत्पादकों ने जितनी मात्रा में फिनाल का उत्पादन किया उसे विक्रय किया जिसका कि इस तथ्य से मिलता है कि घरेलू उत्पादकों ने 1999-2000 में 70145 मी०टन और 2000-2001 (अप्रैल- नवम्बर) में 47465 मी०टन फिनाल बेचा । यह रक्षोपाय शुल्क के अधिरोपण के कारण संभव हो सका जिसने घरेलू उत्पादकों को उनके द्वारा विनिर्मित माल के बिक्री करने में सहायता प्रदान की ।

फिनाल का आयात जो कि 1998-99 में गिरती सी आई एफ कीमतों पर हो रहा था वह वित्तीय वर्ष 1999-2000 की अवधि के पूर्व अमेरिकी डालर 400-425 के बीच की कीमतों पर होता रहा । तथापि नवम्बर, 1999 से आगे आयातित फिनाल के सी आई एफ मूल्यों में बढ़ने की प्रवृत्ति दर्शानी शुरू की जैसा कि सारिणी में दर्शाया गया है:-

सारिणी

अवधि (अमेरिकी डालर)	मूल्य प्रति मी०टन
नवम्बर, 1999	575
दिसम्बर, 1999	625
जनवरी, 2000	580
फरवरी, 2000	580
मार्च, 2000	580
अप्रैल, 2000	600
मई, 2000	610
जून, 2000	625
जुलाई, 2000	645
अगस्त, 2000	625
सितम्बर, 2000	635

अक्तूबर, 2000	655
नवम्बर, 2000	645
दिसम्बर, 2000	610

कुछ पक्षों द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आयातित फिनाल के सी आई एफ मूल्यों में वृद्धि के पीछे घरेलू उत्पादक आगे रक्षोपाय शुल्क की सुरक्षा के पात्र नहीं है । यद्यपि कच्चे माल की कीमतों आदि में वृद्धि के परिणामस्वरूप उत्पादन की लागत में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, फिनाल की सी आई एफ कीमतों में वृद्धि को इसके समुचित परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है । यह विचार कच्चा भी आवश्यक है कि फिनाल के उत्पादन की लागत में वृद्धि ने घरेलू उत्पादकों पर और आयातित फिनाल के सी आई एफ मूल्यों को प्रभावित किया है और क्या आयातित मूल्य इस वृद्धि के लिए पूर्ण जिम्मेदार है या घरेलू रूप में उत्पादित फिनाल के मूल्य कम करने चाहिए ।

फिनाल के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले मुख्य कच्चे माल बेन्जिन और प्रोपिलीन है । 1999 के पूर्व में कच्चे तेल की कीमतों में लगभग 10 अमेरिकी डालर प्रति बैरल से और वर्ष 2000 के द्वितीयार्ध में 30 अमेरिकी डालर प्रति बैरल तक की वृद्धि ने भी इन कच्चे माल की कीमतों पर अपना प्रभाव छोड़ा है 1998-99 के बाद के छःमाही में अंतर्राष्ट्रीय बेन्जिन के मूल्य 200-220 अमेरिकी डालर प्रति मी०टन के बीच थे जो कि उसके बाद बढ़ने शुरू हुए और वर्ष, 2000 के द्वितीयार्ध में 400-418 अमेरिकी डालर प्रति मी०टन के बीच में थे । उसी प्रकार प्रोपिलीन के मूल्य, जो कि 1998-99 के अर्द्ध में और मई, 1999 तक 240 से 255 अमेरिकी डालर के बीच थे, में भी वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी तथा वर्ष, 2000 के द्वितीयार्ध में 400 से 470 अमेरिकी डालर प्रति मी०टन तक बढ़ गए । इस प्रकार बेन्जिन के मूल्य लगभग 95% और प्रोपिलीन के मूल्य लगभग 75% तक बढ़े । मूल कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि की तुलना में फिनाल के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य, जो कि 400 से 435 अमेरिकी डालर प्रति मी०टन के बीच थे, वर्ष 2000 के द्वितीयार्ध में लगभग 630 अमेरिकी डालर प्रति मी०टन की औसत से बढ़े अर्थात् लगभग केवल 50-55% की वृद्धि हुई ।

इस संबंध में यह विचार करना आवश्यक है कि बहुत ही थोड़े समय में विश्व स्तर पर फिनाल की क्षमता 1.2 लाख टन प्रतिवर्ष से ऊपर बढ़ गई है । नई क्षमताओं में अमेरिका में फिनालकेमी (4,00,000 टन प्रतिवर्ष) अमेरिका में एरिस्टेक (2,00,000 टन प्रतिवर्ष) अमेरिका में शैल (2,00,000 टन प्रतिवर्ष) और ताईवान में बारमासा (2,00,000 टन प्रतिवर्ष) के अलावा सिंगापुर में मित्सुई 2,00,000 टन प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ) क्रियान्वयन की एक अग्रिम श्रेणी होने के कारण है । प्रतिशत में इसका अर्थ है वर्तमान विश्व स्तर पर फिनाल की मांग से करीब 20% की क्षमता की वृद्धि । इसके परिणामस्वरूप किंचित वृद्धि हुई । विनिर्माण की लागत में वृद्धि से फिनाल की कीमतों में वृद्धि ।

यहाँ पर यह ध्यान दिया जाए कि ज्यादातर केमिकल/पेट्रोकेमिकल उद्योग घरेलू बाजार में आयातित माल की भूमि पर उतराई के समय की कीमतों के समान कीमतों पर अपना उत्पादन बेचते हैं। इसलिए फिनाल के घरेलू उत्पादकों को भी अपने कच्चे माल की खरीद और फिनाल की ब्रिकी भूमि पर उतराई के समय की कीमतों के बराबर करनी पड़ती है। इस विषय में घरेलू उत्पादकों ने कहा है कि बैन्जीन और प्रोपीलीन की कीमतों में वृद्धि के लिए बैन्जीन और प्रोपिलीन के रूप में फिनाल की लागत के घटक को समायोजित करके 1998-99 की दूसरी छःमाही में लगभग 203-214 अमरीकी डालर प्रति मी०टन से 2000 की दूसरी छःमाही में 384-414 अमरीकी डालर प्रति मी०टन तक बढ़ी अर्थात् लगभग 90% की वृद्धि। एच ओ सी एल दरकदार एल पी जी से प्रोपिलीन पृथक करता है। सितम्बर, 1998 से नवम्बर, 2000 तक के दौरान एच ओ सी एल की प्रापण कीमतें 84% तक बढ़ गई जबकि दरकदार एल पी जी की कीमतें 103% तक बढ़ गई। इस अवधि के दौरान एच ओ सी एल द्वारा प्रयोग की जाने वाली एल एस एच एस की कीमतें 101% तक बढ़ गई और आयातित क्यूमिन की भूमि पर उतराई के समय की कीमतें 104% तक बढ़ गई। एच सी एल ने बैन्जीन के लिए 97% और प्रोपिलीन के लिए 54% की कीमतों की वृद्धि का सामना किया। इस अवधि के दौरान एच ओ सी एल के लिए एल एस एच एस नाफ्ता और ईंधन तेल की प्रापण कीमतों में क्रमशः 96%, 104% और 78% की वृद्धि थी। एच सी एल की क्यूमिन प्रापण कीमतों में 118% की वृद्धि हुई।

जहाँ तक कच्चे माल की कीमतों में वृद्धि के प्रभाव का संबंध है यह पाया गया है कि बैन्जीन और प्रोपिलीन की कीमतों में वृद्धि के लिए समायोजन बनाने के पश्चात् आयातित माल लागत समायोजित कीमतों ने 1998-99 की दूसरी छःमाही में 395-435 अमरीकी डालर प्रति मी० टन की तुलना में 2000 की दूसरी छःमाही में 417-464 अमरीकी डालर प्रति मी०टन का कुछ सुधार दर्शाया। घरेलू रूप से उत्पादित फिनाल के विषय में आवेदकों ने यह प्रस्तुत किया कि एच सी एल को उनके फिनाल के संचालनों में 1999-2000 में लगातार हानि हुई (आयातित फिनाल पर 22% रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित होने के बावजूद) और एच ओ सी एल को बहुत कम लाभ हुआ (रक्षोपाय शुल्क नहीं होने पर क्षति में परिवर्तित हो जाता) 2000-2001 में (अप्रैल-नवम्बर) दोनों घरेलू उत्पादकों को, 15% रक्षोपाय शुल्क लगने पर, कुछ लाभ हुए जिसने उनको अपने विक्रय मूल्य, 15% रक्षोपाय शुल्क मिलाकर, आयातित फिनाल की भूमि पर उतराई के समय की कीमतों के बराबर बढ़ाने के लिए अनुमत किया। यह देखना महत्वपूर्ण है कि यदि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित न किया जाता तो दोनों घरेलू उत्पादकों को नुकसान हुआ होता और यदि जून, 2001 के पश्चात् रक्षोपाय शुल्क जारी न रहा तो उनको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। दोनों घरेलू उत्पादकों के लागत के लेखों का परीक्षण विभागीय लागत लेखा विशेषज्ञों द्वारा किया है और वे सही पाए गए हैं।

यह देखना भी महत्वपूर्ण है कि आयातित फिनाल 90-120 दिनों की ऋण अवधि पर आता है जिसका प्रभाव घरेलू उत्पादकों के लाभांश पर पड़ता है क्योंकि घरेलू उत्पादकों को घरेलू बिक्रियों पर जल्द नकद प्राप्ति के लिए छूट देनी पड़ती है अथवा लंबी अवधि का ऋण प्रस्ताव देना पड़ता है इसके कारण दोनों घरेलू उत्पादकों के लिए कर्जदारों की वृद्धि हुई । आवेदकों ने दृढ़ता से दावा किया है कि कर्जदारों के बढ़ने से लाभों पर दबाव पड़ा है जिसने नकदी के लिए संकट की स्थिति पैदा की जिसके कारण कच्चा माल खरीदने के लिए नकदी न होने के कारण कई बार उत्पादन प्रभावित हुआ । यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि घरेलू उत्पादकों को उनके कच्चे माल की कीमतें तत्काल देनी पड़ती है क्योंकि 15 जून, 2000 से तेल कम्पनियों ने सभी ऋण और छूटों को वापिस ले कर लिया है । उपरोक्त कारणों से घरेलू उत्पादक क्यूमिन का पर्याप्त भंडार नहीं कर सके जो कि उनको अधिक फिनाल उत्पादित करने के लिए सहायता कर सकता था । इसके फलस्वरूप भी घरेलू उत्पादकों की कार्यरत पूंजी की आवश्यकता बढ़ी और कम लाभांशों, अपर्याप्त वित्तीय कार्य सम्पादन और फिनाल के आयातों पर नियत 29.06.01 को समाप्त होने वाले रक्षोपाय शुल्क को यदि सरकार द्वारा बढ़ाया न गया वे तो उसके समाप्त होने की संभावना के कारण बैंक द्वारा स्वीकृत अतिरिक्त कार्यरत पूंजी सीमाओं को हासिल करने में समर्थ नहीं होंगे ।

यह भी महसूस किया जाता है कि घरेलू उत्पादकों ने शेयर मूल्यों पर ठीक व्यवहार नहीं किया है क्योंकि उनके शेयर मूल्य गिर रहे हैं । उन्हें मार्च, 99 से नवम्बर, 2000 के बीच रोजगार में हानि भी उठानी पड़ी है उनकी संयुक्त श्रमशक्ति 31.3.99 को 1168 से 30.11.2000 को 1110 तक कम हो गयी ।

घरेलू उत्पादकों की वर्तमान स्थिति दर्शाती है कि वे फिनाल के आयात से गंभीर क्षति की जारी आशंका का सामना कर रहे हैं और जून, 2001 से आगे रक्षोपाय शुल्क गंभीर क्षति को रोकने के लिए आवश्यक है जो कि रक्षोपाय शुल्क वापिस लेने से उनको हो सकती है ।

घरेलू उद्योग द्वारा सकारात्मक समायोजन:-

घरेलू उत्पादकों ने अपनी उत्पादन क्षमता की वृद्धि के लिए तकनीक को उन्नत करने और अपने संचालनों के मार्गावरोधों को खोलने की योजना बनाई थी । इस विषय में यह पाया गया कि घरेलू उत्पादकों ने अपने आरम्भिक आवेदन में कहेनुसार अपनी क्षमता में सुधार के लिए कदम उठाए है ।

उनके द्वारा किए गए प्रयासों के फलस्वरूप एच ओ सी एल की उत्पादन क्षमता में 49,000 मी०टन प्रति वर्ष की और एच सी एल की क्षमता में बढ़कर 34000 मी०टन प्रति वर्ष की हो गई । दोनों को मिलाकर, उनकी उत्पादन क्षमता में 1998-99 में 75000 मी०टन प्रति वर्ष से 2000-2001 में 83,000 मी०टन प्रति वर्ष की वृद्धि हुई अर्थात् 10% से अधिक की वृद्धि ।

कुछ पक्षों ने उत्पादन क्षमता की वृद्धि के विषय में , विशेषकर एच ओ सी एल पर संदेह व्यक्त किया है कि सत्यापित की जाने वाली कोई भी पुर्नमूल्यनिर्धारण ओर वर्धित क्षमता के लिए, उस क्षमता स्तर पर सुसंगत उत्पादन को एच ओ सी एल के बोर्ड द्वारा अनुमत करवाने के लिए स्थापित करवाना होगा । तथापि सत्यापन करने पर एच ओ सी एल और एच सी एल की उत्पादन क्षमता क्रमशः 49000मी०टन और 34,000मी०टन पाई गई । एच ओ सी एल की वर्ष में 330 दिनों के संचालन के आधार पर 40,000 मी०टन प्रति वर्ष की उत्पादन क्षमता थी । वर्ष 1999-2000 में संशोधनों के पश्चात इसकी फिनाल की उत्पादन क्षमता 49,000मी०टन प्रति वर्ष तक बढ़ गई थी । यूनिट के ऑक्सीडेशन कक्ष की वायु प्रणाली की प्रक्रिया को इस वृद्धि को पाने के लिए बढ़ाया गया था । नवम्बर-दिसम्बर, 2000 में यूनिट की उत्पादन क्षमता 55,000 मी०टन प्रतिवर्ष तक बढ़ाने के लिए और प्रयोग किए गए जिनके उत्साहवर्धक परिणाम प्राप्त हुए ।

यह भी सत्यापित किया गया कि एच ओ सी एल ने द्विस्तरीय विदलन तकनीक को लागू करके कम लागत के लाभ भी हासिल किए जिसने उनको विदलन प्रतिक्रिया में एसिडिटी कम करने के लिए समर्थ बनाया जिससे गौण-उत्पादनों के संघटन में कमी हुई और कुल मिलाकर उत्पादन में वृद्धि हुई । उन्होंने भाप ओर विद्युत की लागत कम करने की योजनाओं को लागू किया जिससे और अधिक अच्छा उपभोग अनुपात प्राप्त किया और फिनाल क्षमता में वृद्धि के फलस्वरूप निर्धारित लागतों में कमी भी हासिल की ।

इसी प्रकार उन्नत तकनीक के क्षेत्र में एच ओ सी एल ने संलयक और नई एसिड इंजेक्शनप्रणाली की स्थापना में भी उन्नति की है । अतिरिक्त निस्स्यन्दन ओर बैंजीन वेपर रिकवरींग प्रणाली से फिनाल की 49000 टन प्रति वर्ष की वर्धित क्षमता को पाने के लिए प्रतिवर्ष 12000 टन क्यूमिन उत्पादित की जा सकती है । इनके फलस्वरूप अनुबद्ध लागत में भी बचत हुई ।

घरेलू उद्योग ने कहा है कि रक्षोपाय शुल्क लगने के बावजूद कुछ अतिरिक्त अप्रत्याशित परिस्थितियों के कारण 1999-2000 वर्ष के दौरान फिनाल संचालन लाभकारी नहीं थे जिसने धन संभूतियों की कमी के कारण उनकी लागत में कमी करने की योजनाओं को बुरी तरह प्रभावित किया । तथापि उनकी लागत को कम करने और प्रतिस्पर्धी की वचनबद्धता के कारण उन्होंने समायोजन योजनाओं को लागू करने की व्यवस्था की ।

उत्पादन लागत को कम करने के लिए उनके और प्रयास और उनको पाने के लिए पर्याप्त आवश्यक समय के विषय में एच ओ सी एल ने कहा है कि वे अपनी संचालन नियंत्रण प्रणाली को उन्नत करेंगे और संचालन दक्षता को सुधारेंगे जिसके कारण फिनाल की लागत में (गोपनीय) रू० प्रति मी०टन की बचत होगी और यह डेढ़ वर्ष के अंदर लागू होनी है । उन्होंने यह भी कहा है कि दक्षता को सुधारने के लिए अपनी दक्षता को बढ़ाएंगे और अपने उपकरणों को उन्नत करेंगे जिसके फलस्वरूप फिनाल की लागत में (गोपनीय) रू० प्रति मी०टन की बचत होगी जिसको लागू होने में दो वर्ष का समय लग जाएगा । इसी प्रकार एच सी एल ने कहा है कि एक

वर्ष के अंदर अधोसामयिक रखरखाव को घटाने के लिए मार्गावरोधों को दूर करके और उपकरणों की स्थापना करके फिनाल की लागत में (गोपनीय) रू० प्रति मी०टन की बचत हासिल कर लेंगे । डेढ़ वर्ष के अंदर संवर्धन और संशोधनों द्वारा फिनाल की लागत में (गोपनीय) रू० प्रति मी०टन की बचत हासिल कर लेंगे और दो वर्षों के अंदर विद्युत दक्षता और मध्यवर्ती संयंत्र का आधुनिकीकरण के द्वारा फिनाल की लागत में गोपनीय रू० प्रति मी०टन की बचत हासिल कर लेंगे । इस प्रकार यह देखा गया कि घरेलू उत्पादकों को अपनी और संरचना योजनाओं को पर्याप्त रूप से लागू करने के लिए दो वर्षों की अवधि की और आवश्यकता है जिससे उत्पादन क्षमताओं में वृद्धि होगी और फिनाल की विनिर्माण की लागत में भी कमी आएगी ।

सार्वजनिक हित

कुछ पक्षों ने तर्क दिया है कि फिनाल के आयात पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण सार्वजनिक हित में किसी प्रकार से सहायता नहीं करेगा । इसके विपरीत रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण सार्वजनिक हित को गंभीर रूप से क्षति पहुंचाएगा इससे अनेक अंतिम प्रयोगकर्ता उद्योग बंद हो सकते हैं । इस विषय में यह देखा गया कि ' सार्वजनिक हित ' अभिव्यक्ति अपने दायरे में केवल उपभोक्ता के हित को आच्छादित नहीं करती । इस शब्द का अधिक व्यापक अर्थ है जो अपने दायरे में बड़े जन समुदाय हित के साथ सामान्य सामाजिक कल्याण को भी शामिल करता है । जहां रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के परिणामस्वरूप खरीदारों के लिए आयातित फिनाल की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, यह उसके अंतिम उत्पाद विनिर्माताओं को भी प्रभावित कर सकता है । इसलिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण के उद्देश्यों को भी ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है । रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण का उद्देश्य घरेलू उद्योग को वर्धित आयातों से उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की नई स्थिति से निपटने के लिए सकारात्मक समायोजन बनाने के लिए घरेलू उद्योग को समय उपलब्ध करवाना है । इसलिए कुछ पर्याप्त समय के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण ग्राहकों के लिए लिए न केवल प्रतिकूल प्रभावों को, यदि कोई कोई हो, तो कम करेगा बल्कि उनको प्रतिस्पर्धी कीमतों पर अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए व्यापक चुनाव भी प्रदान करेगा । जिन घरेलू उत्पादकों ने बड़े सार्वजनिक निवेशों से संयंत्र स्थापित किए हैं, बहुत लोगों को रोजगार देकर राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को बहुमूल्य योगदान देते हैं । रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण जो घरेलू उत्पादकों को वर्धित आयातों द्वारा उत्पन्न प्रतिस्पर्धा की स्थिति में टिकाए रखेगा वही वह लंबे समय तक फिनाल के क्रेताओं और उससे विनिर्मित उत्पादों के क्रेताओं के हित में भी होगा । इसलिए यह महसूस किया जाता है कि और दो वर्षों के लिए फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क का जारी रहना सार्वजनिक हित में होगा ।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण देश के निर्यातों को गंभीर रूप से प्रभावित करेगा । निर्यात उत्पादन में प्रयोग किया गया आयातित फिनाल महंगा हो जाएगा । इस विषय में यह पाया गया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शुल्क और करों से घिरा हुआ है अर्थात् सभी निवेशों पर रक्षोपाय शुल्क सहित समस्त जो शुल्क और कर निर्यात उत्पादन के लिए प्रयोग किए जाते हैं वे शुल्क वापसी इत्यादि के रूप में शुल्क प्रतिदाय के पात्र हैं । इसलिए निर्यात उत्पादन में प्रयोग हुए आयातित फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क सहित शुल्क और कर भी शुल्क प्रतिदाय के पात्र होंगे । रक्षोपाय शुल्क का उद्देश्य घरेलू उत्पादकों को

अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के योग्य बनाना है । इसलिए यदि निर्यात उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाने वाला घरेलू उत्पादित फिनाल अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी नहीं है तो रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण को उन्हें अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायता करनी चाहिए जो लंबे समय तक निर्यातकों के हित में होगी । विभिन्न योजनाओं में निर्यात उत्पादनों में प्रयोग के लिए जहां तक फिनाल के निःशुल्क आयात का संबंध है ऊपर चर्चित वही सिद्धांत लागू होता है अर्थात या तो इस प्रकार के आयातों पर रक्षोपाय शुल्क रोपित नहीं होना चाहिए अथवा यदि रक्षोपाय शुल्क लिया गया है तो वर्तमान कानूनों के अनुसार इसे अंतिम उत्पाद के निर्यात हो जाने पर शुल्क प्रतिदाय का पात्र होना चाहिए । इसलिए यह देखा गया कि फिनाल पर सतत रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण से न तो निर्यात उत्पादन को प्रभावित होने की संभावना है न ही यह सार्वजनिक हित के विरुद्ध है ।

भारत को किए जाने वाले निर्यात में देशों का अंश

1998-99, 1999-2000 और 2000-2001 की अवधि के दौरान भारत में फिनाल के आयातों के विषय में सूचना के आधार पर यह पाया गया कि निम्नलिखित देशों ने भारत को फिनाल का निर्यात किया । 1998-99 और 1999-2000 की अवधि के आंकड़े डी जी सी आई एस, कलकत्ता से लिए गए हैं और 2000-2001 की अवधि के आंकड़े आवेदकों द्वारा प्रस्तुत सत्यापित आँकड़ों पर आधारित हैं । तदनुसार कथित अवधि के दौरान भारत के आयात में उनका अंश निम्न प्रकार से हैं:

मी० टन में आयात

देश/क्षेत्र	1998-99		1999-2000		2000-2001	
	मात्रा	अंश की प्रतिशतता	मात्रा	अंश की प्रतिशतता	मात्रा	अंश की प्रतिशतता
चीन पी आर	7000	0.03	117.667	0.40	-	-
यूरोपियन समुदाय	85.735	0.34	16493.150	56.29	7348.301	27.79
इस्राइल	-	-	20.500	0.07	-	-
जापान	5911.450	23.45	849.716	2.90	1014.139	0.16
कोरिया आर पी	9762.106	38.72	16.000	0.05	-	-

मैक्सिको	-	-	100.000	0.34	-	-
रूस	36.000	0.14	895.046	3.05	-	-
साऊथ अफ्रीका	8522.457	33.80	2165.344	7.40	374.000	1.41
सिंगापुर	16.000	0.06	72.600	0.25	41.4001	0.16
स्विटजरलैंड	0.100	-	28.000	0.09	-	-
सऊदी अरब	-	-	108.000	0.37	-	-
ताइवान	809.505	3.21	231.850	0.79	3550.420	13.13
अमेरीका	62.645	0.25	8204.216	28.00	14114.732	53.38
कुल	25212.999	100	29302.089	100	26442.992	100

निष्कर्ष एवं संस्तुति

(1) उपर्युक्त जाँच परिणामों को ध्यान में रखते हुए फिनाल के घरेलू उत्पादक फिनाल के आयातों से लगातार गंभीर क्षति की आशंका का सामना कर रहे हैं और आयातों द्वारा प्रस्तुत प्रतिस्पर्धा के लिए स्पष्ट रूप से सकारात्मक समायोजन योजना बना रहे हैं । उनको अपनी अतिरिक्त संरचनात्मक योजना को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए और दो वर्षों के समय की आवश्यकता है तथा रक्षोपाय शुल्क और दो वर्षों के लिए जारी रहना सार्वजनिक हित में होगा । इसके अलावा फिनाल की मांग और आपूर्ति के अंतर को देखते हुए यह भी सार्वजनिक हित में होगा कि फिनाल पर रक्षोपाय शुल्क अधिरोपण की बढ़ाई हुई अवधि के प्रथम वर्ष में फिनाल के 12000 मी०टन और द्वितीय वर्ष में 12,500 मी०टन के आयात (निर्यात उत्पादन में प्रयोग करने के लिए फिनाल की मात्रा को छोड़कर) पर रक्षोपाय शुल्क अदायगी से छूट दी जाए ।

(2) रक्षोपाय शुल्क की कितनी राशि निर्धारित की जाए कि घरेलू उद्योग की गंभीर क्षति को रोका जा सके और अनुकूल समायोजन को सरल बनाने के लिए एच ओ सी एल और एच सी एल के 2000-2001(नवम्बर, 2000 तक) की अवधि के उत्पादन को लिया गया है । घरेलू उत्पादकों ने लगाई गई पूंजी पर संभावित वापसी के आधार पर निश्चित लाभ का दावा किया है जो कि समझा गया है कि अधिक है इसलिए उत्पादन की भारित औसतन लागत के आधार पर लाभ की कम से कम राशि (गोपनीय) उचित समझी गई है और अनुमत की गई है । इसी प्रकार 2000-2001 (नवम्बर, 2000) तक की अवधि के लिए फिनाल की सी आई एफ कीमतें भारित औसत आधार पर निकाली गई है ऋणों के लिए सी आई एफ आयात कीमतों में समायोजनाएं

बनाई गई है । आयातित फिनाल की भूमि पर उतराई के समय की कीमत निकालने के लिए लागू होने वाली सीमा शुल्क दरों में परिवर्तन को ले लिया गया है ।

(3) कुछ पक्षों ने कहा है कि क्योंकि पहले और दूसरे वर्ष के मध्य सरलीकरण 7% तक था तो तीसरे वर्ष में सरलीकरण या तो 7% अथवा उससे अधिक होना चाहिए । फलस्वरूप यदि तीसरे वर्ष के लिए रक्षोपाय शुल्क संस्तुत किया जाता है तो यह 8% या इससे कम होना चाहिए । इस विषय में यह पाया गया कि एक समान सरलीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है और इसे घरेलू उत्पादकों के संरचनात्मक/समायोजन योजना और तथ्यों के साथ विशेष परिस्थितियों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनके अनुसार होने की जरूरत है जो घरेलू उद्योग की सकारात्मक समायोजन को सरल करने हेतु यथोचित प्रभावी है और न्यूनतम आवश्यकता के अधीन फिनाल के वर्धित आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति की आशंका से बचाने के लिए अधिरोपित किया गया रक्षोपाय शुल्क कम से कम है ।

(4) घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सकारात्मक समायोजना को और अधिक सरल बनाने की आवश्यकता पर विचार करते हुए यह संस्तुति की जाती है कि भारत में फिनाल के आयातों पर, निम्नलिखित दरों पर, न्यूनतम आवश्यकता के अधीन घरेलू उद्योग को फिनाल के आयातों से निरंतर गंभीर क्षति की आशंका से संरक्षण के लिए रक्षोपाय शुल्क अधिरोपित कर दिया जाए

अवधि	संस्तुत कुल - संरक्षण का स्तर %	वर्तमान संरक्षण %	संस्तुत शुल्क %	रक्षोपाय (3)- (2)
(1)	(2)	(3)	(4)	
विस्तारित अवधि- का प्रथम वर्ष	25 + 12	25	12	
विस्तारित अवधि का द्वितीय वर्ष	25 + 9	-	9	

तथा बढ़ाई गई अवधि के प्रथम और द्वितीय वर्ष में क्रमशः 12,000 मी०टन ओर 12,500 मी०टन फिनाल पर (निर्यात उत्पादनों में प्रयोग होने वाले फिनाल की मात्रा को छोड़कर) सम्पूर्ण रक्षोपाय शुल्क की अदायगी से छूट दी जाए ।

[फा. सं. एस जी/आई एम बी/2/98(राजस्व)]

आर. के. गुप्ता, अपर महानिदेशक (रक्षोपाय)

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL (SAFEGUARDS)**NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th May, 2001

Subject : Review of Safeguard duty imposition on imports of Phenol into India under Rule 18 of the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997—final findings.

G.S.R. 441(E).—Having regard to the Customs Tariff Act, 1975 and the Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 thereof.

A. INTRODUCTION

The notice initiating investigation concerning import of Phenol into India was issued on 02.02.99 under Rule 6 of the SGD Rules. Final findings were issued under Rule 11(1) of the said Rules, (published in the Gazette of India (Extraordinary) Part II-Section-3-Sub-section (i)) on 11.06.99, recommending safeguard duty to be imposed @ of 22% advalorem during the 1st year and @ of 15% advalorem during the 2nd year on imports of Phenol into India being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury threatened to be caused by the increased imports of Phenol. In exercise of powers conferred by sub section (1) of section 8B of the Customs Tariff Act, 1975(51 of 1975) read with Rules 12 and 14 of the SGD Rules and based on the final findings of the Director General (Safeguards), the Central Government vide Notification No.82/99-Customs dated 30th June, 1999 imposed on Phenol, falling under sub-heading number 2907.11 of the First Schedule to the said Customs Tariff Act, when imported into India, a safeguard duty at the rate of;

22% when imported upto and inclusive of the 29th day of February, 2000; and

(b) 15% when imported from the 1st of March, 2000 to 29th day of June, 2001 (both days inclusive).

B. PROCEDURE

The Notice of Review to consider whether safeguard duty on imports of Phenol into India should be continued to be imposed to prevent serious injury was issued on 01.01.2001 and was published in the Gazette of India, Extraordinary on 08.01.2001. A copy of the Notice was sent to all known interested parties, namely:-

Domestic Producers

- (i) Hindustan Organic Chemicals Ltd (HOCL), Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd. (HCL), Mumbai
- (iii) Neyveli Lignite Corporation, Tamilnadu.

Importers/User Industries

- (i) C.J.Shah & Company, Mumbai
- (ii) Haresh Kumar & Company, Mumbai
- (iii) PCL Industries, New Delhi.
- (iv) Kantilal Manilal & Company, Mumbai
- (v) Vinmar International India Pvt. Ltd., Mumbai
- (vi) Sonkamal Enterprises, Mumbai
- (vii) Khetan Brothers, Mumbai
- (viii) Shubham Dyes & Chemicals Ltd., Delhi
- (ix) Xpro India, Mumbai
- (x) Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai
- (xi) Bakelite Hylam Ltd., Hyderabad
- (xii) Greenply Industries Ltd., Distt. Ratnagiri, Maharashtra
- (xiii) Gargi Huttenes Albertus Private Limited, Mumbai
- (xiv) Alta Laboratories Ltd., Dadar, Mumbai
- (xv) United Phosphorus Limited, Mumbai
- (xvi) Colour Chem Limited, Balkum, Thane
- (xvii) Kitply Industries, Calcutta
- (xviii) Romit Resins Pvt. Ltd., Panvel
- (xix) Bilag Industries, Vapi
- (xx) United Metachem, Pune
- (xxi) Marvel Thermosets P. Ltd., Mumbai
- (xxii) Helm India Pvt. Ltd., Mumbai.

Exporters

- (i) Phenolchemie GmbH, Germany
- (ii) Enichem, Italy
- (iii) Georgia Gulf Corporation, U.S.A.
- (iv) Mitsui Chemicals, Tokyo
- (v) Kumho Chemical Company, Seoul, Korea
- (vi) Taiwan Prosperity Chemical Company, Taiwan
- (vii) Merisol, South Africa, (Merichem Sasol)
- (viii) Kolmar Petrochemicals AG, Switzerland.
- (ix) ICC Chemical Corporation, New York,
- (x) Tosoh Corporation, Tokyo
- (xi) Formosa Plastics Corporation, Taiwan
- (xii) Tricon Energy Ltd., U.S.A.

Overseas Associations

- (i) Chemical Safety Management Centre, Japan Chemical Industry Association-JCIA, Tokyo 100, Japan.
- (ii) Chemical and Allied Industries Association -(CAIA) Auckland Park 2006, South Africa.
- (iii) Korean Petrochemical Industry Association -(KPIA) Chongno-ku, Seoul, Korea.
- (iv) Petrochemical Industry Association of Taiwan (PIAT) Section 4, Chutung, Hsinchu, Taiwan.
- (v) Chemical Manufacturers Association (CMA) Virginia-22209, USA
- (vi) Verband der Chemischen Industrie - VCI Germany

Indian Associations

- (i) Society of Thermosetting Industries, Mumbai
- (ii) Indian Laminates Manufacturers Association, Mumbai
- (iii) Indian Chemical Manufacturers Association, Mumbai

2 A copy of the notice alongwith the application and questionnaire was also sent to the governments of exporting countries through their High Commissions/Embassies in New Delhi namely Belgium, Chinese Taipei, Germany, Italy, Japan, Korea DPR, Korea RP, the Netherlands, Russia, Singapore, South Africa, U.K., USA and to the European Union, Delegation of the European Commission in India, New Delhi.

3. Questionnaires were also sent on the same day to all known domestic producers, exporters and importers who were asked to submit their response by 09.02.2001.

4. Request for extension of time to submit their reply was made by the following parties:

- (i) Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai
- (ii) Alta Laboratories Ltd., Dadar, Mumbai
- (iii) Kitply Industries, Calcutta
- (iv) Romit Resins Pvt. Ltd., Panvel
- (v) Marvel Thermosets P. Ltd, Mumbai
- (vi) Dujodwala Resins & Terpenes Ltd., Mumbai
- (vii) The Institute of Indian Foundrymen, Calcutta
- (viii) All India Association of Industries, Mumbai

However, as the requests for extension were made without proper justification, the extension of time prayed for was not acceded to and the parties concerned were informed accordingly.

5. Replies to the Notice dated 01.01.2001 and to the questionnaire were received from the following parties:-

Domestic Producers

- (i) Hindustan Organic Chemicals Ltd., Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai
- (iii) Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli

Importers/User Industries

- (i) Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai
- (ii) Alta Laboratories Ltd., Dadar, Mumbai
- (iii) Kitply Industries, Calcutta
- (iv) Marvel Thermosets P. Ltd., Mumbai
- (v) Xpro India Ltd., Mumbai
- (vi) United Metachem Pvt. Ltd., Pune
- (vii) Daurala Organics Ltd., New Delhi
- (viii) Colour Chem Ltd., Thane
- (ix) Schenectady Specialities Asia Ltd., Mumbai
- (x) Gargi Huttenes – Albertus, Mumbai
- (xi) Foseco India Ltd., Pune
- (xii) Century Laminating Co. Ltd., Calcutta

Exporters

- (i) Phenolchemie, Germany
- (ii) ICC Chemical Corporation, USA
- (iii) Mitsui Chemicals, Tokyo, Japan

Indian Associations

- (i) Society of Thermosetting Industries, Mumbai
- (ii) All India Association of Industries, Mumbai
- (iii) Indian Chemical Manufacturers' Association, Mumbai

6. Verification of the information considered necessary for the investigation was done and to this end a team of officers including Cost Accounts experts visited the premises of M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd., Cochin; M/s. Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai; M/s. Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai. The outcome of investigations was conveyed to the concerned parties and a copy of the investigation report was also placed in the Public File.

7. A Public Hearing was given to all interested parties on 12.04.2001 notice for which was sent on 09.03.2001. During the Public Hearing, the interested parties were requested to file their written submission of oral arguments made by them by 19.04.2001, collect replies filed by others on 23.04.2001 and to file rebuttals if any, by 30.04.2001.

The following parties attended the public hearing:

- (i) Hindustan Organic Chemicals, Mumbai
- (ii) Herdillia Chemicals Ltd., Mumbai
- (iii) Phenolchemie, Germany (through Counsel)
- (iv) Schenectady Specialities Asia Ltd., Mumbai
- (v) Sumitomo Corporation, Japan
- (vi) Mitsui & Co. Ltd., Japan
- (vii) Beardseil Ltd.,
- (viii) Foseco India Ltd., Pune. } Through Counsel
- (ix) Kesar Petroproducts Ltd., Mumbai }
- (x) Daurala Organics. Ltd., New Delhi }
- (xi) Herman Bawa (P) Ltd. }
- (xii) Shubham Dyes & Chemicals., Delhi
- (xiii) Century Laminating Co. Ltd., Calcutta.
- (xiv) Everest Plastics, New Delhi.
- (xv) Paras Dyes & Chemicals, Delhi.

B VIEWS OF EXPORTERS

The following main points have been made by the exporters:

(a) Phenol Chemie, Germany

- i) They are a global player selling phenol all over the world. Their average price in India was 630 US\$ per ton which was 20% higher than prices prevailing in other Asian markets, especially in South East Asia.
- ii) They had a capacity of 1.2 million tons per annum in the year 2000 and presently their capacity is 1.4 million tons per annum namely Gladbeck 639 Kt/Antwerp (Belgium) 420 Kt/Mobile (US) 400 Kt. Their capacity utilisation was above 92%.
- iii) They had exported to India 4579 MT of Phenol during the year 2000.
- iv) Phenol besides being used as a pesticide is used to produce Phenol formaldehyde condensation resins, which continue to account for more than 25% of all uses of phenol worldwide. Phenol resins are used in many different applications: in decorative & industrial laminates, drugs, moulds in the foundry industry, adhesives, as well as in a wide range of other applications. In recent years the use of phenol for the production of Bisphenol-A has grown at above average rates & this growth is expected to continue. The most important reason for this growth is the use of Bisphenol-A in products such as compact discs & CD ROMs for computer storage, aircraft windows & structural parts in trucks.
- v) The impact of credit has no place in a non-injurious price calculation. As exporter they would like to put on record that any credit they grant is only against Letter of Credit. In India as far as they are aware there is a cost for

getting the Letter of Credit. As all commercial transaction, credit has cost which eventually reflects in the pricing of the goods.

vi) There can be no basis for the continued imposition of Safeguard Duty since there have been no increase in imports; the data that the applicants rely revealing increase in imports of Phenol have already been taken into consideration and consequently is covered under the principle of Res Judicata i.e. the same issue cannot be decided twice between the same parties.

vii) There is no provision in the law that as a result of the imposition of Safeguard Duties the domestic petitioners must make profit or that they must regain the lost market share.

viii) The continued imposition of Safeguard Duty & even extension at a reduced level is unfair & is contrary to Public Interest.

(b) ICC Chemical Corporation, USA

i) Section 8B of the Customs Tariff Act, 1975 provides for levy of continuation of Safeguard Duty and the three conditions for imposition of Safeguard Duty are namely Articles must be imported into India in increased quantities; there must be a serious injury to the domestic industry; and Casual link between imports in increased quantities and serious injury or thereby a serious injury to the domestic industry.

ii) For continuation of Safeguard Duty, the Central Government must be of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or the threat thereof.

iii) The applicants have failed to establish the ingredients mentioned above which are required not only for the levy of Safeguard Duty, but also the continuation thereof.

iv) The total import of Phenol during the current year 2000-2001 is projected to be less than the total imports during 1998-99 and 1999-2000. It is estimated to be 25760 MTs. The domestic industry has achieved 97% capacity utilization based on their installed capacity declared in their Balance Sheets. The domestic production was affected by factors related to the internal problems of the domestic industry which have nothing to do with the import of Phenol.

v) For both HOCL and HCL, Phenol is a profit-making product. HOCL and HCL appeared to be seeking protection to recoup/recover the loss made by them on other products manufactured by them at the cost of the domestic industry using Phenol and manufacturers of other down-stream products.

vi) The closing stock of the two manufacturers of Phenol, reflect an healthy sales in the local market. The closing stocks are equal to about 4 days production which is normal by any standards.

- vii) The sale price of Phenol has increased from Rs. 35,541/- per MT in 1998-99 to Rs. 45,810/- per MT in 2000-2001.
- viii) The percentage of sale price to the cost of the raw material is about 260% at the present sale price of Phenol of the applicants.
- ix) The applicants have not made any adjustments in the past two years when SGD was imposed to be more cost efficient and remedy the alleged injury caused or threaten to be caused by imports.
- x) The applicants are oversized in terms of manpower and the cost estimates for the proposed expansion is excessive and exaggerated having regard to the International standards and norms.
- xi) They had exported to India approximately 5,000 MT of Phenol per year during the last three years.

They had addressed a letter dated 27.04.2001 stating interalia that on the request of M/s. Kesar Petroproducts, Mumbai they had forwarded a covering letter for submission of routine paper work for the Public Hearing on 12.04.2001. Subsequently they have been given to understand that their covering letter was submitted alongwith certain documents of which they have no knowledge and are without their approval or permission. They have requested that all documents submitted under their covering letter be treated as null and void and not to be taken on record.

(c) Mitsui Chemicals, Tokyo, Japan

- i) Imports of Phenol into India have increased with internationally competitive price due to insufficient quantity of production by Indian manufacturers against demands from Phenol Users.
- ii) Price levels in India set out by Indian manufacturers is extremely high compared to that of other Asian Countries, which compress profitability of Phenol derivatives manufacturers, and would cause irreparable adverse effect on general economy in India.
- iii) Non-achievement of "Implementation of Adjustment Plan" for Indian manufacturers is not caused by increment of imports of Phenol but by structural problems of Indian Phenol manufacturers.
- iv) It is not true that Phenol is being imported into India at prices much lower than that of second half of the year 1998 (when adjusted for the increase in the raw material cost). They admit that the import prices of Phenol in India was at rather low level during the period of Mar/99 to Oct/99, and consequently, the margin from Phenol price and raw material cost was lower than that of 2nd half of 1998. However, it was not the specific issue in India but in all over the world

including other Asian countries, which was due to the sudden price increment of raw materials. If the average of cost adjusted Phenol from April, 2000 to December 2000 is taken, it works out to US \$ 437/MT, not for from that of Sept, 1998 US@ 450/MT which is the evidence that Phenol manufacturers could have adjusted the export prices to India at least 9 month later than sudden increment in price of raw materials. The import price of Phenol into India has been in appropriate range from the marginal point of view as of now.

v) Due to Force Majeure circumstances and cash crunch as stated by the applicants they were obliged to stop production for certain period of time. As a consequence, the quantity produced by Indian Phenol producers could not satisfy the total demand of Phenol in India and Phenol users had to procure Phenol from outside India even after the imposition of Safeguard Duty. The increment of imported Phenol was not the cause for lower production by Indian manufacturers, but less production by the Indian manufacturers has caused increased imports of Phenol in spite of imposition of Safeguard Duty from July, 1999.

vi) HOCL and HCL have requested for US \$ 201.05/MT of Safeguard Duty in order to raise the import price of Phenol to US\$ 991/MT being claimed as the reasonable average survival selling price. If one takes US\$ 610/MT as CIF price, which was actual sales price of December 2000 in Phenol producing countries in Asia, the landed cost after import duty (exclusive of Safeguard Duty) of each country is as follows :

Country	Import Duty Rate Excluding Safeguard Duty	Import price After Import Duty	Difference From US\$ 777.75
People's Republic of China	9%	US\$664.90	-US\$112.85
Japan	0%	US\$610.00	-US\$167.75
Republic of Korea	8%	US\$658.80	-US\$118.95
Taiwan	1.25%	US\$617.63	-US\$160.12
India	27.5%	US\$777.75	-US\$0.00

vii) Taking into account the other related cost for import such as Custom clearance fee, the price of Phenol after import duty in India is already higher than those of other Asian countries due to high quantum of Custom Duty in India even excluding Safeguard Duty. Requesting additional US\$201.05/MT or equivalent quantum of Safeguard duty is the evidence of high-cost structure of Indian manufacturers compared to those of other Asian Countries. They understand that India belongs to WTO, whose function is to ensure trade flows between nations as smoothly, predictably and freely as possible, and in that sense, US\$201.05/MT of safeguard duty is against the policy of WTO and unreasonable requirement which no other country except India applies in the world. Most of the Phenol manufacturers other than HOCL and HCL actually exported with more or less the same level of price stated as above, and no

quantity of export by HOCL and HCL during year 2000 is the evidence of non-competitiveness of Indian Phenol manufacturers as well.

viii) They have been requested by Phenol users in India to supply them Phenol at competitive price with high quality which domestic Phenol manufacturers were unable to attain. However, as long as Safeguard Duty on Phenol is imposed in India, Phenol users in India are obliged to bear the said additional duty, and consequently, the price of Phenol derivatives, which are used in various industries from Plywood to electrical equipment industry or pharmaceutical industry, would lose international competitiveness and would cause irreparable adverse effect on general economy in India.

ix) The compression of Gross Margins of Indian manufacturers is due to structural failure of procurement of raw materials, and no counter-measure have been made for that and for "Implementation of Adjustment Plan Scheme"

x) They have a strong objection to the view of significant global over capacity incase of Phenol expressed by HOCL and HCL since their view is lateral from Phenol supply side only and demand from users has not been taken into account.

xi) HOCL and HCL mentioned that Phenol production capacity has been or will be increased by 1.2 million TPA. However, during the same period, Bisphenol-A, which is one of the biggest Phenol derivatives, has been or will be increased its production capacity by 0.9 Million TPA (which is equal to 0.8 Million TPA as Phenol) mainly from Bayer in USA (160,000 TPA), Bayer in Thailand (160,000 TPA), Mitsui Chemicals in Singapore (140,000 TPA), Bayer in Europe (135,000 TPA) and Nanya Plastics in Taiwan (100,000 TPA). Considering the increased demand from other Phenol derivatives, such as Phenolic Resins, Cyclohexanone, and Aniline, the worldwide relation between supply and demand of Phenol is well-balanced. In addition to that, further increment of production capacity of Bisphenol-A is expected by Kumho P&B in Korea (100,000 TPA), Bayer in China (100,000 TPA), and Mitsui Chemicals in Singapore (70,000 TPA) during 2002-2003, while no Phenol production capacity increment has been officially announced by them.

C. VIEWS OF THE INDIAN ASSOCIATIONS

The following main points have been made by them :

(a) All India Association of Industries, Mumbai.

The views expressed by them are on the same lines to that of domestic user industry.

(b) Indian Chemical Manufacturers Association

They wish to state that Hindustan Organic Chemicals Ltd. and HCL are members of ICMA and they have requested for restoration of customs duty on Phenol to peak level duty on chemicals. Their request was considered favourably in the Trade & Business Development Expert Committee meeting and they have recommended in their products specific recommendations forwarded to the Government of India that the customs duty on Phenol should be restored to peak level duty on chemicals.

(c) Society of Thermosetting Industries, Mumbai

Safeguard Duty is intended to give sufficient time to the indigenous manufacturers so as to make them competitive vis-a-vis imports. No substantial change will take place in the working or operation of both these manufacturers by continuing the duty. While imposing or continuing the Safeguard Duty, the Government should also consider the harm that may be caused to the consuming industry. A greater harm will be caused to the consuming industry by continuing it.

After imposition of the Safeguard Duty, the manufacturers frequently increased their basic phenol price by almost 52% which is very steep i.e. from Rs. 31,000 per ton in July, 1999 to Rs. 47,000 per ton in October, 2000. Phenolic Resin industry which is the main consuming industry of Phenol cannot pass on the increased burden fully and have been able to pass on only a fraction of added cost to their customers. This has seriously affected the working of all the consuming industries in the current financial year and many of them are under the verge of closure.

When the original application was made for imposition of safeguard duty, the international price of Phenol was between US\$ 395-420 per ton CIF India. At present, it has stabilized and is above US\$ 630 per ton and as such there is no reason for manufacturers to complain.

D. VIEWS OF IMPORTERS/USER INDUSTRIES

They have made the following broad main points:

- i) The Effective Phenol capacity (TPA) by the applicants has been overstated for the year 1997-98 onwards. As per their published Annual Report Hindustan Organic Chemicals Ltd.(HOCL) the installed capacity was 40000 TPA which has not increased till 1999-2000 . Even in the reports submitted by HOCL to its controlling Administrative Ministry the target has been shown as 40,000 TPA in the years 1999-2000 and 2000-01. Thus, the installed capacity for the year and capacity utilisation mentioned in the application needs to be corrected. The capacity has been overstated to make out a case of under utilisation of capacity.
- ii) As regards 2000-01 there is no basis to assume that the installed capacity has increased over 1999-2000, since the Annual Report of 1999-2000

of both the domestic manufacturers do not reflect any such programme to increase their capacities.

iii) If the Effective Phenol capacity of HOCL had really been increased in 1997-98, there can not be any reason why the same would not have been included in the Company's Annual Report which is the true and fair record of its performance duly audited by statutory authorities and in case of HOCL by Government auditors also. The Annual Report is a Company's authentic document made available to the legal authorities and its shareholders and must contain the correct details.

iv) If the correct figures are adopted, the capacity utilisation for 1997-98 would be 104%, 95% in 1998-99, 97% in 1999-2000 and 96% during 2000-01. This is despite the fact that their plants were not operational on many occasions due to their internal problems not related to market demand or imports.

v) HOCL in their report to their Administrative Ministry reported loss of production of Phenol of 5201 MT due to shortage of power, raw material, shutdowns etc. during the period from April 2000 to Dec 2000. HCL has also reported loss of production during April – June, 2000 to the extent of 5,300 MT. Thus, the total potential loss of Phenol production is 10,501 MT which is not on account of an increase in imports but due to other factors.

vi) In the board meeting held on 27th July for declaring unaudited results for quarter ending 30th June 2000, HCL had mentioned that "the company's operation were affected due to non-availability of a key raw material because of extended shut down at the suppliers refineries." Hence production loss was not due to imports or cash crunch but because of other reasons.

vii) The capacity utilisation ranged between 68% to 78% in respect of other products manufactured by HCL vis-à-vis the capacity utilisation of Phenol which was much higher at 85 % to 93 %. Similar was the case in respect of HOCL where the capacity utilisation ranged between 79% to 86% in respect of other products as compared to the capacity utilisation of Phenol plant which was much higher between 89% to 105%. The losses due to such under utilisation of capacities in respect of other products should not be taken into account to reckon the performance of the Phenol plant.

viii) In their earlier submission, the domestic manufacturers had complained about very high imports(25048 Mt) during 1998-99 (till Dec 98) as against 15352 Mt. during 1997-98. Actually in 1998-99 the domestic Phenol production upto Dec 98 was very low i.e. 48703 Mt. (i.e. 5411 Mt. /month) as compared to the normal production of 69281 Mt. (5773 Mt/ /month). This resulted in higher imports upto Dec'98. The production in the last quarter was 17506 (i.e. 5835 MT/month) and thus when the production increased the imports came down drastically and the imports in last quarter of 1998-99 were only 1622 MT. It is thus seen that imports increased in first three-quarters of 1998-99 only because

domestic manufacturers failed to produce adequate quantities. Thus the Safeguard Duty was recommended by Director General (Safeguard) on the apprehension that imports in 1998-99 would go up to 33400 MT. Actual import were however 26,670 MT and that too for meeting the gap between market demand and domestic production. The market share of imported material in 1998-99 was projected to be 36% on the basis of statistics upto Dec'98 where as it was actually 29%. It may be noted that the market share of imported material in 1997-98 was 23%. Thus even before imposition of Safeguard Duty, the increase in the market share of imports was very moderate and that too because of increased market demand from 79708 MT in 1997-98 to 92073 MT in 1998-99 (16% increase).

ix) Imports are growing because the domestic consumption has been increasing whereas the domestic production was not growing in the same proportion, which resulted in increased imports to fill in the gap between domestic demand and supply. As per working group set up by erstwhile Department of Chemicals and Fertilisers, Govt. of India the projected demand of Phenol for 9th Five year plan is 1,45,000 MTA by 2001-02 and 2,49,000 TPA by 2006-07. This shows there is a big demand in India. Therefore, the manufacturers can not claim falling market share as a reason for seeking protection.

x) HCL consumes phenol for its captive requirement and has also imported Phenol. HCL should have produced extra quantity to meet its requirement and increase its capacity utilisation, which only shows that HCL can not produce more and its capacity utilisation is at its best.

xi) The closing stocks of imported materials are not substantial, which shows that the imports are resorted to only for actual requirements and the closing stock of domestic production is even less than the closing stock of imported material as reflected in the application which shows that the domestic production was being sold without any difficulty. The domestic manufacturers are not suffering because of increase in imports but on the other hand the consumers are required to import Phenol because of inability of the domestic manufacturers to supply the same. Thus, the consumers of Phenol have to import Phenol for their requirements over and above the domestic supply and have to unnecessarily pay higher price due to imposition of safeguard duty which makes their cost of production non competitive in international markets and also makes their capacities remaining underutilised and their operations non profitable.

xii) The closing stock with the manufacturers is not high and the same works out to 7 days production for the year 1999-2000 and 4 days production for the 8 months during the year 2000-01. Even prior to the imposition of Safeguard Duty the closing stock for the year 1997-98 was 12 days production and for the year 1998-99 it was 14 days production which is a normal stock level for bulk chemicals.

xiii) The total consumption of Phenol is steeply increasing from the year 1997-98 onwards. In fact the demand will be much more if the price of Phenol is at a reasonable level to enable the down stream producers to use their full capacities which is not presently possible since their end products are getting imported at a cheaper prices in India.

xiv) There is a limit up to which the domestic manufacturers of Phenol can increase their production under the existing capacities whereas the consumption will go on increasing and the manufacturers should not have a grudge that their market share is going down. There has been no serious progress made in setting up new capacities by the domestic manufacturers.

xv) Due to increased demand for Phenol in Indian market and non-increase of domestic production the consumers have to import higher quantity of Phenol paying higher import duty due to imposition of Safeguard Duty. This, however, provided additional cover for the indigenous manufacturers to increase their prices without taking steps to improve their efficiency for additional production or reduction in cost of manufacture. When the domestic manufacturers cannot meet the market demand even after selling their entire material they can not complain about increasing imports and ask for continued protection by way of safeguard duty which is being used only as a cover to increase their sales prices and make undue profits.

xvi) With the imposition of Safeguard duty, the domestic manufacturers of Phenol have gained unintended benefit of Rs.5738/= PMT due to increase in price of Phenol and exchange rate escalation. The depreciation of rupee coupled with an increase in the price of Phenol in last two years has ensured sufficient protection to the applicants.

xvii) It is seen that applicants have calculated the allocated raw material cost at different consumption norms varying between 0.554 per MT to 0.723 per MT for Benzene and 0.255 per MT to 0.394 per MT for Propylene as against applicant's data of average consumption for Benzene of 0.606 and of Propylene 0.348. This is not based on any recognised industry standards. The average consumption norms are higher than 0.538 per MT. and 0.300 per MT given by UOP (International Technology supplier). Thus the average consumption taken by the applicants is higher by 12.4% in case of Benzene and 16% in case of Propylene. The higher consumption ratio exposes inefficient operating level of the applicants, which has prevented them from being more competitive vis-à-vis Imports. If the applicants improve the consumption ratios their average allocated raw material cost will go down from US\$306.95 to US\$ 268.35 i.e. US\$38.60. The Cost Adjusted Phenol price would correspondingly go up which will increase their profitability. This shows that the manufacturers should concentrate on improving their efficiency instead of penalising the customers by asking for safeguard duty protection.

xviii) It will also be seen from the details of Raw material prices and Phenol sales prices from 1994-95 to 2000-01 that both the manufacturers have

recovered substantial contribution throughout this period. The contribution in case of HOCL ranged from Rs. 20440 to Rs. 28187/MT whereas in case of HCL it was Rs. 19559 to Rs. 29890/MT. The manufacturers have not only recovered fully the increased cost of raw material but also increased their profitability margins.

xix) The details of CIF price of imported phenol, total import price with duty and HOCL's and HCL's prices for the years 1994-95 to 2000-01 will reveal that the CIF prices went up from Rs.19614 to Rs.26825 (37%) and correspondingly HOCL's sales price also went up from Rs.32184 to Rs.45810 (42%) and HCL's sales price from Rs.33008 in 1994 -95 to Rs.47513 (44%) in 2000-2001. Thus there was no loss to the manufacturers due to international prices. Their prices were always adjusted to the total import prices.

xx) M/s. Phenol Chemie, Germany had stated earlier that there was price erosion of 50% in Phenol market due to continuous technology improvements which are making existing Phenol prices substantially more cost effective. Thus the correct way to face the international competition is to achieve saving in cost of production by technology up-gradation.

xxi) Both the manufacturers had committed in their earlier submission that they would be achieving cost saving of Rs. 6000/= PMT. They have however now stated that all the schemes have not been implemented. Thus, having failed to implement the adjustment plan there is no case for their asking for further extension of Safeguard duty protection.

xxii) Though the cost adjusted Phenol price has not gone up, the price in absolute terms has gone up from USD 450 to USD 670 per MT. This has given indirect benefit to the manufacturers due to increased prices in form of additional quantum of duty as well as increased US Dollar rate in terms of Indian Rupee. When 22% Safeguard Duty was introduced in June'99 the benefit accrued to Phenol manufacturers was Rs. 3798 in form of Safeguard Duty and Rs. 9744 in form of import duty protection excluding CVD. When the rate of Safeguard Duty was reduced from 22% to 15% in March 2000, the benefit by way of Safeguard duty has actually gone up to Rs. 3811 and the reduction in rate of safeguard duty did not affect the phenol manufacturers. The import duty protection excluding CVD increased from Rs. 9744 to Rs. 12476. In Dec 2000 the safeguard duty benefit worked out to Rs. 4729 against Rs. 3798 when the safeguard duty was introduced even though the rate has been brought down from 22% to 15%. The import duty protection has further gone up to Rs. 15,482 without CVD.

xxiii) The Phenol manufactures, thus already got unintended additional cover of Rs.5738/MT (Rs. 15482 - Rs. 9744) due to dollar escalation and increased international prices of Phenol. If this is added to the cost saving which was promised by Phenol manufacturers of Rs.6000/MT, then they have already got much higher protection than the intended protection. Even if the Safeguard

duty is removed, the import duty protection will still be Rs. 10534 (i.e. BCD + Surcharge @ 27.5% (8669) plus SAD @ 4% (1865).

xxiv) HOCL has been making profit in its Kochi Plant since inception, and when the earlier safeguard duty application was made in 1998-99 there was no loss but a profit of Rs 18.3 crores which has increased to Rs. 36.5 crores in first 9 months of 2000-01. The performance of phenol plants of HCL & HOCL should be counted as individual entities whose profits are eaten away by their other inefficient plants wherein they have made substantial unproductive investments. The sole intention of asking the Safeguard Duty was to earn extra benefit at the cost of Phenol consumers.

xxv) The domestic Phenol manufacturers have cited creation of additional Global capacity which fact was known to them at time of their first application during 1998. Director General (Safeguards) had suggested Safeguard Duty to meet the challenge of the new capacities as per their earlier application. Actually the increase in Phenol capacities was done to meet and match the increased global demand of Bisphenol- A and other Phenol end products.

xxvi) The crude oil prices have started coming down to the level of US\$ 25/barrel. Moreover the increase in crude price has affected many industries the world over and such market forces are to be faced for which no artificial protection like Safeguard Duty can be claimed.

xxvii) The credit being given by domestic supplier is at cost since interest at 19 % is recovered for delayed payment. In fact the normal credit period is reduced from 90 days 60 days by HOCL. There is no increase in Debtors as a percentage of sales value. It is seen that that average sales price of HCL has gone up by 35.01% and HOCL by 36.97% in the year 2000-01 as compared to 1999-2000. The Phenol manufacturers are imposing strict credit terms and insist on Bank Guarantees for allowing credit. They are in a sound financial position to dictate the terms of sale.

xxviii) In the earlier application HOCL had mentioned that their credit period has increased to 69 days. Presently HOCL does not supply Phenol to any of its customers with a credit period extending 60 days, and if credit is given beyond 60 days it is with interest cost, this should have improved their cash flow and solved their cash crunch.

xxix) The manufacturers had given an Adjustment plan to achieve cost reduction of Rs. 6000/= PMT and they have confirmed that they have implemented the same. They have also received unintended benefit of increase in the international price and exchange rate fluctuations. They cannot thus have any valid reason to ask for an extension of Safeguard duty protection.

xxx) Both the manufacturers have got sufficient experience and have built up substantial reserves from past operations to withstand international competition under normal duty protection by technological innovations. They have also got

benefit of Safeguard Duty for 24 months. Thus there is no case to continue Safeguard duty benefit any further.

xxxi) The schemes committed in the Adjustment Plan on the basis of which Safeguard Duty was recommended by Director General (Safeguard) do not appears to have been implemented and if at all they had implemented as vaguely stated by them the reduction in cost of production does not warrant imposition of SGD.

xxxii) The flight of competent and skilled manpower can not obviously be due to performance of Phenol plant but can be due to many other reasons since both the units are making substantial profits in Phenol plant. It is also seen from their application that the reduction in manpower is only 5% in 8 months, which can be due to the trend in every industry to reduce its manpower cost to maximise efficiency. It may be mentioned that Mitsui operates its 200000 TPA plant with only 80 persons and Phenol Chemie operates its 400000 TPA plant with 125 persons. On the same lines, HCL has reduced its manpower costs and HOCL has planned its VRS scheme to reduce its manpower cost from 9% to 10% of total cost to lower level since industry average is 5% to 6% and global average is 2% to 4%.

xxxiii) A fair Phenol selling price of US\$ 991 is totally unjustified when the average international Phenol price for April 2000 to Nov 2000 was US\$ 624. It is requested that the details of this US\$ 991 price may be made available to all the affected parties so that the same can be examined in a transparent manner. The Plants of the two manufacturers have been fully depreciated and they have achieved substantial profit on these plants in the past. They are thus in a position to achieve full capacity utilisation with maximum efficiency to face international competition with normal duty protection. The manufacturers have also got unintended additional benefit of Rs.5738/- PMT due to increase in international prices of Phenol and dollar rate escalation. Thus further extension of the Safeguard Duty is not at all justified. If such extension is granted, it will only result in price hikes by Phenol manufacturers and under utilisation of capacities of Phenol user plants.

xxxiv) The ability to borrow and the share prices depend upon the overall performance of the Company and since Phenol was being sold at a profitable price, the losses made by the Company were on account of other products and not due to Phenol.

xxxv) The claim of increase in effective Phenol capacity can not be accepted as the capacity shown in latest Annual report of HOCL continues to be 40000 TPA. The adjustment plans submitted for continued imposition of safeguard duty is absolutely vague, without any realistic time frame and commitment. There is no provision in HOCL's Annual budget estimates for the capital expenditure involved. Similarly no convincing details have been supplied regarding technology up-gradation. It is not known whether any Feasibility Report duly supported by their Licensors or well known consultant has been

prepared in absence of which the achievement of targeted saving could be assessed.

xxxvi) The Annual Report of HCL for the year 1997-98 contains a statement by its Directors that the project of co-generation has been nearly completed during 1998 and the Gas turbine generation has commenced smooth operation. In the findings of Director General (Safeguard) also it was mentioned that the facility of co-generation has been installed and would get established in 1999. It is not understood how HCL is showing the scheme under the Adjustment Plan to be carried out during the period of Safeguard Duty protection when it was already implemented before the hearing of the first application. It is seen from HCL's Annual report of 1999-2000 that the cost of power per KWH as per own generation is Rs. 4.23 for DG set and Rs. 3.34 for Gas turbine based on naphtha against Rs. 6.37 for purchased power. This shows that major savings were achieved by captive power generation. In fact saving could have been much more if costlier fuel naphtha had been substituted by cheaper fuel as has been done by many other power plants.

xxxvii) It was submitted by the applicants before the Director General (Safeguard) that with procurement of Propylene at JNPT port and new technology for Cumene the raw material prices will be reduced. There is no mention of the progress on any such definite scheme and the savings achieved. These details may be called for as it has been now stated that the benefit is neutralised because of an increase in crude prices. However crude prices have since come down and HCL may be asked to quantify the benefit achieved in this regard.

xxxviii) The adjustment plans submitted by both HOCL and HCL are an eye wash which even on paper, leave alone actual implementation, inspires no confidence and seriousness. Vague and general statement, totally lacking in details and particularly unsupported by evidence and material have been made to create false impression about the proposed adjustments, only with a view to somehow ensure continued levy of Safeguard Duty.

In addition to the above, some of the interested parties have stated as under :-

a) M/s Kesar Petroproducts Limited, Mumbai

The imported price of Phenol for Dec 2000 was US\$ 670 per MT and not US\$ 610 as per actual imports made by them and the cost adjusted Phenol price would work out to US\$ 489.

An analysis of Article 7 of the Agreement on Safeguards shows that the word "Review" has been used in the context of a measure that has been applied for a period exceeding three years. In case where the measure is applied for less than three years, as in the present case, the Authority has already determined that the said shorter period is adequate to prevent or

remedy serious injury & to facilitate adjustment. In such a case, to extend the period of application of the Safeguard measure amounts to the application "again" on the import of the product. This cannot be done unless a period of two years had elapsed after the initial imposition.

Rules 16 & 18 of the Safeguard Duty Rules deal with the above aspects. In terms of Rule 16(2), a Safeguard Duty levied in terms of Rule 12 ceases to have effect on the expiry of four years from the date of imposition, unless revoked earlier. Since the Director General recommended the Safeguard Duty for two years only and the Central Government imposed the duty also for two years i.e. upto 29.06.2001, the duty shall cease to have effect on that day unless revoked earlier. In other words, rule 16(2) empowers the Director General only to revoke the Safeguard Duty earlier to 29.06.2001.

Rule 18 deals with the situation where the Director General undertakes a review, during the time the Safeguard Duty is in operation. This review is to determine whether the said duty should be continued for the period originally intended or it should be withdrawn or the process of liberalisation should be increased. It does not deal with the situation where the Director General can extend the duty beyond the period for which it was originally recommended. The power of the Director General was only to examine whether the said period of two years could be curtailed or not and the Director General has no powers to extend this period of imposition. Extending the period of imposition will amount to imposing the duty again akin to initiating a new investigation.

(b) Alta Laboratories Ltd., Mumbai

They are the manufacturers of Aspirin (Acetyl Salicylic Acid I.P.) and Phenol is our basic raw material for manufacturing this product. Our annual consumption of Phenol is approximately 1200 M. Tons. The price of Aspirin is statutorily controlled by the Government under DPCO 1987. Phenol being the main raw material for manufacture of this product, the cost of Phenol has a direct bearing on the price of Aspirin. During the last 12 months the applicants have raised their selling prices almost by 55% in stages. Due to unusually high price of Phenol charged by indigenous manufacturers during the last three years, They have incurred losses as their selling price is revised by the Government once in three years and the process of getting interim relief is lengthy and laborious. There is always inordinate delay between the escalation in the cost and the revision of price.

c) Schenectady Specialties Asia Ltd., Mumbai

(i) They are a joint venture company between Schenectady International Inc. (SII) of USA (the world's largest manufacturer of Alkylated Phenols) and Sunshield Chemicals Ltd. (SCC) a listed company manufacturing speciality chemicals. They manufacture with the state-of-art technology widest range of Alkylated Phenols which finds its use in various vital and core sectors.

(ii) Phenol is the basic raw material, accounting for 50% of their raw material input for manufacture of Alkylated Phenols, and its purity, reliable quality and competitive prices are of utmost importance to the successful quality production of their products. They consume about 3000 MT of Phenol per annum.

(iii) Besides Phenol, Herdillia Chemicals also manufacture Alkyl Phenols and if they get an opportunity to hike the price of Phenol it will no more remain viable to manufacture Alkyl Phenols in India by others. In such a situation, the Alkyl Phenols Industry will become a total monopoly of Herdillia and end product industry such as Surfactants, Antioxidants which go in Agriculture, Textiles, Pesticides, Plastics, Food and many more industries producing day to day necessities of Indian public will also become cost inefficient.

(iv) The manufacturers of Phenol have reaped the benefits of their investments and have over the years invested these amounts into unrelated diversification without re-investing into improving their plant economics or building economic size Plants.

(v) They have requested to allow "sector specific exemption" to Alkyl Phenol manufacturers so as to ensure a level playing field for them.

d) XPRO India Limited, Mumbai

Safeguard Duty should be imposed only for the indigenous manufacturers to gain time and to be more competitive vis-à-vis imports. From the submission made by the applicants, it is clear that Phenol manufacturing can really be economical only if world size efficient Plants are in operation. There is no indication that the two domestic manufacturers will be going in for such a plan. They have put in abeyance their earlier plans of putting a new Plant and therefore nothing substantial will occur to make the domestic manufacturers globally competitive.

e) Colour-Chem Limited, Thane

The import duty on finished product namely leather chemicals / leather goods is less than the duties on raw material Phenol. They have lost their business since the leather industry prefers to import leather chemicals being cheaper than indigenous products manufactured by them due to lower import duties.

E. VIEWS OF DOMESTIC PRODUCERS

The domestic producers have made the following main points:

(a) M/s. Hindustan Organic Chemicals Ltd., Cochin.

(i) They have their manufacturing units at (1) Rasayani-410027, Distt. Raigad Maharashtra (2) Ambalamugal-682302, Distt. Ernakulam, Kerala and Phenol plant is located at Ambalamugal only.

(ii) They manufacture Basic Organic Chemicals namely Phenol also known as Carboic Acid or Hydroxy Benzene, Acetone, Aniline, Nitrotoluenes, Nitrochlorobenzenes, Monochlorobenzene, Formaldehyde, Nitrobenzene, Sulphuric Acid, Cyclohexylamine, Acetanilide, Caustic Soda, Hydrogen Peroxide, Butene-1, 4-Diol.

(iii) Phenol manufactured by them, both Crystal and Hydrated form, is used in the manufacture of Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Pharmaceuticals, etc. In the manufacture of Leather Chemicals, Bisphenol-A and Alkyl Phenols only Crystal form of Phenol is used.

(iv) Benzene and Propylene are the major raw materials while Cumene is an intermediate in the manufacture of Phenol. Acetone is formed as a co-product in the manufacture of Phenol. Phenol and Acetone are formed in the ratio of 1:0.6.

(b) Herdillia Chemicals Ltd. Mumbai

(i) They manufacture Basic Organic Chemicals and Specialties like Phenol, Acetone, Phthalic Anhydride, Diacetone Alcohol, Dodecyl Phenol, Nonyl Phenol, Diphenyl Oxide, Isobutyl Benzene, Isophorone, Heat Transfer Media, Acetophenone.

(ii) There are two grades of Phenol manufactured by them namely Crystalline and Hydrated. Whereas Crystalline Phenol is solid Phenol in crystal form, hydrated Phenol is a composition of Phenol and water with a percentage of water being less than 10%. Due to this, Phenol remains in molten form even in ambient or cold conditions and simplifies material handling procedure by the end users during unloading. The purity of Crystalline Phenol is minimum 99.5% by weight. However, the billing of Hydrated Phenol is done on the basis of the actual Phenol content in the material.

(iii) Phenol is used in the manufacture of Phenol Formaldehyde Resins, Laminates, Plywood, Particle Boards, Bisphenol-A, Alkyl Phenols, Pharmaceuticals, Diphenyl Oxide etc. Applications such as Leather Chemicals and Bisphenol-A normally require only Crystalline Phenol.

(iv) The imported Phenol and the Phenol manufactured by them is same in all respects. The Phenol produced in India is of International standard and has been well accepted in the global market.

(v) Phenol facility of 10,000 TPA capacity was set up in the 1960s and became operational in 1968. Initial investment in the Phenol manufacturing facility was Rs.3.31 crores. Over a period of time, the capacity was increased to well over 20,000 TPA till the end of the fiscal year 1996-97 through investments in debottlenecking financed entirely through internal accruals. The capacity of the plant during 1999-2000 was 32000 TPA & the present capacity of the Phenol plant on an annualised basis is 34000 TPA.

(vi) Packing cost for Phenol was around Rs.3.5/Kg. for the year 1995-96, Rs.3.75/Kg (Average) for the year 1996-97, and Rs.4/Kg for the years 1997-98. This is approximately the difference between the net sales realisation of Bulk and packed Phenol. The selling price of Phenol is based on the landed price parity and not on a cost plus basis concept. As a result there is no correlation between the raw material cost and the selling price.

(vii) Even though the price realisations in absolute terms have shown an increase after the very low levels of past safeguard duty investigation period, the net price realisation after deducting the cost increases have shown a decline.

(viii) Despite the safeguard duty in force the loss of employment per ton of Phenol production has been to the tune of 19.86% between 1998-99 & April-November 2000.

(ix) They have not exported Phenol during the years 1998-99, 1999-2000 & 2000-01 (upto November 2000)

In addition to the above, the domestic producers have also stated broadly the following :

(a) Phenol is being imported into India primarily from Belgium, Chinese Taipei, Germany, Italy, Japan, Korea DPR, Korea RP, the Netherlands, Russia, Singapore, South Africa, U.K. and USA. The imports have shown an increasing trend in absolute terms as well as compared to domestic production. The imports and domestic production of Phenol during 1994-95 to 1999-2000 have been as under:

Year	Domestic production (MT)	Import (MT)	Imports as %age of domestic production
1994-95	57780	6664	11.53
1995-96	63719	21752	34.14
1996-97	57466	19545	34.01
1997-98	69281	15352	22.16
1998-99	66210	26670	40.28
1999-2K	69961	28992	41.44

(b) Besides HOCL and HCL, there is only one manufacturer of Phenol in India (Neyveli Lignite Corporation Limited) whose capacity is 1500 TPA and production lower than 1000 TPA. The total domestic production of Phenol in the country is thus accounted for by HOCL & HCL.

(c) The imports during the first eight and half months i.e. April to December (first half) 2000 – have been reported to be 18247 MT. They have stated that the imports have been increasing sharply in November and December 2000. The import data furnished by them for the period 1998-99 and 1999-2000 are based on market intelligence sources.

(d) The capacity utilisation of domestic producers to meet with the domestic demand which increased from 85% in 1996-97 to 89% in 1999-2000 declined to 83% in the first 8 months of 2000-01. They made successful efforts to enhance their effective production capacities, even though the benefits of safeguard duty did not accrue in terms of additional funds for making investments for such expansions. Forced by cash crunch, HOCL had to take shutdowns in the months of April, June and October 2000 due to which, production volumes were lower in these months in comparison with the enhanced capacity levels.

(e) Their market share of Phenol in the total domestic consumption of Phenol which increased from 74.3% in 1996-97 to 80.25% in 1997-98 declined to 71.13% and 70.75% in the year 1998-99 and 1999-2000. They have also stated that they are facing depressed conditions of performance in spite of imposition of safeguard duty on Phenol.

(f) The investigation carried out during the first half of 1999 was based on the facts of the situation existing at that point of time. Thereafter, the situation in terms of sustained high level of imports has continued unrelentingly and imports have still been coming at prices which are even lower than the September 1998 levels when adjusted for mere Raw Material cost increases.

(g) Even though the absolute price levels at which Phenol is being imported showed some increase in the period since October 1999, the increase is highly deceptive as the same has been forced by phenomenal increase in the cost of raw materials and fuels. Phenol prices are lower than the raw material cost escalation adjusted price (computed in comparison with September 1998 price and raw material costs.) Considering costs versus prices, the prices in 1999-2000 and in 2000-01 have generally been lower than the lowest prices existing (till then) in second half of 1998. Phenol is being imported into the country at prices, which are lower than the price levels of 2nd half of the year 1998.

(h) The increase in international prices of inputs like Benzene, Propylene and Cumene has led to an increase in the domestic input prices as well for manufacture of Phenol. HCL continued to make losses on Phenol manufacture in 1999-2000 (despite Safeguard Duty in force) and in respect of HOCL, the profits were far short of even the mere incremental profit accrued on

account of Safeguard Duty imposition. The marginal profit of April – November, 2000 will turn into losses in the event of withdrawal of Safeguard Duty.

(i) The increase in crude oil prices from USD 10/Barrel in early 1999 to the present levels of nearly USD 30/Barrel coming at a time of global over capacity for Phenol certainly was not foreseeable. The resultant sudden and significant increase in prices of raw materials and fuels at the time of global Phenol over capacity has led to Phenol being exported at significantly low levels of 'cost adjusted Phenol prices'. As a sequel the domestic prices when adjusted for cost increases have dwindled further after the earlier period of investigations. The cost adjusted Phenol price has gone down by 19% and 13% during Sept. 1998 to November, 2000 in respect of HOCL & HCL respectively.

(j) The size of the Indian market and the consequent size of the domestic Phenol producing industry are both lower than 2% of the size of the global Phenol producing industry. Since Phenol is freely importable, they have no control what so ever on the Indian Phenol prices which get decided entirely by the world majors in this business.

(k) The imports are being made at extended credit period, which is also a cause of serious injury to the domestic industry. As a result of long credit periods on imports, the domestic producers are required to either give a cash discount for prompt payment on domestic sale or are required to offer long credit periods.

(l) Despite implementation of adjustment plan being on schedule, the impact of cost reduction schemes has been more than neutralised by the increase in raw material and fuel costs which led to an overall cost escalation. Imports are coming at prices that would render the domestic manufacture of Phenol unviable.

(m) The savings in Variable Costs due to improvement in operating efficiency could not be realised because the increase in prices of inputs more than neutralised the impact of operation efficiencies achieved. On the fixed cost front also, even though debottlenecking led to higher capacities but the actual production levels did not increase primarily due to sustained increased level of imports and also because of Force Majeure circumstances. There has been instances when production of HCL suffered when the public sector refineries, from whom they procure essential raw materials, took shut down without adequate notice and also the oil companies withdrew all credits and discounts leading to increase in working capital requirement.

(n) Due to poor financial performance caused by the import prices being lower than even the mere cost adjusted import prices, the banks were reluctant in sanctioning additional working capital limits. In fact HOCL due to cash crunch had to take shut downs in the months of April, June & October, 2000 due to which their production volumes were lower in these months in comparison with the enhanced capacity levels

(o) The total outstanding of the domestic industry on sale of Phenol and Acetone between April 1999 to November 2000 have increased by 36% due to high credit periods enjoyed by the importers.

(p) Due to the dismal situation caused by sustained increased imports, the flight of competent, skilled manpower has continued in the domestic Phenol and Acetone industry.

(q) The size of the Indian market being small in comparison with the global market size, Indian import parcels are transacted on 'spot basis'. Spot prices most often tend to be significantly lower than the contract prices. Due to this reason, the CIF India arrival prices of Phenol are often lower than the prices prevailing in the developed world/major Phenol producing regions. In a falling price regime, domestic prices are fixed based on expected landed price parity to prevent further booking of material. Hence, the domestic prices always tend to be lower than the actual landed cost of import. However, in a situation in which import prices are increasing, the domestic prices cannot be fixed based on the expected or even actual landed price parity. This is because the stock of the material imported at lower prices (prior to the increase in prices) determines the domestic prices so long as these stocks remain. These prices also tend to be lower than the actual arrival prices of import. The domestic industry thus suffers till prices adjust to a reasonable level and remain steady.

(r) It has been contended by some of the parties that additional production of Phenol globally will be consumed by additional capacity of Bisphenol-A (BPA) which are currently being set up in different parts of the world. The consumption of Phenol will depend on actual consumption for BPA (and other end-uses) and not on the production capacity of BPA. Hence, the new capacity of BPA is likely to take away BPA's market share from the current producers and the requirement of Phenol for manufacture of BPA will increase only at the realistic growth rate of BPA. Even after considering the impact of growth in Phenol for Bisphenol-A segment, the overall Phenol demand growth rate is estimated at not more than 4% per annum according to some of the agencies of international repute like CMAI, Chem Systems, Phenolchemie and Shell.

(s) They have requested for continued imposition of safeguard duty on imports of Phenol for a further period of 3 years from July 2001 to prevent serious injury to the domestic Phenol manufacturing industry and to help them to adjust to the extremely difficult situation created by excess global capacity of Phenol combined with significant increase in raw material costs.

F. FINDINGS

I have carefully gone through the case records and the replies filed by all interested parties including the domestic producers, users/importers and exporters. Submissions made by various parties and the issues arising

therefrom are dealt with at appropriate places in the findings below. However, before proceeding to discuss the merits of the case it is considered necessary to discuss a preliminary issue concerning Rule 18 of Customs Tariff (Identification and Assessment of Safeguard Duty) Rules, 1997 hereinafter referred to as SGD Rules.

It has been averred by some of the interested parties that Rule 18 of the SGD Rules deals with the situation where the Director General undertakes a review, during the time the Safeguard duty is in operation. This review is to determine whether the said duty should be continued for the period originally intended or it should be withdrawn or the process of liberalisation should be increased. It does not deal with the situation where the Director General can extend the duty beyond the period for which it was originally recommended. The power of the Director General was only to examine whether the period of two years for which the Safeguard Duty on Phenol was imposed initially could be curtailed or not and the Director General has no powers to extend this period of imposition. Extending the period of imposition will amount to imposing the duty again akin to initiating a new investigation.

It has been argued that Article 7 of the Agreement on Safeguards stipulates that a review of safeguard measure is contemplated in the context of a measure that has been applied for a period exceeding three years. In a case where the measure is applied for a shorter period, as in the present case, extension of the period of application of the safeguard measure amounts to the application again of the measure on the import of the product, which can not be done unless a period of two years had elapsed after the initial imposition. It has been further argued that Rule 18 of the Safeguard Duty Rules deals with the situation where the DG undertakes a review, during the period the safeguard duty is in operation. This review is to determine whether the said duty should be continued for the period originally intended or it should be withdrawn or the pace of liberalisation be increased. It does not deal with the situation where the DG can extend the duty beyond the period for which it was originally recommended. Besides, the DG had examined the status of the domestic industry and came to the positive conclusion that it required two years to remedy serious injury and to facilitate adjustment. Consequently, the power of the DG is only to examine whether the said period of two years could be curtailed or not. The DG has no power to extend this period of imposition.

This is an important aspect and needs to be examined in the context of the scheme of safeguard law as envisaged under the provision of Custom Tariff Act, 1975 and the Safeguard Duty Rules, which reflect the provision of the Agreement on Safeguards.

Paragraph 1 of Article 7 of the Agreement on Safeguards stipulates

“A Member shall apply safeguard measures only for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate

adjustment. The period shall not exceed four years, unless it is extended under paragraph 2".

Paragraph 2 of Article 7 reads

" The period mentioned in paragraph 1 may be extended provided that the competent authorities of the importing Member have determined, in conformity with the procedures set out in Articles 2,3,4, and 5, that the safeguard measure continues to be necessary to prevent or remedy serious injury and that there is evidence that the industry is adjusting, and provided that the pertinent provisions of Articles 8 and 12 are observed."

A plain reading of the last sentence of paragraph 1 of Article 7 makes it abundantly clear that the period of initial imposition of a safeguard measure shall not exceed four years and that this period can be extended under paragraph 2. Similarly paragraph 2 makes it clear that the period under paragraph 1 can be extended subject to fulfillment of certain conditions. Paragraph 1 specifically requires the period of initial application of a safeguard measure to be not exceeding four years i.e. it can be any period which is four years or less. And this period of upto four years can be extended in accordance with the provision of paragraph 2 *ibid.* Article 7, therefore, in no way requires the period of initial application of a safeguard measure to be a definite period to be eligible to be extended further.

Further paragraph 4 of Article 7 reads as under:

"In order to facilitate adjustment in a situation where the expected duration of a safeguard measure as notified under the provisions of paragraph 1 of Article 12 is over one year, the Member applying the measure shall progressively liberalize it at regular intervals during the period of application. If the duration of the measure exceeds three years, the Member applying such a measure shall review the situation not later than the mid-term of the measure and, if appropriate, withdraw it or increase the pace of liberalization. A measure extended under paragraph 2 shall not be more restrictive than it was at the end of the initial period, and should continue to be liberalized."

This paragraph focuses upon the need to liberalise a safeguard measure, if the period of application of a safeguard measure is more than one year. It also mandates a mid term review if the period of application of the safeguard measure exceed three years. The purpose of this review is to consider whether the pace of liberalisation be increased or the measure be withdrawn. The last sentence of Paragraph 4 envisages the process of liberalisation to be ensured even in cases where the safeguard measure is extended under paragraph 2.

The above provision of Article 7 of the Agreement on Safeguards have been incorporated in Rule 18 of the Safeguard Duty Rules, which is reproduced below.

“(1) The Director General shall, from time to time, review the need for continued imposition of the safeguard duty and shall, if he is satisfied on the basis of information received to him that :

- (i) safeguard duty is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, it may recommend to the Central Government for the continued imposition of duty;
- (ii) there is no justification for the continued imposition of such duty, recommend to the Central Government for its withdrawal:

Provided that where the period of imposition of safeguard duty exceeds three years the Director General shall review the situation not later than the mid-term of such imposition, and, if appropriate, recommend for withdrawal of such safeguard duty or for the increase of the liberalisation of duty.

2. Any review initiated under sub-rule (1) shall be concluded within a period not exceeding 8 months from the date of initiation of such review or within such extended period as the Central Government may allow.

3. The provisions of rules 5, 6, 7 and 11 shall *mutatis mutandis* apply in the case of review.”

Rule 18 requires the DG, from time to time, to review the need for continued imposition of the safeguard duty, incorporating the relevant provision in this regard, both of paragraph 2 and paragraph 4 of Article 7 of the Agreement on Safeguards. The provisions of Rule 18 in no way limit the power of the DG to restrict himself, in a review only to the initial period of imposition. On the contrary, it specifically empower the DG and requires him to recommend for the continued imposition of duty if;

- (i) the same is necessary to prevent or remedy serious injury, and
- (ii) there is evidence that the industry is adjusting positively. The above interpretation also finds support from the language of Rule 16 wherein first proviso to sub rule 2 reads:

“ Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard duty should continue to be imposed, it may extend the period of such imposition”.

In this proviso the expression “ ... safeguard duty should continue to be imposed it may extend such period” has clearly been used in the context of extension of the safeguard duty beyond the initial period of imposition.

In view of the above discussion, there is no merit in the argument that the DG has powers only to examine whether the period of initial imposition

should be curtailed and that the DG has no power to recommend extension of this period of initial imposition.

As per Rule 18 of Safeguard Duty Rules the essential requirements to be satisfied for a continued imposition of Safeguard duty is that it should be necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively. And, if there is no justification for the continued imposition of such duty, recommendation for its withdrawal needs to be made. The law itself provides a mechanism for review of Safeguard Duty and sets out a standard by which the necessity for such a continued imposition needs to be examined. If the conditions are met with, continued imposition of Safeguard Duty is justified.

As regards the merits of the case, in the present case, it was found that the imports of Phenol into India increased from 6664 MT in 1994-95 to 15312 MT in 1997-98 and to 24550 MT in the first nine months (April to December) of 1998-99. The increased imports of Phenol caused a decline in domestic production of Phenol which had registered a growth of about 16.1% in 1997-98 over 1996-97. The decline in 1998-99 over 1997-98 was 6.69%. Similarly, the domestic producers suffered a loss of 10.31% age points in the capacity utilisation in 1998-99 (April-Dec.) over 1997-98. They registered a marginal growth in domestic sales of 3.38% in 1998-99 (April-Dec.) over 1997-98 as compared to a growth of 25.1% in the apparent domestic consumption during the relevant period. Even this small growth was achieved only at the cost of a drastic reduction in their average sales price which was reduced to Rs.28/- per Kg. in December 1998 as compared to Rs.37/- per Kg. in January-March 1998. They had to reduce the list price of Phenol and offer various additional discounts to prevent their customers from shifting to imports completely. The reduction in net sales realisation had serious effect on profitability of the domestic industry and both HOCL and HCL started incurring losses on their Phenol operation. HOCL suffered a loss of Rs. (Confidential) per MT and HCL suffered a loss of Rs. (Confidential) per MT in December 1998, which in turn depressed their share prices, as well. It was further found that the domestic industry suffered also on account of some increase in inventory, loss of employment and loss in productivity.

The domestic industry thus witnessed severely depressed conditions of Phenol operation in the first three-quarters of 1998-99.

As regards the effort on the part of the domestic industry to make positive adjustment, it was observed that the existing facilities in HCL were built in the pre-liberalisation, MRTP era which led to high fixed costs due to lack of economy of scales. The domestic producers however undertook to regularly upgrade technology and debottleneck their manufacturing facilities with the objective of enhancing their capacities and thereby reducing the operative costs. They also took steps to reduce power cost by setting up captive power generation facilities by the co-generation route, which was to stabilise by 1999. The other cost reduction measures included improvement in quality of

feedstock, increased availability of Propylene and state of the art Zeolite technology for the production of Cumene etc.

Continued threat of Serious injury

The imports of Phenol into India were 26670 MT in 1998-99. In spite of safeguard duty having been imposed on Phenol on 30th June 1999 @ 22% advalorem, the onslaught of imports of Phenol continued unabated and increased further to 28992 MT in 1999-2000 (as per DGCIS data, the imports were 29302 MT, which is slightly, more than 28992). As per the information provided by the applicants, the imports of Phenol till mid-December, 2000 were reportedly 18247 MT which in turn, worked out to an annualised figure of 25760 MT. Doubts were expressed by some parties about the authenticity of import data provided by the Applicants, particularly in respect of import data for the period 2000-01. The domestic producers in this regard have submitted that the data for the years upto 1999-2000 are available with the DGCIS Calcutta. Due to time lag in publication of DGCIS figures, for 2000-01 they have taken the data based on market intelligence sources. As far as 2000-01 data is concerned, the Applicants have provided the details of imports giving the name of the vessel, date of arrival, quantity, name of the importers and import prices alongwith surveyor/insurance reports. On verification of the details it is found that a quantity of 26442.992 MT of Phenol have been imported during the year 2000-01, out of which a quantity of 12510.594 MTs was imported upto November 2000, 8652.173 MTs in December 2000, making it 21162.767 MTs during April-December, 2000. Table-I below gives the details of imports.

Table-I

Year	Imports	Domestic Production	Imports in MT
			Imports as a % of domestic Production
1997-98	15700	69281	22.66
1998-99	25213	66210	38.08
1999-00	29302	69961	41.88
2000-01 (April-Dec.)	21163	52278	40.48

It has been argued by some of the interested parties that sub-rules (3) of Rule 18 stipulates that rules 5, 6, 7 and 11 shall *mutatis mutandis* apply in the case of review and Rule 5 inter alia requires increased imports to cause injury or threat thereof and since there is no increase in imports, there is no case for the safeguard protection.

It has been stated that Rule 5 of the SGD Rules requires that for any initiation of investigation, the Director General must find an increase in imports. In particular, clause 5(3) requires that the Director General shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1) unless he examines the adequacy and accuracy of the evidence provided in the

application and satisfies himself that there is sufficient evidence regarding increased imports; serious injury or threat of serious injury and a causal link between increased imports and alleged injury or threat of serious injury. On the basis of information provided by the Domestic Industry there have been no increase in imports and the information provided by the domestic industry reveals that the domestic production has plateaued in keeping with the market demand conditions. Further under the WTO Jurisprudence if an increase in imports is in fact present this should be evident both in an end-point-to-end-point comparison and in analysis of intervening trends over the period. That is, the two analysis should be mutually reinforcing. Since there have been no increase in imports, there is no basis to impose Safeguard Duty.

In this regard, it is observed that the law requires the provision of Rules 5, 6, 7 and 11 to apply *mutatis mutandis* (emphasis added). Notwithstanding the fact that the actual imports in 1999-2000 were 29302 MT (DGCIS figures), which were the highest during the recent period, one has to consider the quantum of imports during the period 1999-2000 and 2000-01 keeping in mind the fact that safeguard duty was imposed on Phenol imports during this period, the very purpose of which was to give relief to the domestic industry from the injurious imports. One has, therefore, to consider the quantum of imports keeping in mind the impact of the safeguard measure already in force and whether the imports would continue to injure the domestic industry, if the safeguard measure was removed.

The domestic producers during this period produced 69281 MT in 1997-98, 66210 in 1998-99, 69961 MT in 1999-2000 and 45848 MT in April-November 2000. Their year wise production capacity was 66500, 75000, 77000 and 83000 (Annualised) during the said periods. They thus achieved capacity utilisation of 104.18% in 1997-98, 88.28% in 1998-99, 90.86% in 1999-2000 and 82.86% in the first eight months of 2000-01.

Some of the interested parties have stated that if imports were coming into India at higher prices even after payment of Safeguard Duty, it only implied that there is an increased demand for Phenol which the domestic industry was unable to cater and it is this inability of the domestic industry to satisfy this increased demand to the extent of their capacity that imports had to enter into India. In this connection they have stated that Imports are growing because the domestic consumption has been increasing whereas the domestic production was not growing in the same proportion, which resulted in increased imports to fill in the gap between domestic demand and supply. They have also averred that as per the Working Group set up by erstwhile Department of Chemicals and Fertilisers, Govt. of India the projected demand of Phenol for 9th Five year plan is 1,45,000 MTA by 2001-02 and 2,49,000 TPA by 2006-07. The total consumption of Phenol is steeply increasing from the year 1997-98 onwards. In fact the demand will be much more if the price of Phenol is at a reasonable level to enable the down stream producers to use their full capacities which is not presently possible since their end products are getting imported at cheaper prices in India. Due to increased demand for Phenol in Indian market and non-

increase of domestic production the consumers have to import higher quantity of Phenol paying higher import duty due to imposition of Safeguard Duty. This, however, provided additional cover for the indigenous manufacturers to increase their prices without taking steps to improve their efficiency for additional production or reduction in cost of manufacture. When the domestic manufacturers cannot meet the market demand even after selling their entire material they can not complain about increasing imports and ask for continued protection by way of safeguard duty which is being used only as a cover to increase their sales prices and make undue profits.

The above submissions made by the interested parties were got checked up from the Department of Chemicals and Petrochemicals (Ministry of Chemicals & Fertilizers). The Ministry has clarified that no Working Group has been set up by the Department of Chemicals in the recent past, projecting demand for Phenol. However, the Working Group on Petrochemicals under chapter X in its report on "Feedstock & Building Blocks" has made the demand projection of Phenol as 133,000 MT and 229,000 MT for the years 2001-02 and 2006-07 respectively. The Ministry has clarified that these are estimates based on the data on consumption of Benzene more than three years ago. Market realities have since undergone substantial changes. The actual consumption of Phenol in the country, according to the Ministry was 78,093 MT, 88,800 MT and 91,000 MT (Approx.) during the years 1997-98, 1998-99 & 1999-2000 respectively. It has also been stated by the Ministry that the actual demand for Phenol in the country in 2001-2002 may be at substantial variance with the estimates.

There is however, a supply-demand gap that needs to be considered in the context of quantum of imports of Phenol entering into India. The apparent domestic consumption (domestic sales + import) of Phenol in the domestic market was 90923 MT in 1998-99 which increased to 99440 MT in 1999-2000 and stood at 60101 MT for the period April-November, 2000. The applicants, however, have worked out the total domestic consumption of 92073 MT in 1998-99, 95598 MT in 1999-2000 and 64440 MT in 2000-01 (April-Nov.), on the basis of opening stocks and closing stocks of imported Phenol. The Administrative Ministry has reported consumption of 78093 MT, 88800 MT and 91000 MT (appr.) in the years 1997-98, 1998-99 and 1999-2000. While the Ministry has provided a figure of consumption 91000 MT, the apparent domestic consumption works out to 99440 MT in 1999-2000. As compared to these the total domestic consumption figure of 95598 MT worked out by the applicants taking into account the opening and closing stocks appear to be more representative. Thus as compared to domestic production of 69961 MT in 1999-2000 and 45848 MT in 2000-01 (April-November), the total domestic consumption in 1999-2000 was 95598 MT and 64440 MT in April-November, 2000.

The Table below gives details of domestic production, capacity, imports, sales and domestic consumption.

Year	Domestic Capacity	Domestic Production	Capacity utilisation	Domestic Sales	Imports	Domestic Consumption
1998-99	75000	66210	88.28	65710	25213	92073
1999-2000	77000	69961	90.86	70138	29302	95598
2000-01 (April-Nov)	55332	45848	82.86	46363	12510	64440

There was thus a supply demand gap of (95598-69961) 25637 MT in 1999-2000, including that required for use in export production estimated to be about 13500 MT per annum. It is, therefore, evident that certain quantities of Phenol were necessary to be imported to meet with the domestic demand. The applicants have worked out consumption of imported Phenol to meet with the domestic demand taking into account the opening stocks and closing stocks of both the domestic producers and of imported Phenol. According to them the consumption of imported Phenol during 1999-2000 was 25453 MT.

It is, however, observed that as against the consumption of 25453 MT of imported Phenol in 1999-2000, the total imports were 29302 MT during that year which resulted in build-up of stocks of imported material from 3800 MT at the end of 1998-99 to 7339 MT at the end of 1999-2000. It can be inferred from this built up inventory that about 3500MT of Phenol was imported in excess of demand in 1999-2000, which accounts for about 12% of the total imports. With the depletion of stocks of imported Phenol in 2000-01 (April-Nov.), from 7339 MT in April, 2000 to 2000 MT at the end of November, 2000 large quantities have been imported in November and December 2000. As compared to an average of 1419 MT per month till October 2000, the imports of Phenol in November 2000 were 2550 MT and 8652 MT in December, 2000.

The domestic producers, however, sold the entire quantities they produced, which is evident from the fact that the domestic producers sold 70145 MT in 1999-2000 and 47465 MT in 2000-01 (April-Nov.). This became possible due to imposition of safeguard duty which helped the domestic producers to sell the material produced by them.

Imports of Phenol which entered at declining cif prices in 1998-99 continued to be priced between US\$ 400-425 PMT for the earlier period of the financial year 1999-2000. The cif prices of imported Phenol, however, started showing an upward trend from November, 1999 onwards as indicated in the Table below:

Table

Period	Price in (US\$)PMT
November,99	575
December,99	625
January,2000	580
February,2000	580
March, 2000	580
April, 2000	600
May, 2000	610
June,2000	625
July,2000	645
August,2000	625
Sept,2000	635
October,2000	655
November,2000	645
December,2000	610

It has been argued by some of the parties that in the wake of increase in the cif prices of imported Phenol, the domestic producers do not deserve the protection of safeguard duty any further. The increases in the cif import prices of Phenol, however, need to be seen in its proper perspective keeping in view the increases in cost of production as a result of increases in raw material prices etc. It also needs to be considered as to how the increases in cost of production of Phenol have impacted upon the domestic producers and on the cif price of imported Phenol and whether the imported prices fully account for such increases or still undercut the domestically produced Phenol prices.

The main raw materials used in the production of Phenol are Benzene and Propylene. The increase in Crude Oil prices from about US\$ 10 per Barrel in early 1999 to a level of US\$ 30 per Barrel in the second half of the year 2000 has had its impact on the prices of these raw materials. The international Benzene prices were in the range of 200-220 US\$ PMT in the later half of 1998-99 which started rising thereafter and were in the range of 400-418 US\$ PMT in the second half of the year 2000. Similarly, Propylene prices which were in the range of 240-255 US\$ PMT in the later half of 1998-99 and till May 1999, started showing an upward trend and reached in the range of 400-470 US\$ PMT in the second half of the year 2000. The Benzene prices thus increased by about 95% and Propylene prices by about 75%. As compared to these increases in the basic raw material prices, the international prices of Phenol which were in the range of 400-435 US\$ PMT, increased to an average of about 630 US\$ PMT, in the second half of the year 2000, i.e. an increase of about 50-55% only.

In this regard it is also important to observe that the global Phenol capacity has been augmented by over 1.2 million TPA within a very short span of time. The new capacities include that of Phenolchemie in USA (4,00,000 TPA), Aristech in USA (2,00,000 TPA), Shell in USA (2,00,000 TPA) and Formosa in Taiwan (2,00,000 TPA) besides Mitsui at Singapore with 2,00,000

TPA capacity, being in an advance stage of implementation. In percentage terms this means capacity addition of nearly 20% over the present global demand of Phenol. This has resulted in increase in prices of Phenol by only a small modicum of the increase in the cost of manufacture.

It may be observed here that generally the chemical/petrochemical industry sells its production in the domestic market at prices keeping in line with the landed prices of imported material. The domestic producers of Phenol, therefore, have also to buy their raw materials and sell Phenol at par with landed prices thereof. In this context, the domestic producers have submitted that the component of cost of Phenol representing Benzene and Propylene adjusted for the increase in the prices of Benzene and Propylene, has risen from around 203-214 US\$ PMT of Phenol in the second half of 1998-99 to 384-414 US \$PMT of Phenol in the second half of year 2000 i.e. an increase of about 90%. HOCL extracts Propylene from cracked LPG. During the period from September 1998 upto November 2000, the procurement prices of Benzene for HOCL have gone up by 84% whereas the cracked LPG prices have gone up by 103%. The prices of LSHS used by HOCL during this period have gone up by 101% and landed prices of imported cumene have gone up by 104%. HCL faced a price hike of 97% for Benzene and 54% for Propylene. The increase in procurement prices of LSHS, Naphta and fuel oil for HCL during this period was 96%, 104% and 78% respectively. The cumene procurement prices for HCL increased by 118%.

As regards the impact of increase in the raw material prices, it is observed that after making adjustment for the increase in Benzene and Propylene prices, the cost adjusted prices of imported material have shown some improvement in the second half of the year 2000 being in the range of 417-464 US\$ PMT, as compared to 395-435 US\$ PMT in the second half of 1998-99. In the case of domestically produced Phenol, the applicants have submitted that HCL continued to make losses on their Phenol operations in 1999-2000 (despite safeguard duty of 22% levied on the imported Phenol) and HOCL made some marginal profits, (which would have turned into losses but for the safeguard duty). In 2000-2001 (April-November) both the domestic producers have made some profits, with 15% safeguard duty in force, which allowed them to raise their selling prices in tune with landed prices of imported Phenol taking into account the 15% safeguard duty. It is important to observe that both the domestic producers would have incurred losses if the safeguard duty was not levied and would start incurring losses if the safeguard duty is not continued beyond June, 2001. The cost accounts of both the domestic producers have been examined by departmental Cost Account experts and have been found to be in order.

It is also important to observe that the imported Phenol arrives with 90-120 days credit period, which had its impact on the profitability of the domestic producers, as the domestic producers are required to either give a cash discount for prompt payment on domestic sales or are required to offer long credit periods. This has resulted in increasing debtors for both the domestic

producers. The applicants have strongly contended that compression of margins coupled with mounting debtors leads to a cash crisis situation affecting at times the production due to non-availability of cash to finance purchase of raw materials. It is also important to observe that the domestic producers have to pay the prices for their raw materials up-front, as from 15 June 2000, oil companies, have withdrawn all the credits and discounts. The domestic producers also could not build up sufficient stocks of cumene for the above reasons, which could have helped them in producing more Phenol. This has also resulted in increased working capital requirements for the domestic producers and they are also not able to get additional working capital limits sanctioned by the banks, as a consequence of low profitability, poor financial performance and the possibility of cessation of safeguard duty on imports of Phenol due to expire on 29.06.01 unless extended by the Government.

It is also observed that the domestic producers have not fared well on the share price front, as their share prices have been falling. They have also suffered loss of employment between March 1999 to November 2000, their combined manpower reducing from 1168 as on 31.03.1999 to 1110 on 30.11.2000.

The current status of domestic producers thus indicates that they face a continued threat of serious injury from imports of Phenol and imposition of safeguard duty beyond June 2001 is necessary to prevent serious injury that may be caused to them on withdrawal of the safeguard duty.

Positive adjustment by the domestic industry

The domestic producers had planned to upgrade technology and debottleneck their operations so as to increase their production capacities. In this regard it is observed that the domestic producers have taken steps enumerated by them in their initial application for improving their efficiencies.

As a result of the efforts made by them, the production capacity of HOCL has increased to 49000 MT pa and that of HCL to 34000 MT pa. Taken together their production capacity has increased from 75000 MT pa in 1998-99 to 83000 MT pa in 2000-2001 i.e. an increase of over 10%.

Some of the parties have expressed doubts about enhancement of production capacity, particularly of HOCL. It was stated by HOCL that for any re-rating and enhanced capacity to be certified, consistent production at that capacity level has to be established for the approval by the HOCL Board. On verification, however, the production capacities of HOCL and HCL have been found to be 49000 MT and 34000 MT pa respectively. HOCL had a production capacity of 40000 MT pa on a 330 days yearly operation basis. Its capacity was expanded to 49000 MT pa of Phenol after modifications in the year 1999-2000. The process air system of the oxidation section of the unit was augmented to achieve this expansion. Further trial runs to increase the

throughput of the unit to 55000 MT pa were conducted in November-December 2000 which have given encouraging results.

It has also been verified that HCL have achieved cost reduction benefits from implementation of two stage cleavage Technology which enabled them to reduce the acidity in cleavage reaction, reducing in turn formation of by-products and increasing overall yield. They have also implemented cost reduction schemes for steam and power, achieving better consumption ratio and also achieved reduction in fixed costs as a result of increase in Phenol capacity.

Similarly, HOCL on the technology up-gradation front have made progress in installation of coalescer and new Acid Injection system. With the additional filtration and Benzene Vapour Recovering System additional 12000 TPA of cumene can be produced to meet with the increased Phenol capacity of 49000 TPA. These have also resulted in the stipulated cost savings.

The domestic industry have stated that despite the levy of safeguard duty the Phenol operations were not remunerative during the year 1999-2000 due to certain additional unforeseen circumstances which adversely affected financing of their Cost Reduction Schemes due to shortage of fund accruals. However, due to their commitment to reduce cost and be competitive, they managed to implement the Adjustment Plan Schemes.

With regard to further efforts to bring down their cost of production and the time period required to achieve them substantially, HOCL have stated that they will be upgrading their operating control systems and improve operating efficiencies which is expected to result in a cost saving of Rs.(Confidential) PMT of Phenol and to be implemented within one and half years. Further they have stated that they will expand their capacity and upgrade their equipments for efficiency improvement which will result in a cost saving of Rs.(Confidential) PMT of Phenol and may take a period of two years for its implementation. Similarly HCL have stated that they will be able to achieve a cost saving of Rs.(Confidential) PMT of Phenol on account of de-bottlenecking and installation of equipments to reduce maintenance downtime within a period of one year; achieve a cost saving of Rs.(Confidential) PMT of Phenol by augmentation and revamping within a period of one and half years and a cost saving of Rs.(Confidential) PMT of Phenol by improving energy efficiency and modernisation of intermediate plant within a period of two years. It is thus observed that the domestic producers require a further period of two years to substantially implement their further restructuring plans that will result in enhanced production capacities and reduction in the cost of manufacture of Phenol.

Public Interest

Some of the parties have argued that continued imposition of safeguard duty on imports of Phenol would not serve any public interest. On the contrary

imposition of safeguard duty would severely prejudice the public interest as a number of end user industry may close down. In this regard, it is observed that the expression 'public interest' does not cover in its ambit consumer interest alone. It is a much wider term, which covers in its ambit the general social welfare taking into account the larger community interest. While the imposition of safeguard duty may result in increased cost of imported Phenol in the hand of buyers and therefore, it may also effect the end products manufactured therefrom, it is important to keep in mind the objective of imposition of safeguard duty. The purpose of imposition of safeguard duty is to provide time to the domestic industry to make positive adjustment to meet with the new situation of competition offered by the increased imports. The imposition of safeguard duty, for the period and to the extent just adequate, would, therefore, not only minimise the adverse effect, if any, for the customers but also w them a wider choice to source their requirements, and at competitive prices. The domestic producers who have set up plants with huge public investments provide employment to a large number of people and make valuable contribution to the national economy. Imposition of safeguard duty that may enable the domestic producers to survive in the face of competition offered by the increased imports, will, therefore, also be in the long-term interest of the buyers of Phenol as well as of the buyers of products manufactured therefrom. It is, therefore, considered that the continued imposition of safeguard duty on Phenol for a further period of two years will be in public interest.

It has also been submitted that imposition of safeguard duty will adversely affect country's exports, as imported Phenol used in export production will become costlier. In this regard, it is observed that in international trade exports are net of duties and taxes i.e. all duties and taxes including safeguard duty paid on inputs used in the manufacture of export production are entitled to be refunded as duty drawback etc. Duties and taxes including safeguard duty paid on imported Phenol used in export production would also, therefore, be entitled to be refunded. The objective of safeguard duty is to enable the domestic producers to become internationally competitive. If, therefore, the domestically produced Phenol is not internationally competitive for use in export production, imposition of safeguard duty should help it in becoming internationally competitive, which should be in the long-term interest of the exporters. As far as duty free imports of Phenol under various schemes for use in export production are concerned, the same principle as discussed above applies i.e. either such imports may not be subjected to levy of safeguard duty *ab initio* or if safeguard duty is collected, it should be entitled to be refunded on export of final product, in accordance with the existing laws. It is, therefore, observed that continued imposition of safeguard duty on Phenol is neither likely to affect adversely the export production, nor is it against the Public interest.

Share of countries in exports to India

On the basis of information in regard to imports of Phenol into India during the period 1998-99, 1999-2000 and 2000-01 it is observed that the

following countries exported Phenol to India during the said period. The data for the period 1998-99 and 1999-2000 have been taken from DGCIS Calcutta and for the period 2000-01 is based on the duly verified data furnished by the applicants. Accordingly their share in India's import during the said period is as under:

Imports in MT						
Country/territory	1998-99		1999-2000		2000-01	
	Quantity	%age share	Quantity	%age share	Quantity	%age share
China PR	7 000	0.03	117.667	0.40	-	-
European Community	85.735	0.34	16493.150	56.29	7348.301	27.79
Israel	-	-	20.500	0.07	-	-
Japan	5911.450	23.45	849.716	2.90	1014.139	0.16
Korea RP	9762.106	38.72	16.000	0.05	-	-
Mexico	-	-	100.000	0.34	-	-
Russia	36.000	0.14	895.046	3.05	-	-
South Africa	8522.457	33.80	2165.344	7.40	374.000	1.41
Singapore	16.000	0.06	72.600	0.25	41.400	0.16
Switzerland	0.100	-	28.000	0.09	-	-
Saudi Arabia	-	-	108.000	0.37	-	-
Taiwan	809.505	3.21	231.850	0.79	3550.420	13.43
USA	62.645	0.25	8204.216	28.00	14114.732	53.38
Total	25212.999	100	29302.089	100	26442.992	100

Conclusion and Recommendation

(1) In view of the findings above, the domestic producers of Phenol are facing a continued threat of serious injury from imports of Phenol and they are evidently making positive adjustment to the competition offered by the imports of Phenol. They require a further period of two years to substantially complete their further restructuring plan and continued imposition of safeguard duty for a further period of two years would be in public interest. Further, keeping in view the supply and demand gap of Phenol, it will also be in public interest to exempt from payment of safeguard duty, imports (excluding the quantity of Phenol imported for use in export production) of 12000 MTs of Phenol during the First year and 12500 MTs of Phenol during the Second year of the extended period of imposition of safeguard duty on Phenol.

(2) In arriving at the amount of safeguard duty that would be adequate to prevent serious injury to the domestic industry and to facilitate positive adjustment, weighted average cost of production for HOCL and HCL has been taken into account for the period 2000-01 (upto November 2000). The domestic producers have claimed a certain amount of profit on the basis of expected return on capital employed etc. which is considered to be on the higher side and, therefore, a lower amount of profit (confidential) based on the weighted average cost of production has been considered appropriate and allowed. Similarly, the CIF import prices of Phenol also have been considered on weighted average basis for the period 2000-01 (upto November 2000).

Adjustments have been made in the CIF import price for credit terms. Change in the applicable rate of customs duty has been taken into account in working out the landed price of imported Phenol.

(3) Some of the interested parties have stated that since the liberalisation between the first and second year was to the extent of 7%, the rate of liberalisation for the third year has to be either 7% or more. Consequently, the Safeguard Duty, even if recommended for the third year has to be 8% or lower. In this regard it is observed that liberalisation need not be uniform and needs to be in accordance with the requirement of particular set of circumstances keeping in view, inter alia, the restructuring/adjustment plan of the domestic producers and factors which have a reasonable bearing in order to facilitate positive adjustment by the domestic industry and the quantum of safeguard duty imposed being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the serious injury threatened to be caused by the increased imports of Phenol.

(4) Considering the need to progressively liberalise the safeguard duty in order to facilitate positive adjustment by the domestic industry, it is recommended that safeguard duty be imposed on imports of Phenol into India at the rates specified below on ad-valorem basis for a further period of two years being the minimum necessary for the protection of the domestic industry from the continued threat of serious injury by the imports of Phenol as under:

Period	Level of total protection recommended%	Existing protection %	Safeguard duty recommended % (3)-(2)
(1)	(2)	(3)	(4)
First year of extended period	25+12	25	12
Second year of extended period	25+9		9

And a quantity of 12000 MTs and 12500 MTs of Phenol during the First year of the extended period and Second year of the extended period respectively (excluding the quantity of Phenol imported for use in export production) be exempted from payment of whole of the safeguard duty.

[F. No. SG/INV/2/98(REV)]

R. K. GUPTA, Director General (Safeguards)

